• फ्रीहैंड सरकार नहीं चला पाएंगे शिवराज? • 4500 करोड़ स्वाहा कर जागी सरकार

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

ये दोस्ती टूट गई!

वर्ष 18, अंक-15

1 से 15 मई 2020

मूल्य 25 रूपये

R.N.I. No.HIN/2002/8718 M.P. BPL/642/ 2018-20

चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा भारत?

- कोविड-19 के बाद बदल जाएगी दुनिया की सूरत
- भारत बन सकता है विश्व की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु
- सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती
- लॉकडाउन की वजह से हर चौथा व्यक्ति बेरोजगार
- स्वदेशी को बढ़ाने की जरूरत
- केवल वादों और नारों से नहीं बनेगी बात
- भारत को विश्वगुरु बनाने का बेहतर मौका
- प्रकृति के महत्व को समझने का अवसर
- भारत को मुक्त व्यवस्था से निकलना होगा बाहर
- स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना जरूरी
- चीन पर अत्यधिक निर्भरता को करना होगा बाय-बाय
- स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारों को बजट बढ़ाना होगा
- ईमानदारी से गरीबी को मिटाना होगा
- अगर 100 साल बाद कोई महामारी आती है तो उससे निपटने का प्लान बनाना होगा

आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन करें...

- गर्म पानी, काढ़ा का निरंतर सेवन करें।
- शाम के समय नाक के दोनों छेदों में तिल या नारियल का तेल लगाएं।
- खाने में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन जैसे मसालों का इस्तेमाल करें।
- रोजाना कम से कम 30 मिनट तक योगासन, प्रणायाम और मेडिटेशन करें।
- तुलसी, दालचीनी, कालीमिर्च, सुनथी और मनक्के से बने काढ़े को दिन में एक से दो बार पीएं।

राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका

अक्स

कोरोना के इस संक्रमण काल में भी
आपके साथ, आपके लिए

राज्य सरकारों द्वारा बताए अनुसार लॉकडाउन/दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य करें

इस अंक में

राजपाट

9 | चार दिन की चांदनी

चला-चली की बेला में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुखिया कमलनाथ ने अपने चहेते नेताओं को निगम-मंडलों और आयोगों में ताबड़तोड़ कुर्सी बांट दी, लेकिन सत्ता बदलते ही भाजपा ने इन सबकी विदाई कर दी...

राजपथ

10-11 | बागी होंगे स्वीकार

कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए सिंधिया समर्थक 22 पूर्व विधायकों को अब उपचुनाव की चिंता सताने लगी है। ये नेता भलीभांति जानते हैं कि उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस विभीषण के तौर पर प्रचारित करेगी...

लालफीताशाही

15 | भरे गोदाम, भूखा इंसान

कोरोना काल के इस महासंकट को यूएन की तसदीक की कोई जरूरत नहीं थी। यह हमारे चारों ओर दिख रहा है और साफ दिख रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर झारखंड के सुदूर गांवों तक, करोड़ों लोगों के सामने भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं...

मप्र कांग्रेस

16 | उपचुनाव की रिहर्सल

मप्र की सत्ता भले ही कमलनाथ के हाथों से खिसक गई हो, लेकिन उन्होंने अभी हार नहीं मानी है। दोबारा मध्यप्रदेश की सत्ता में कैसे काबिज हों, इस जुगत में वे जुट गए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रदेश की जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से ज्यादा सीटें जीतने के लिए अभी...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

चीन ने कोरोना महामारी का ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि उसने लोगों की सेहत के साथ-साथ देश-दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर डाला है। लेकिन भारत को एक अवसर भी मिला है कि वह अपनी श्रमशक्ति के बल पर विश्व की अर्थव्यवस्था का मजबूत केंद्र बन सके। साथ ही भारत को यह भी तैयारी करनी होगी कि अगर 100 साल बाद फिर से कोई ऐसी महामारी फैलती है तो उससे आसानी से निपटा जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारों को बजट बढ़ाना होगा।

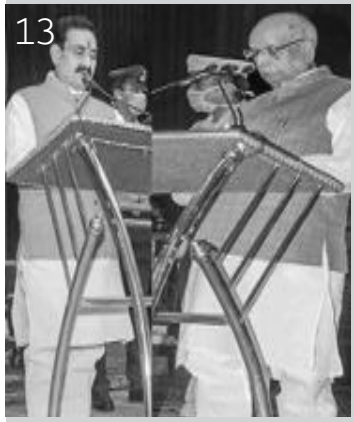

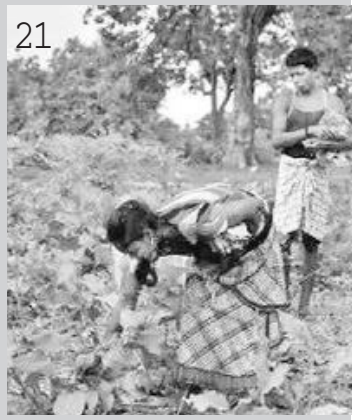

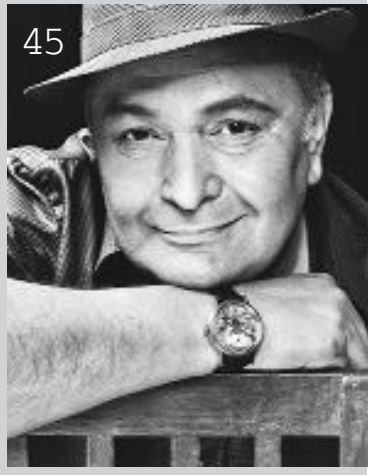

राजनीति

30-31 | कुछ तो बात जरूर है

कांग्रेस में सोनिया गांधी की मंजूरी से राहुल गांधी की अगुवाई में एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई है। राहुल गांधी की अगुवाई इसलिए भी क्योंकि लिस्ट में सबसे ऊपर उनका ही नाम नजर आ रहा है। वैसे तकनीकी तौर पर राहुल गांधी का नाम मनमोहन सिंह के ठीक बाद है, हालांकि वो कमेटी...

महाराष्ट्र

35 | राज्यपाल भरोसे उद्धव

कोरोना संक्रमण के संकट से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र से आ रही राजनीतिक खबरें वहां एक बार फिर राजनीतिक संकट खड़ा होने का संकेत दे रही हैं। पिछले सप्ताह राज्य मंत्रिमंडल ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सूबे के राज्यपाल से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्य...

बिहार

38 | मन के घाव

कोरोना संकट काल में बिहार सरकार कैसा काम कर रही है? क्या वह जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है? क्या वह आम लोगों की भावनाओं का सही आंकलन कर पा रही है? क्या वह इस स्थिति में है कि बिहार की जनता एक बार फिर...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

यहां तो इलाज में भी वीआईपी कल्चर...

कवि अदम गोंडवी की ये पंक्तियां तो आपने सुनी ही होंगी...

तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है।
उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर परदे के पीछे बर्बरीयत है, नवाबी है।।

कुछ ऐसे ही हालात इन दिनों मप्र में देखने को मिल रहे हैं। भारत समेत पूरी दुनिया अभी कोरोनावायरस महामारी से जूझ रही है। इस बीमारी ने पूरी दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जाहिर है, अन्धविश्वास पर यकीन रखने वाले देश भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था और अचानक आने वाली महामारी से बचने और इसके लिए की जा रही तैयारियों की भी पोलपट्टी खुल गई है। भारत हमेशा से अपनी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाता रहा है। लेकिन इस बीमारी ने सबकी आंखें खोल दी हैं। इस महामारी के संक्रमण की जकड़ में जो आ रहा है उसका इलाज सरकारी खर्चे पर कराया जा रहा है। लेकिन अजब और गजब वाले मप्र में तो इलाज में भी भेदभाव नजर आ रहा है। यानि एक ही संक्रमण से ग्रस्ति किसी व्यक्ति का सरकारी अस्पताल में तो किसी का सर्वसुविधायुक्त हाईफाई अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। मप्र की राजधानी भोपाल में कोरोना का इलाज एम्स सहित कुछ निजी अस्पतालों में भी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह ओहदे के हिसाब से अस्पतालों में मरीजों को जगह दी जा रही है उससे इलाज में भी वीआईपी कल्चर नजर आ रहा है। देखने में यह आ रहा है कि इस बीमारी की चपेट में आने वाले आम लोगों, कर्मचारियों और अधिकारियों को या तो एम्स या फिर शहर से दूर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। ऐसा नहीं कि इन अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है। इन अस्पतालों से कोरोना का इलाज कराकर कई मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि कुछ वीआईपी मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें शहर के बीचोंबीच स्थिति एक हाईफाई अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इस अस्पताल में केवल वही लोग भर्ती हो रहे हैं जिन्हें नौकरशाही का दर्जा मिला है। वह भी केवल वे जो डायरेक्ट आईएएस बने हैं। इस अस्पताल में प्रमोटी नौकरशाह को भी जगह नहीं दी जा रही है। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि इस अस्पताल के साथ सरकार का कोई इलाज संबंधी समझौता भी नहीं हुआ है। फिर भी नौकरशाहों को यहां इलाज के लिए भर्ती किया जा रहा है। दरअसल, हमारी व्यवस्था में नौकरशाही अपने आपको अन्य लोगों से अलग मानती है। इसलिए वह हमेशा इस कोशिश में रहती है कि उसे अन्य लोगों से अलग समझा जाए। जिस निजी अस्पताल में कोरोना पीड़ित नौकरशाहों का इलाज हो रहा है वह बेहद महंगा है। दरअसल, हमारी नौकरशाही सरकारी खर्चे पर महंगी चीजों की भुगतभोगी हो गई है। जनता से लिए गए टैक्स पर वीआईपी कल्चर में रहने वाले ये लोग संक्रमणकाल में भी अपना स्वभाव नहीं बदलने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो इस वीआईपी कल्चर के कारण ही मप्र में कोरोना का संक्रमण इतना विकराल रूप ले चुका है। कोरोना के डर से हुए लॉकडाउन ने सरकार के भेदभाव वाली मंशा से भी पर्दा हटा दिया है। एक तरफ अलग-अलग जगहों में फंसे अमीरों को तो सरकार हवाई जहाज से लेकर आई। वहीं बड़े महानगरों में मजदूरी करने गए गरीबों के साथ-साथ सरकार ने जो व्यवहार किया, उसे पूरी दुनिया ने देखा। लोग सड़कों पर अपने बच्चों, परिवार और जरूरी सामान के साथ देश की सड़कों पर निकल पड़े हैं। यह भेदभाव आखिर कब खत्म होगा?

-राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 18, अंक 15, 1 से 15 मई, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2015-17

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:**- इंद्रकुमार, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-
फोन : 011 25495021, 011 25494676
मुंबई : बी-1, 41 शिव पावर्ती चेम्बर प्लाट नंबर 106-110 सेक्टर-21 नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411
कोलकाता : 70/2 हजरा रोड कोलकाता
फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिंलटर निपानिया, इंदौर
मोबाइल - 094251 25096

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

aksnews.com

पुलिस के जज्बे को सलाम

कोरोना के इस संकट में पुलिस अपना कर्त्तव्य बखूबी निभा रही है। इस संकट की घड़ी में पुलिस रात-दिन सड़कों पर खड़ी रहती है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। अब तो उन्हें घर भी जाने को नहीं मिलता। प्रदेश सहित देशभर की पुलिस के इस जज्बे को सलाम है।

● **रंजन रघुवंशी,** इंदौर (म.प्र.)

मजदूरों को होगी परेशानी

कोरोना वायरस के कारण सभी उद्योग ठप पड़े हैं। इस कारण अधिकांश मजदूर भी अपने घरों के लिए पलायन कर चुके हैं। इस महामारी के कारण प्रदेश को आर्थिक क्षति पहुंचेगी। हजारों मजदूरों को अपना परिवार चलाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

● **सुरेश मीना,** भोपाल (म.प्र.)

महिलाएं न हों प्रताड़ित

देशभर में लॉकडाउन की वजह से सभी घरों में कैद हैं। ऐसे में कई जगहों पर महिलाओं को घर में प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके लिए राज्य व केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। ताकि महिलाओं को किसी भी तरह की प्रताड़ना का शिकार न होना पड़े।

● **रहिम सिंह,** ग्वालियर (म.प्र.)

कोरोना को लेकर सरकार कर रही अच्छे प्रयास

पूरा देश इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार सहित सभी राज्यों की सरकारें अपने-अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। केरल, दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारों द्वारा इस महामारी को रोकने के लिए कई अच्छे कदम उठाए गए हैं। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी इस संकट से निपटने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। इस संकट से बचने के लिए लोगों को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। कोरोना की जंग अभी और लंबी है। जब जनता सरकार का साथ देगी तभी जाकर जनता और सरकार दोनों मिलकर इस महामारी से निपट सकेंगे।

● **कौशल सोनी,** रायसेन (म.प्र.)

पानी की कीमत को समझना होगा

देश के हर व्यक्ति को स्वच्छ पीने का पानी मिल सके इसके लिए सरकार की योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचना जरूरी है। हमें पानी की कीमत को समझना होगा। आज देश में 60 करोड़ आबादी भीषण जल संकट का सामना कर रही है। प्रदूषित पानी के इस्तेमाल से देश में हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। आज अगर हमने पानी को बचाने का प्रयास नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें पानी के लिए भटकना पड़े। इसलिए हमें पानी की अहमियत समझनी होगी।

● **राजू मकोडिया,** सीहोर (म.प्र.)

बेहतर हों सरकारी स्कूल

कई प्रदेशों में आज सरकारी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जिलों में कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनसे अन्य प्रदेशों को सीखना चाहिए। सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर हो इसके लिए सरकार को और अधिक काम करना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा मिल सके, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे इसके लिए सरकार को सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर बनानी ही चाहिए।

● **पूजा सिंह,** जबलपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

दो नाव की सवारी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पांच साल पहले लालू प्रसाद के साथ मिलकर अगड़ा-पिछड़ा की राजनीति की थी। राजद और जदयू गठबंधन ने भाजपा के ज्यादा बड़े और ज्यादा इंद्रधनुषी गठबंधन को हरा दिया। पर डेढ़ साल के बाद ही नीतीश ने राजद का साथ छोड़ दिया और वापस भाजपा से नाता जोड़ लिया। पांच साल के बाद अब वे अगड़ा-पिछड़ा के पुराने फॉर्मूले को नहीं दोहरा सकते हैं तो कोरोना काल में अमीर और गरीब का दांव चल रहे हैं। हालांकि इसकी सफलता बहुत संदिग्ध है। इसके बावजूद नीतीश इसे आजमा रहे हैं। उन्होंने इसी राजनीति के तहत कोटा में पढ़ने गए बिहार के बच्चों को लाने से मना किया है। नीतीश ने न सिर्फ इससे इनकार किया, बल्कि सार्वजनिक रूप से कहा कि वो सब संपन्न परिवार के बच्चे हैं और वहां उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अपने इस बयान से उन्होंने यह मैसेज दिया कि वे गरीबों के नए मसीहा हैं, जैसे पहले लालू प्रसाद होते थे। हालांकि मुश्किल यह है कि उनका यह दांव इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वे गरीब प्रवासी मजदूरों को भी बिहार नहीं आने दे रहे हैं। अगर वे मजदूरों को आने देते और कोटा के छात्रों को रोकते तब उनकी राजनीति चलती। पर वे दो नावों पर सवारी कर रहे हैं, जिसका उनको अगले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

हैरान करने वाली सलाहकारों की टीम

वैसे तो सोनिया गांधी जबसे सक्रिय राजनीति में आई हैं उनके एक ही सलाहकार रहे हैं- अहमद पटेल। पर कोरोना वायरस मौजूदा संकट के समय में पार्टी अध्यक्ष ने सलाहकारों की एक टीम बनाई है। यह टीम कांग्रेस अध्यक्ष को मौजूदा समय के मुद्दों पर सलाह देगी और पार्टी की राय बनवाने में मदद करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मनमोहन सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है क्योंकि इस तरह के मुद्दों पर आज भी देश में उनसे बेहतर समझ रखने वाला शायद ही कोई सार्वजनिक व्यक्ति होगा। पर हैरानी की बात यह है कि इसमें कई ऐसे नाम नहीं हैं, जो कांग्रेस की राय बनवाने में अहम स्थान रखते थे। जैसे इस सूची में एके एंटनी, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा आदि के नाम नदारद हैं। बहरहाल, इस समिति में शामिल चौंकाने वाले तीन नाम बिल्कुल नए लोगों के हैं। इसमें डाटा विभाग संभालने वाले प्रवीण चक्रवर्ती, पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ और हाल ही में सोशल मीडिया टीम के प्रमुख बनाए गए गुजरात से आने वाले रोहन गुप्ता का है। क्या यह कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के बदलते डायनेमिक्स का कोई संकेत है? पुराने नेताओं के साथ-साथ कई नए नेता भी इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं।

जैसे को तैसा वाली एप्रोच

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन किया और उनसे राज्य के बुलंदशहर जिले में दो साधुओं की हत्या के मामले में बात की। उद्धव ने मुख्यमंत्री से कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि बुलंदशहर में एक मंदिर के दो साधुओं की हत्या हुई है और बताया जा रहा है कि मुरारी नाम का एक व्यक्ति नशे में था और उसने इन साधुओं की लाठी से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसकी गहराई से जांच चाहते हैं। असल में कुछ दिन पहले जब महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की हत्या हुई थी तो योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे को फोन किया था और इसे गंभीर मामला बताते हुए जांच और कार्रवाई करने को कहा था। उस मामले में राज्य की पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और उसे लेकर हो रहे सांप्रदायिक प्रचार को खत्म करने के लिए सभी आरोपियों के नाम भी जारी किए थे। उसी का बदला चुकाने के लिए उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को फोन किया। उस समय केंद्रीय गृह मंत्री ने भी उद्धव से इस बारे में बात की थी।

सरकार पर तंज

अधिकारी सेवा शर्तों के साथ बंधे होते हैं इसलिए बेचारे खुलकर तो नहीं कह सकते हैं पर छद्म रूप से सोशल मीडिया में उन्होंने सरकार को जमकर निशाना बनाया है। अधिकारियों और केंद्रीय कर्मचारियों ने या उनकी ओर से उनके शुभचिंतकों ने या विपक्षी पार्टियों ने यह मजाक बनाया है कि जो निजी कंपनियों और आम लोगों से अपील कर रहे थे कि वे अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं काटें और छुट्टी के समय का भी पूरा वेतन उनको दें, उन्होंने खुद ही अपने कर्मचारियों का पैसा काटना शुरू कर दिया। सिर्फ वेतन ही नहीं काटा है, बल्कि महंगाई भत्ता भी रोक दिया है और कई राज्यों में तो एलटीसी भी रोकी जा रही है। ध्यान रहे कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए जब लॉकडाउन लागू हुआ तो प्रधानमंत्री सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लोगों से कहा कि वे अपने यहां काम करने वालों को लॉकडाउन की अवधि का भी पैसा दें। लेकिन खुद सरकारों ने अपने कर्मचारियों का पैसा काटना शुरू कर दिया। ऐसे में अब सरकारों पर तंज कसा जा रहा है।

राहुल पर फिर बना फोकस

कांग्रेस पार्टी में संगठन के चुनाव होने हैं। संगठन में बदलाव भी होना है। यह फैसला किया जाना है कि सोनिया गांधी कब तक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगी। इस बारे में भी विचार होना है कि उन्हें ही पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जाएगा या उनकी जगह नया अध्यक्ष बनेगा, नए अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल का होगा या पार्टी संविधान में बदलाव करके वापस तीन साल का कार्यकाल बहाल किया जाएगा। कई राज्यों में संगठन के अंदर बदलाव किया जाना है। पर कोरोना वायरस की वजह से यह सब कुछ अटक गया है। कोरोना का मामला शुरू होने के बाद राहुल गांधी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाने की बातें भी स्थगित कर दी गई थीं। पर अब फिर से राहुल गांधी पर फोकस है। कांग्रेस के नेता राहुल के प्रचार और उनके गुणगान में जुटे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर फिर से राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाना है तो उन्हें पहले क्यों हटाया गया था। लेकिन यह सवाल आलाकमान से कौन पूछे?

साहब के पिंजरे से निकल गई मैना

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक नई नवेली पुलिस अधिकारी की पीड़ा चर्चा में है। प्रशासनिक अधिकारियों ने इस नई नवेली पुलिस अधिकारी को मैना नाम दिया है। दरअसल, उक्त डीएसपी स्तर की महिला पुलिस अधिकारी की पदस्थापना डकैतों के लिए कुख्यात रहे अंचल में हुई थी। वहां उन पर विभाग के बड़े साहब की नजर पड़ गई। फिर क्या था साहब ने कायदे-कानूनों की आड़ में मैडम को इस कदर फांस लिया कि वे पिंजरे में कैद मैना की तरह तड़पने लगीं। बताया जाता है कि साहब से परेशान होकर मैडम ने उनके चंगुल से निकलने के बहुत प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाईं। इसके बाद उन्होंने अपने पैरेंट्स को सारी हकीकत बताई। बताया जाता है कि पुलिस अधिकारी बेटी की पीड़ा को सुनकर माता-पिता आनन-फानन में बेटी के पास पहुंच गए। फिर उन्होंने इस मामले में ऊपर से लेकर नीचे तक हस्तक्षेप किया। माता-पिता के हस्तक्षेप के बाद मैना साहब के पिंजरे से निकलने में कामयाब रहीं। सूत्र बताते हैं कि अब ये मैडम मालवा-निमाड़ क्षेत्र के एक आदिवासी जिले में पदस्थ हुई हैं। वे वहां राहत की सांस ले रही हैं। उधर, सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में ऐसी कई मैना हैं जो या तो साहब के पिंजरे में कैद हैं या फिर उन्होंने खुद साहब को अपने पिंजरे में कैद कर रखा है।

जेल में कैद होने जैसा अहसास

कोरोना वायरस के संक्रमण ने कई क्षेत्रों को जेल सा बना दिया है। आलम यह है कि जिस क्षेत्र में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलता है उसे इस तरह पैक कर दिया जाता है कि लोग उसको देखकर ही अपने आपको अस्वस्थ महसूस करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों प्रदेश के नौकरशाहों को भी महसूस हो रहा है। दरअसल, नौकरशाहों के सबसे बड़े रहवासी क्षेत्र में एक संक्रमित अधिकारी के मिलने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया बना दिया गया है। इस कारण अफसरों को बाहर आने जाने में परेशानी हो रही है। आलम यह है कि अब तो अफसर सरकार को कोसने लगे हैं कि उसका यह कैसा नियम है कि एक संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद उस क्षेत्र की इस तरह नाकेबंदी कर दी जा रही है कि लोगों को घुटन महसूस हो रही है। लेकिन इन साहेबान को यह कौन बताए कि ऐसी ही घुटन अन्य क्षेत्रों में आमजन भी महसूस कर रहे हैं। अफसरों को तो कई तरह की छूट है, उनके पास सभी सामान और सुविधाएं आसानी से पहुंच रही हैं। जबकि आमजन एक कैदी की तरह रह रहे हैं। दरअसल कंटेनमेंट एरिया में रह रहे इन अफसरों को इस बात का अहसास हो रहा है कि पाबंदी का असर क्या होता है।

रिश्तेदार भी हो गए वीआईपी

सत्ता का अपना रसूख होता है। जिसके पास सत्ता आ जाती है उसके लिए कायदे-कानून कोई मायने नहीं रखता है। ऐसा ही दृश्य विगत दिनों देखने को मिला। दरअसल, 12 साल बाद फिर से मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होने के बाद एक नेताजी इतने आतुर हो गए कि उन्होंने लॉकडाउन के बाद भी सारी बंदिशों को तोड़कर अपने नाते-रिश्तेदारों को मंत्रालय घुमा डाला। जबकि प्रदेश में उस समय लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना पूरी तरह वर्जित था, लेकिन मंत्री का रुतबा पाते ही माननीय ने पूरे नाते-रिश्तेदारों को एक ही गाड़ी में भरकर मंत्रालय घूमने भेज दिया। उस समय मंत्रालय में अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही आमजन का भी प्रवेश वर्जित था। लेकिन मंत्रीजी के परिजनों पर यह नियम लागू नहीं हो सका। मंत्रालयीन सूत्रों का कहना है कि विशेष निर्देश पर मंत्रीजी के नाते-रिश्तेदारों को मंत्रालय दर्शन कराया गया। सवाल यह उठता है कि जब कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा था तो मंत्रीजी के नाते-रिश्तेदारों को किस हैसियत से मंत्रालय घुमाने की परमिशन दी गई। हद तो यह देखिए कि दूसरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का पाठ पढ़ाने वाले मंत्रीजी ने एक ही इनोवा गाड़ी में कई लोगों को भरकर मंत्रालय घुमाने भेजा था। दरअसल, सैय्या भए कोतवाल, अब डर काहेका... वाली व्यवस्था जो अपने देश में है।

एकसाथ कट रही रात

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों दो अधिकारियों की रात की खुशी अन्य अधिकारियों की नींद हराम किए हुए है। दो अलग-अलग जिलों में पदस्थ ये दो पुलिस अधिकारी जब रात को एक ही जगह मिलते हैं तो अन्य अधिकारी चटखारे लेकर इनकी चर्चाएं करते हैं। दरअसल, मालवा क्षेत्र के दो पड़ोसी जिलों में पदस्थ इन अधिकारियों की रात एक ही जगह गुजरती है। ऐसा नहीं है कि ये अधिकारी हमनिवाला-हमप्याला हैं। बल्कि दोनों विपरीत लिंग के हैं। ऐसे में इनका रात को एक ही जगह मिलना और रात गुजारना चर्चा में तो रहेगा ही। यही कारण है कि दिनभर अपने-अपने जिले में अपने-अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने के बाद जब ये अधिकारी एक ही जगह रात गुजारने पहुंचते हैं तो इसकी चर्चा राजधानी में स्थित मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों से लेकर उन जिलों की प्रशासनिक वीथिका में भी होने लगती है। आलम यह है कि कई वरिष्ठ अधिकारियों ने तो इनके मिलन की गाथा सुनाने के लिए अपने कुछ लोग भी इनके पीछे लगा दिए हैं। ये लोग नमक-मिर्च मिलाकर इनके मिलन की गाथा सुनाकर वाहवाही लूट रहे हैं।

सेल्समैन बन गए साहब

नौकरशाहों को सरकार मोटी-मोटी पगार देती है। इसके बावजूद कई नौकरशाह लक्ष्मी कमाने के लिए इस कदर बेचैन रहते हैं कि वे कुछ भी करने पर उतर जाते हैं। इन दिनों एक विभाग के साहब ऐसा ही कुछ करने में व्यस्त हैं। दरअसल, कोराना वायरस के इस संक्रमणकाल में कोरोना के इलाज के लिए सरकार कई तरह की खरीदारी कर रही है। इस खरीदारी में कई अफसर कमीशन कमाने में जुट गए हैं। ऐसे ही एक अफसर जो पूर्व में राजधानी भोपाल के कलेक्टर भी रहे हैं इन दिनों कोविड-19 के टेस्ट मशीन की सप्लाई के खेल में जुटे हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि स्वास्थ्य से जुड़े महकमे में जिम्मेदारी वाले पद पर पदस्थ ये साहब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 टेस्ट मशीन की सप्लाई करवा रहे हैं। बताया जाता है कि साहब खुद आगे बढ़कर कंपनियों के लिए लाइजिनिंग कर रहे हैं और साहब के कहने पर तीन-चार मशीनें सप्लाई भी कर दी गई हैं। साहब की इस कार्यप्रणाली को देखकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उनको ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यह कमीशन का खेल है या कुछ और... ?

अगर सरकार सोचती है कि गरीबों के खाते में महज 500 रुपए डालकर या उन्हें मुट्ठीभर दाल-चावल का लालच देकर बहला लेगी तो यह गलत है। देश में जो स्थिति दिख रही है, उससे लगता है कि कोरोना से कोई मरे न मरे लेकिन भूख से करोड़ों लोग मर जाएंगे।

● **तेजस्वी यादव**

आखिर ये सब किसके लिए है? लोग इस बात का जवाब दें जो सरकार की बात नहीं सुन रहे। जो आपकी सेवा कर रहे हैं, उन पर आपने पत्थर बरसा दिए। चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। दुआ करो कि वो नौबत न आए कि आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। इसलिए मौके की नजाकत को समझें और सरकार के निर्देश मानें।

● **सलमान खान**

भारतीय टीम में वापसी करना महेंद्र सिंह धोनी के लिए मुश्किल लगता है, क्योंकि लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद लय में आना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए धोनी के सामने भारतीय टीम में वापसी करना चुनौतीपूर्ण है। अब तो आईपीएल पर भी संकट के बादल हैं। ऐसे में धोनी अपने आपको कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि वे वापसी लायक हैं।

● **मोहम्मद अजहरुद्दीन**

यदि कोरोना संकट के लिए चीन जिम्मेदार निकलता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कोरोना वायरस को चीन में शुरू होने से पहले रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज पूरी दुनिया इस संकट से गुजर रही है।

● **डोनाल्ड ट्रम्प**

यह जानकर लोगों को हैरानी होगी कि जब मैंने मिस इंडिया का खिताब जीता था उस समय मेरे पास डिजाइनर ड्रेस के पैसे नहीं थे। हमारे पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि हम डिजाइनर कपड़े पहन सकें, हमें चार डिजाइनर ड्रेस चाहिए थीं। हम मिडिल क्लास के लोग हैं और हमें अपनी पाबंदियां पता थीं। मेरी मां ने कहा था कि क्या हुआ लोग कपड़े देखने थोड़ी आ रहे हैं, तुम्हें देखने आ रहे हैं। उसके बाद हम बाजार से कपड़े खरीदकर लाए। हमारे घर के नीचे एक पेटीकोट सिलने वाला टेलर बैठता था, उसने मेरा विनिंग गाउन तैयार किया। मम्मी ने बचे हुए कपड़े से फूल बनाकर लगाया। वो दिन मेरे लिए बहुत खास हैं।

● **सुष्मिता सेन**

वाक्युद्ध

केंद्र सरकार कोरोना वायरस का मुकाबला लॉकडाउन से करवा रही है। देश में न तो इलाज के पर्याप्त संसाधन हैं और न ही डॉक्टर। ऐसे में कब तक लोग घरों में रहकर कोरोना का मुकाबला करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। अगर सरकार नहीं चेती तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।

● **राहुल गांधी**

इस संकटकाल में भी विपक्ष को राजनीति नजर आ रही है। विश्व की मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों की स्थिति क्या हो रही है, यह पूरा विश्व देख रहा है। जिन देशों की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं वहां भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अगर भारत में समय पर लॉकडाउन नहीं होता तो यहां भी हालात गंभीर होते।

● **अमित शाह**

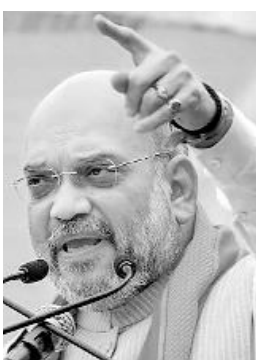

चार दिन की चांदनी

चला-चली की बेला में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुखिया कमलनाथ ने अपने चहेते नेताओं को निगम-मंडलों और आयोगों में ताबड़तोड़ कुर्सी बांट दी, लेकिन सत्ता बदलते ही भाजपा ने इन सबकी विदाई कर दी। चार दिन की चांदनी देखने वाले इन नेताओं की स्थिति ऐसी हो गई है कि ये ठीक से खुशी भी नहीं मना पाए। दरअसल, करीब डेढ़ साल तक कमलनाथ सरकार निगम-मंडलों और आयोगों में अपने नेताओं की नियुक्ति नहीं कर पाई थी। पार्टी में कई बार यह मांग उठती रही कि अधिक से अधिक नेताओं को कुर्सी पर बैठा दिया जाए ताकि गुटबाजी थामी जा सके, लेकिन कमलनाथ ने किसी की एक नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब सत्ता जाने वाली है तो उन्होंने अपने कुछ चहेतों को निगम-मंडलों और आयोगों में कुर्सियों पर बैठा दिया।

आलम यह रहा कि कमलनाथ ने राजनीतिक नियुक्तियों की झड़ी लगा दी। पूर्व सांसद आनंद अहिरवार अनुसूचित जाति आयोग, मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष, आईटी सेल के अभय तिवारी को युवा कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं जेपी धनोपिया को मप्र पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष और गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी को मप्र अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। सागर संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद डॉ. आनंद अहिरवार को राज्य अनुसूचित जाति आयोग में चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जबलपुर के हवाबाग महाविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक डॉ. आलोक चंसोरिया को निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्णकालिक चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया। रामू टेकाम और राशिद साहिल सिद्दीकी मप्र लोक सेवा आयोग के सदस्य बने और महिला आयोग में सदस्यों की नियुक्तियां कर दी गईं। ये सभी संवैधानिक पद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी सरकारी वकीलों को हटाकर नए वकील नियुक्त कर दिए गए। युकां नेता मनोज शुक्ला के पिता व कांग्रेस के सहकारी नेता सुभाष शुक्ला जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रशासक बना दिए गए। इन नेताओं ने भी मौके की नजाकत को देखते हुए ताबड़तोड़ पदभार भी संभाल लिया। लेकिन इनकी खुशी अधिक दिन कायम नहीं रह पाई। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ शासनकाल में की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया। गौरतलब है कि डेढ़ साल तक एक भी नियुक्ति नहीं करने वाले कमलनाथ ने जब अचानक राजनीतिक नियुक्तियां शुरू की थी तो उस पर सवाल उठे थे। कमलनाथ सरकार चला-चली की बेला में जो कर रही थी, इसका इंतजार जनता और कांग्रेस के नेता लंबे समय से कर रहे थे। मंत्रिमंडल विस्तार न हो पाने के कारण विधायकों में असंतोष बढ़ रहा था। राजनीतिक नियुक्तियों में देरी के कारण पार्टी के नेता नाराज थे। लेकिन सरकार सिर्फ गाइडलाइन बनाने में व्यस्त दिख रही थी। यदि सरकार ने पहले इस ओर ध्यान दिया होता तो शायद ये हालात निर्मित न होते। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित पूरी पार्टी को मालूम था कि मंत्रिमंडल विस्तार न होने के कारण समर्थन दे रहे निर्दलीय, सपा, बसपा के विधायकों के सब्र का बांध टूट रहा था। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक खुद को दरकिनार करने के कारण नाराज थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जवाबदारी न दिए जाने के कारण उनके समर्थक मंत्री एवं विधायक लामबंद हो रहे थे। बावजूद इसके सब हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। लेकिन जब सब हाथ से छूटता दिखने लगा तब ताबड़तोड़ नियुक्तियां की गईं।

जिन नेताओं को निगम-मंडलों और आयोगों में पद मिले थे उन्हें भी मालूम था कि अगर सत्ता बदली तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन कुर्सी का लालच ऐसा होता है कि सबकुछ जानते हुए भी लोग उसके मोह में पड़ जाते हैं। पद की घोषणा होते ही नेताओं ने आव देखा न ताव जाकर पदभार संभाल लिया, लेकिन कोई भी उस कुर्सी पर सुकून से बैठता उससे पहले ही उनकी कुर्सी छिन गई। अब ये नेता कुर्सी जाते ही राजनीतिक पटल से भी गायब हो गए हैं।

● **कुमार विनोद**

अकादमियों में की गई नियुक्तियां भी हो गई निरस्त

कमलनाथ सरकार द्वारा निगम-मंडलों, अकादमी, आयोग, परिषदों में की गई राजनीतिक नियुक्तियों को शिवराज सरकार ने निरस्त कर दिया। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। 20 अप्रैल को काम-काज शुरू होते ही मुख्यमंत्री सचिवालय ने राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त करने के आदेश दिए। सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटशीट पहुंचते ही तत्काल आदेश जारी कर दिए। इसी आधार पर संबंधित विभागों ने कमलनाथ सरकार के दौरान हुई राजनीतिक नियुक्तियों के मनोनयन निरस्त कर दिए। इनमें आदिवासी लोककला एवं बोली विकास अकादमी के निर्देशक राजेश प्रसाद मिश्र, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक अखिलेश वर्मा, साहित्य अकादमी भोपाल के निदेशक नवल शुक्ल, सिंधि साहित्य अकादमी के निदेशक नरेश कुमार गिदवानी, मराठी साहित्य अकादमी की निदेशक पूर्णिमा प्रदीप का मनोनय निरस्त करने के आदेश संस्कृति परिषद ने जारी कर दिए। इसी प्रकार स्वराज संस्थान संचालनालय के अंतर्गत स्थापित धर्मपाल शोधपीठ के निदेशक ध्रुव शुक्ला और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक डॉ. प्रकाश माथुर के पद पर किया गया मनोनयन भी निरस्त कर दिया गया है। इनकी नियुक्ति भी कमलनाथ सरकार में की गई थी। साथ ही उर्दू अकादमी के अध्यक्ष अजीज कुरैशी और हिसमउद्दीन फारूखी का सचिव पद पर किया गया मनोनयन भी निरस्त कर दिया गया है। इनकी नियुक्ति वर्ष 2019 में हुई थी।

कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए सिंधिया समर्थक 22 पूर्व विधायकों को अब उपचुनाव की चिंता सताने लगी है। ये नेता भलीभांति जानते हैं कि उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस विभीषण के तौर पर प्रचारित करेगी, वहीं भाजपा नेता भी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अब इन नेताओं ने भाजपा के क्षेत्रीय क्षत्रपों से गलबहियां करना शुरू कर दिया है। इनको उम्मीद है कि इससे भाजपाई कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार कर सकते हैं।

बागी होंगे स्वीकार

उपचुनाव में होगी बगावत

वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं, जब बागी नेता सिंधिया पर चढ़ाई करेंगे। सिंधिया भाजपा नेताओं पर चढाई करेंगे। भाजपा नेता इस चढ़ाई का बदला बागियों को चुनाव में पराजित कराकर लेंगे। 6 माह बाद भाजपा विपक्ष में, बागी घर में और कमलनाथ सरकार में नजर आएंगे। चलो एक पल के लिए मान लें कि सब ठीक हो गया। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय क्षत्रप जैसे ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, जयभान सिंह पवैया, रूस्तम सिंह और नरोत्तम मिश्रा को वीआरएस लेना होगा? अब यहां के सबसे बड़े नेता तो सिंधिया होंगे। इसी तरह सागर क्षेत्र में गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह समेत सभी भाजपा नेताओं के ऊपर गोविंद सिंह राजपूत होंगे। मालवा क्षेत्र में तुलसी सिलावट भाजपा नेताओं के राजनीतिक जीवन को कुचलकर शिखर पर पहुंच जाएंगे? कुल मिलाकर भाजपा ने मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनाई है, बल्कि अपने नेताओं के राजनीतिक अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

मंत्री बनने की चाह में कांग्रेस से बगावत के बाद अपनी विधायकी छोड़ 22 बागी भाजपा में शामिल तो हो गए हैं लेकिन अब उन्हें विधायक बनने की चिंता सताने लगी है। उन्हें यह तो विश्वास है कि भाजपा उपचुनाव में टिकट देगी, लेकिन जीत उनके हाथ लगेगी या नहीं यह भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता के ऊपर है। इसलिए वे अपने कट्टर विरोधी रहे भाजपा नेताओं से नजदीकी बढ़ाने लगे हैं। आलम यह है कि पुराने भेदभाव को मिटाकर बागी नेता बेझिझक भाजपा के कद्दावर नेताओं के घर पहुंच रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा ने कांग्रेस के असंतुष्ट नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा और केंद्रीय मंत्री बनाने के साथ ही मप्र मंत्रिमंडल में एक उपमुख्यमंत्री, 12 कैबिनेट मंत्री और 22 बागियों को भाजपा से विधानसभा टिकट का वादा किया है। लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन ने सारा गणित बिगाड़ दिया है। ऐसे में बागी नेताओं ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सबसे पहले वे भाजपा नेताओं से नजदीकी बढ़ा रहे हैं।

कुछ समय पहले तक खांटी कांग्रेसी कहे जाने वाले ये बागी नेता अब अपने आपको भाजपाई प्रदर्शित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। दरअसल इन नेताओं को अब उपचुनाव की चिंता सता रही है। इसके चलते ही यह नेता अब भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ ही इलाकाई प्रभावशाली नेताओं के दर पर दस्तक दे रहे हैं। इस दौरान वे पार्टी कार्यक्रमों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते दिखना शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि अब तक इंदौर की स्थानीय राजनीति में सालों से एक दूसरे के धुर विरोधी रहे तुलसी सिलावट और कैलाश विजयवर्गीय में करीबी दिखना शुरू हो गई है। हाल ही में मंत्री बने सिलावट सौजन्य भेंट करने विजयवर्गीय के नंदानगर स्थित उनके घर गए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अकेले में काफी देर तक चर्चा होती रही। कहा जा रहा है कि इसमें सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी बात हुई। इस दौरान विजयवर्गीय ने उन्हें उपचुनाव में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। इसी तरह से मंदसौर के सुवासरा से जीते हरदीप सिंह डंग भाजपा के सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसके लिए वे जिले के संगठन नेताओं से लगतार संपर्क बनाए हुए हैं। खास बात यह है कि डंग बीता चुनाव महज 200 वोटों से जीते थे। अब उपचुनाव में डंग से हारने वाले पूर्व भाजपा प्रत्याशी की मदद हर हाल में जरूरी है। यही वजह है कि उनसे लगातार संपर्क बनाया जा रहा है। इसी तरह से पूर्व मंत्री और रायसेन जिले के सांची से विधायक रहे प्रभुराम चौधरी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मुलाकात कर स्थानीय राजनीति से अवगत करा चुके हैं। वे पिछला चुनाव वरिष्ठ नेता गौरीशंकर शेजवार के पुत्र मुदित के विरोध में जीते थे। क्षेत्र में शेजवार की संगठन पर मजबूत पकड़ है। यही वजह है कि शेजवार के सहयोग के लिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विंध्य के नेता और पूर्व मंत्री बिसाहूलाल सिंह भी अब रामलाल रौतेल, रामलल्लू वैश्य, केदारनाथ शुक्ला जैसे नेताओं से लगतार संपर्क बनाए हुए हैं। बिसाहूलाल पिछला चुनाव रौतेल को हराकर ही जीते थे।

इसी तरह बुंदेलखंड में गोविंद सिंह राजपूत अब भाजपा संगठन में सक्रियता बढ़ा रहे हैं। उपचुनाव में उन्हें सीनियर नेता गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह राजपूत की मदद चाहिए। राजपूत पूर्व भाजपा सांसद लक्ष्मीनारायण यादव के पुत्र सुधीर यादव को हराकर चुनाव जीते थे।

पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ग्वालियर-चंबल अंचल में है। इस इलाके में कांग्रेस से आए नेता और भाजपा के नेताओं में समन्वय की दिक्कत है। यही वजह है कि पार्टी संगठन ने इस काम में सभागीय संगठन मंत्री शैलेंद्र बरूआ को लगा रखा है, जिसकी वजह से वे लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। इसी इलाके से ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सबसे अधिक विधायक और नेता भाजपा में आए हैं। ग्वालियर शहर की दो सीटों पर जीत के लिए पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और मुन्नालाल गोयल के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को मनाने का दौर शुरू हो गया है। मुरैना से रघुराज कंसाना के लिए रूस्तम सिंह को भी मनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस अंचल के नेताओं से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी चर्चा करेंगे।

संगठन सूत्रों की मानें तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद उपचुनाव वाले सभी 24 विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं की बड़ी बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इसमें कांग्रेस से आए नेताओं को खासतौर पर बुलाया जाएगा। यहीं से इन नेताओं को संगठन में पूरी तरह स्वीकार करने की पटकथा तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोचा था, कि अन्य नेताओं के दल बदलने पर होने वाली छोटी-मोटी प्रतिक्रिया की तरह ही उनसे भी एक-दो दिन तक लोग सवाल करेंगे। फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन हालात इसके बिलकुल विपरीत हैं। जहां देशभर के लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने को नासमझी भरा आत्मघाती कदम बताया, वहीं सोशल मीडिया पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार से लेकर तरह-तरह के स्तरहीन शब्दों से संबोधित किया जाने लगा। ज्योतिरादित्य

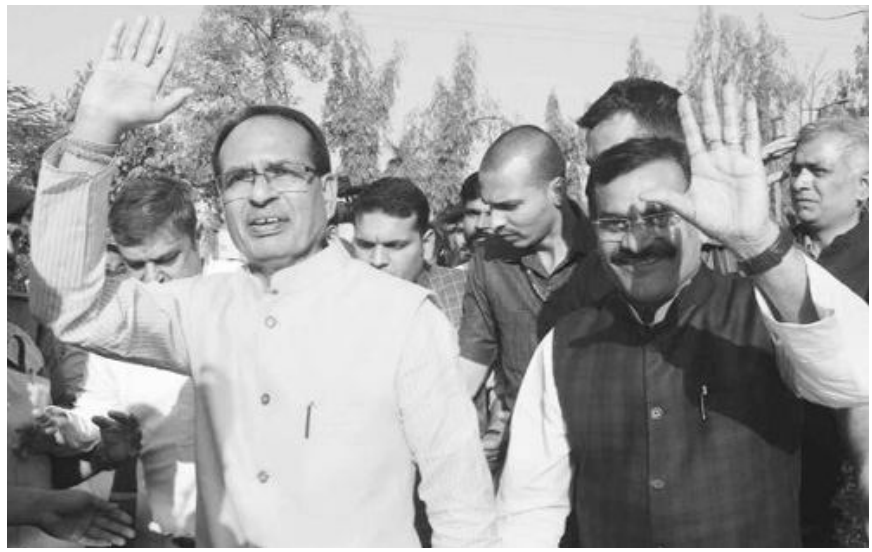

सिंधिया ने न तो कभी जनता से इतनी गालियां सुनी थीं, न ही उन्होंने खुद कभी इसकी कल्पना की थी। सिंधिया की एक गलती से उन्हें श्रीमंत और महाराजा से गद्दार तक की उपाधि से नवाजा जाने लगा है। जब सिंधिया का यह हाल है, तो 22 बागियों के साथ जनता क्या व्यवहार कर रही होगी। उसकी कल्पना तो आप कर ही सकते हैं। बस इतना बता दें कि लोग इन 22 बागियों की सोशल मीडिया पोस्ट का इंतजार करते हैं। जैसे ही ये कोई पोस्ट डालते हैं, हजारों की तादाद में लोग उनसे उनके बिकने की कीमत और जनता से धोखे का कारण पूछकर खिंचाई करने लगते हैं। कुछ बागियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए हैं। तो कुछ ने नया अकाउंट बनाने की तैयारी कर ली है।

वहीं भाजपा खेमे में इन बागियों की अब ना तो कोई जरूरत है, न ही कोई पूछ-परख है। सब जानते हैं कि ये बागी जब अपनी **मातृ संस्था** को धोखा दे सकते हैं। तो फिर ये किसी को भी और कभी भी धोखा दे सकते हैं। ये बागी दिल्ली में भाजपा में तो शामिल हो गए। लेकिन आज तक इनसे इनके जिले का भाजपा जिलाध्यक्ष तक मिलने नहीं आया। ये सब अपने साथ अपने पुराने चमचे भी लेकर भाजपा में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें तब झटका लगा जब एक भाजपा नेता ने कह दिया कि हमें केवल विधायक की जरूरत थी। कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष और प्रवक्ताओं की भाजपा में पहले से ही भरमार है। इसलिए सिर्फ विधायक ही आएं, उनके समर्थक नहीं।

अब ये 22 नेता भाजपा में कांग्रेस से इस्तीफा देकर आ गए हैं, लेकिन भाजपा के छत्रप इन्हें एक बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। एक ऐसा बोझ जिसे जितनी जल्दी उतार फेंका जाए उतनी जल्दी राहत महसूस होगी। अब ये सभी बागी उस पार्टी, उस नेता और उस कार्यकर्ता के भरोसे हैं। जिसे 2018 में हराकर ये विधानसभा पहुंचे थे। इन्हें पैसा मिल गया, मंत्री पद भी मिल जाएगा। विधानसभा का टिकट भी मिल जाएगा। लेकिन भाजपा के उस नेता या उस कार्यकर्ता को क्या मिलेगा जो एक साल पहले ही इनसे पराजित हुआ था। एक बार के लिए भाजपा कार्यकर्ता मन मारकर इनका साथ दे भी दे तो क्या उस क्षेत्र का भाजपा नेता या विधायकी का दावेदार इनका साथ दे पाएगा? हरगिज नहीं, क्योंकि यदि ये बागी एक बार उस क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत गए, तो फिर हमेशा इन बागियों को ही वहां से टिकट मिलेगा। सालों से टिकट का इंतजार कर रहे भाजपा नेताओं का राजीतिक जीवन ही समाप्त हो जाएगा।

● **कुमार राजेन्द्र**

उपचुनाव के बाद भी स्थिरता बनाए रखना मुश्किल

मध्यप्रदेश में जिस तरह के राजनीतिक समीकरण बन गए हैं। उससे यह माना जा रहा है कि उपचुनाव के बाद भाजपा में स्थिरता बनाए रखना मुश्किल होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या क्षेत्रीय भाजपा नेताओं और संघ के पदाधिकारियों के निर्देश पर चल सकते हैं। यह सिंधिया के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, प्रभात झा, रूस्तम सिंह और जयभान सिंह पवैया उन्हें अपना नेता मान लें, यह संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि उपचुनाव के बाद भी जो स्थितियां उत्पन्न होंगी, उसमें भाजपा में भी विरोध देखने को मिलेगा। चर्चा यहां तक होने लगी है कि स्पष्ट बहुमत के अभाव में राष्ट्रपति शासन लगाकर मध्यावधि चुनाव कराकर, भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की कोशिश करेगी। उधर, कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि बागी विधायक इस्तीफा देकर और भाजपा को ज्वाइन करके पछता रहे हैं। क्योंकि अभी तक दो लोगों को छोड़कर न तो कोई मंत्री बना और न ही भाजपा संगठन ने उन्हें स्वीकार किया है। सिंधिया भी न तो राज्यसभा के सदस्य बने, न ही वह केंद्र में मंत्री बने हैं। जिसके कारण उन्हें भी लगने लगा है, कि वह किसी साजिश के शिकार हो गए हैं। उनके समर्थक विधायक भी अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

ये दोस्ती टूट गई!

मप्र की राजनीति में पिछले डेढ़ साल से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी शोले फिल्म के **जय-वीरू** की तरह नजर आ रही थी। वैसे इनकी दोस्ती दशकों पुरानी है। लेकिन इस दोस्ती में जितनी गहराई कांग्रेस की डेढ़ साल की सरकार के दौरान दिखी उतनी पहले नहीं दिखती थी। इनकी दोस्ती को देखकर लोग शोले फिल्म का गाना भी गाने लगे थे कि 'ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे...' लेकिन सत्ता जाते ही दोस्ती में भी गांठ पड़ गई है। ऐसा वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य देखकर मप्र कांग्रेस में दावा किया जा रहा है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि 20 मार्च को कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ दिन बाद से ही दोनों नेताओं में **अबोला** की स्थिति है। आलम यह है कि पिछले एक माह से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में होने वाली बैठकों में कभी भी दिग्विजय सिंह नजर नहीं आए। सूत्रों का कहना है कि न ही उन्हें इन बैठकों के लिए बुलाया गया और न ही वे स्वयं शामिल हुए। इससे प्रदेश की राजनीतिक वीथिका में यह सुगबुगाहट हो रही है कि दोनों नेताओं की दोस्ती टूट गई है।

कमलनाथ ने जबसे प्रदेश कांग्रेस की राजनीति संभाली है तब से यही माना जा रहा था कि वे दिग्विजय सिंह की सलाह पर ही काम करते हैं। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद से लेकर अभी तक हुई बैठकों में दिग्विजय सिंह गायब रहे। उपचुनाव या अन्य मसलों को लेकर कांग्रेस की जितनी भी बैठकें हुई हैं उनमें कमलनाथ के साथ सज्जन सिंह वर्मा, सुखदेव पांसे, एनपी प्रजापति, राजीव सिंह और प्रवीण कक्कड़ शामिल रहते हैं। यहां बता दें कि प्रवीण कक्कड़ तो वर्तमान में कांग्रेस के सदस्य भी नहीं हैं। वहीं कभी-कभार इन बैठकों में बाला बच्चन और सुरेश पचौरी भी नजर आ जाते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह एक बार भी नजर नहीं आए हैं। ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि आखिर ये दोस्ती क्यों टूट गई?

कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की राजनीति की तुलना करें तो, बड़ा फासला है। दिग्विजय सिंह अपनी पारी खेल चुके हैं और कमलनाथ की राजनीति और बिजनेस एक-दूसरे के पूरक जैसे हैं। बिजनेस ही कमलनाथ की राजनीति को सक्षम बनाता है और उसी की ताकत के बूते वो भाजपा के सामने चुनाव मैदान में टिक पाए। वहीं दिग्विजय सिंह का पेशा ही राजनीति है। उनकी हमेशा यह कोशिश रहती है कि उनके आगे कोई न निकले। सूत्रों का कहना है कि अभी तक तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की दोस्ती रही है, लेकिन इस दोस्ती का आधार सिंधिया घराने से दुश्मनी रही है। अब कांग्रेस में फिलहाल सिंधिया घराने का कोई नामलेवा नहीं है। शायद यही वजह हो सकती है कि दोनों ने अपने रास्ते अलग-अलग कर लिए हों।

वहीं सूत्र बताते हैं कि जब कांग्रेस में अपनी उपेक्षा से ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज होने लगे थे तब मौके की नजाकत को भांपते हुए कमलनाथ ने **सुनील भारती मित्तल और शोभना भारती** की मौजूदगी में सिंधिया के साथ समझौता करने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं और सिंधिया बैठक से बाहर हो गए। उसके बाद सिंधिया ने सोनिया गांधी को भी पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। ऐसी स्थिति में दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को आश्वस्त किया था कि सिंधिया कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपकी सरकार पूरी तरह सुरक्षित है। सूत्र बताते हैं कि दिग्विजय के इसी आश्वासन के कारण कमलनाथ ने सिंधिया को कभी भी मनाने की कोशिश नहीं की। अब जब सिंधिया के कारण उनकी सरकार जाती रही तो इसके पीछे दिग्विजय सिंह को वजह मानते हुए कमलनाथ ने दूरी बना ली है।

कुछ सूत्र तो यह भी बताते हैं कि सिंधिया के भाजपा में चले जाने के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ के रास्ते का **एक कांटा** भले ही निकल चुका है लेकिन अभी कई बाकी हैं। इनमें से एक दिग्विजय सिंह भी हैं। जहां सिंधिया खुद कमलनाथ के लिए चुनौती थे, वहीं कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ की राह में भी सिंधिया को बड़े चैलेंज के तौर पर देख रहे थे। सिंधिया की विदाई के बाद कमलनाथ को अपने बेटे के रास्ते में अब सिर्फ दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ही रोड़ा हो सकते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह की भी कोशिश होगी कि वे प्रदेश में नकुलनाथ को सक्रिय न होने दें। इसलिए दोनों नेताओं ने मनमुटाव इतना बढ़ गया होगा कि बरसों पुरानी दोस्ती टूट गई है।

● **राजेश बोरकर**

अजय-अरुण भी पड़े अलग-थलग

डेढ़ साल में ही सत्ता जाने के बाद कांग्रेस के सामने 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव ही वह माध्यम है जिसके रास्ते वह फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है। कांग्रेस उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस की इस चुनावी तैयारी में अजय सिंह और अरुण यादव जैसे कद्दावर नेता गायब हैं। दोनों ही नेता भले ही विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन आज भी इनका प्रदेश की राजनीति में रसूख है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि कमलनाथ की बैठकों में इन नेताओं को बुलावा नहीं भेजा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस किस प्रकार उपचुनाव में भाजपा को मात दे पाएगी और सत्ता में वापसी कर पाएगी। कांग्रेस के एक पदाधिकारी कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ न जाने किस रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्हें विधानसभा चुनाव 2018 की तरह सभी नेताओं को एकसाथ लेकर उपचुनाव में उतरना होगा। तभी भाजपा का मुकाबला किया जा सकता है।

फ्रीहैंड सरकार नहीं चला पाएंगे शिवराज?

लंबे इंतजार के बाद अंतत: शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का गठन हो गया, आम लोगों से लेकर मंत्री बनने की उम्मीद लिए बैठे नेताओं के लिए यह अधूरी ख्वाहिशें पूरी होने जैसा ही है। कोरोना संकट से जूझ रहे मध्यप्रदेश के लोगों को एक भरे-पूरे कैबिनेट की उम्मीद थी। विधायकों की एक बड़ी तादाद भी मंत्री बनने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मंत्रिमंडल में नरोत्तम मिश्रा को शामिल करने पर कोई संदेह नहीं था। कमलनाथ सरकार को गिराने में उनकी भूमिका को देखते हुए शिवराज की सरकार में उन्हें नंबर दो की हैसियत मिलने की पहले से ही संभावना जताई जा रही थी। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के प्रतिनिधि हैं। सिलावट कमलनाथ की सरकार में स्वास्थ्य और राजपूत परिवहन मंत्री थे। मंत्रिमंडल में जातीय समीकरणों को साधने के लिए गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जैसे वरिष्ठ पार्टी नेताओं की दावेदारी को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय से इनके लिए गाड़ियों और दफ्तर की व्यवस्था करने का निर्देश भी जारी हो चुका था, लेकिन अब पांच लोगों को ही शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि शिवराज ने इतनी छोटी कैबिनेट का गठन क्यों किया। सवाल यह भी है कि यह शिवराज की पसंद है या मजबूरी। दरअसल, कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से सत्ता छीनने के लिए भाजपा ने जिस तरह एड़ी-चोटी का जोर लगाया था, अलग-अलग गुटों को साथ लेकर चलना उसकी मजबूरी थी। सरकार बन जाने के बाद ये सभी गुट सत्ता में अपने प्रतिनिधित्व को लेकर उतावले हो रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाहकर भी सभी गुटों को संतुष्ट नहीं कर सकते। ऐसे में पार्टी आलाकमान ने बीच का रास्ता निकाला, जिसमें सभी गुटों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व देकर उन्हें साधने की कोशिश की गई है। शिवराज ने अपने मंत्रिमंडल में प्रदेश के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। इसमें ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग के नेताओं को मंत्री बनाया है। मंत्रिमंडल में दो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं लेकिन उनके गढ़ ग्वालियर-चंबल संभाग से उनके किसी समर्थक को जगह नहीं मिली। उसकी जगह नरोत्तम मिश्रा इस क्षेत्र से मंत्री बने। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खेमे के विधायकों को भी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। उनके गढ़ निमाड़-मालवा से सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट मंत्री बने।

विपक्षी पार्टियां ही नहीं, भाजपा के अपने विधायक भी मंत्रिमंडल के गठन में देरी से खुश नहीं थे। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही थीं कि सत्ता में आने की जल्दी में भाजपा ने कमलनाथ की सरकार तो गिरा दी, लेकिन अब कैबिनेट का गठन तक नहीं कर पा रही। स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक भी कोरोना संकट के दौर में प्रदेश में स्वास्थ्य और गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री नहीं होने को लेकर आपत्ति जता रहे थे। राज्य में कोरोना का प्रकोप भी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए शिवराज के लिए कैबिनेट गठन में और देरी करना मुनासिब नहीं था। बता दें कि मध्यप्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या के लिहाज से मंत्रिमंडल में अधिकतम 15 प्रतिशत यानी 35 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान ने फिलहाल 5 लोगों को जगह दी है और उन्हें मिलाकर छह लोग ही होते हैं। मंत्रिमंडल में अभी भी 29 जगह हैं, माना जा रहा है कि बाद में भाजपा के दिग्गज नेताओं को जगह दी सकती है। मंत्रिमंडल गठन के बाद भाजपा में आक्रोश के स्वर सामने आने लगे हैं। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने श्रमिकों की मजदूरी का मुद्दा उठाते हुए सवाल खड़ा कर दिया है कि मेरे क्षेत्र में तो किसी को एक हजार रुपए नहीं मिले हैं। वहीं कई कद्दावर नेता कोप भवन में चले गए हैं।

मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद अटकलें लगाई जा रहीं थी कि नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान ने शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मुहर लगाई। कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद थे और पार्टी ने उनकी पसंद को सहमति दी है। वहीं, कैबिनेट गठन में भी शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पसंद के नेताओं को जगह मिली है। सिंधिया समर्थक नेताओं को कैबिनेट में शामिल करने के लिए मध्यप्रदेश के कई सीनियर नेताओं को अभी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि मिनी कैबिनेट के गठन के पीछे कोरोना संकट बताया गया है। कहा जा रहा है कि 3 मई के बाद शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे और उसमें पार्टी के सीनियर नेताओं को मौका मिलेगा। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा तोहफा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद एक बार फिर से मध्यप्रदेश की सिसायत में बढ़ गया है।

● **अरविंद नारद**

बड़े नाम मंत्री क्यों नहीं बने?

भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि गत दिनों तक मंत्रिमंडल में गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह को शामिल किया जाना तय माना जा रहा था, लेकिन बाद में दोनों को होल्ड कर दिया गया। इसकी दो वजह भी बताई जा रहीं हैं। पहली जातिगत और दूसरी क्षेत्रीय संतुलन। अगर शिवराज अपने मंत्रिमंडल में पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव को शामिल करते तो उनके मंत्रिमंडल में दो ब्राह्मण मंत्री होते। यदि भूपेंद्र सिंह को शामिल किया जाता तो गोविंद सिंह राजपूत को मिलाकर दो ठाकुर मंत्री होते। इसके अलावा दूसरी वजह जो बताई जा रही है, उसके अनुसार अकेले सागर संभाग से ही तीन मंत्री बनने से भी पद की आस लगाए विधायकों और ज्योतिरादित्य खेमे के पूर्व मंत्रियों को अच्छा संदेश नहीं जाता। सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा राजनीतिक घमासान ग्वालियर-चंबल संभाग में ही देखने को मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के जो विधायक कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, उनका मंत्री बनना तय है। इसमें से चार ग्वालियर-चंबल संभाग से ही आते हैं। इसके अलावा ऐंदल सिंह कंसाना और रघुराज कंसाना सिंधिया समर्थक तो नहीं हैं, लेकिन मंत्री बनाए जाने के आश्वासन पर ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। ऐसे में यहां भाजपा नेताओं का क्या होगा और उनकी अगली रणनीति क्या होगी, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। ग्वालियर के ही कुछ वरिष्ठ नेता सिंधिया समर्थकों के पार्टी में आने और उन्हें मंत्री बनाए जाने से खुश नहीं हैं।

मप्र में मंत्रिमंडल गठन के साथ ही पांचों मंत्री अपने-अपने विभाग के साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने से संबंधित कार्यों में जुट गए हैं। इस दौरान सभी मंत्री लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी को परेशानी न हो। साथ ही लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी आसानी से हो सके।

मप्र में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना की जांच

मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण से संक्रमित लोगों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से शुरू हो गया है। इसके लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पहल की थी। विगत दिनों उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से बात कर प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने की अनुमति मांगी थी। केंद्र ने इसके लिए अनुमति दे दी है और आर्थिक राजधानी इंदौर में इस पद्धति से इलाज भी शुरू हो गया है। कोरोना के हॉटस्पॉट बने इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों का इलाज शुरू किया गया है। शहर के दो मुस्लिम युवा डॉक्टरों ने सबसे पहले अपना प्लाज्मा कोरोना ग्रस्त दो मरीजों को दान किया है। उम्मीद है कि, इस थेरेपी की मदद से बेहतर परिणाम सामने आएंगे।

प्लाजमा थेरेपी उन मरीजों को दी जाएगी, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। क्योंकि ऐसे कई मरीज हैं, जिनका लंबे समय से इलाज चलने के बावजूद हालत में किसी तरह का सुधार नहीं आ रहा है। इसका कारण है उनकी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता। इनमें खासकर बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। इस पद्धति से उन मरीजों का इलाज किया जाएगा, जिन्हें लगातार इलाज दिए जाने के बावजूद उनके बचने की उम्मीद कम है। अब तक जो भी मरीज इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, उनके शरीर में अब ऐसी एंटी बॉडीज बन गई हैं, जिनकी मदद से उनका शरीर इस संक्रमण से लड़ने में सफल हो गया है। ऐसे में स्वस्थ हो चुके मरीज अपना प्लाज्मा अधिक संक्रमित मरीज को देगा, तो उसके शरीर में भी वो एंटी बॉडीज पहुंचकर संक्रमण से लड़ने लगेंगी। अब तक इस थेरेपी के चीन में काफी सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं।

दुनियाभर में विकराल रूप धारण करते जा रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की खोज की जा रही है। इसके लिए परीक्षण भी शुरू किया जा चुका है। लेकिन कामयाबी कब तक मिलेगी, यह किसी को नहीं पता। हालांकि इस बीच कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी कारगर मानी जा रही है। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना से पहले भी कई बार संकट के मौके पर अपना सटीक काम कर चुकी है। अभी तक देश में कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल दिल्ली और केरल में ही हो रहा था। वहीं दुनिया के कई अन्य देशों में भी इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के अलावा अमेरिका, स्पेन, दक्षिण कोरिया,

इटली, टर्की और चीन समेत कई देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है।

चीन में कोरोना वायरस का मामला सामने आने पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल शुरू किया गया था। चीन में जहां कोरोना का मामला बढ़ा, वहां पर भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। वहां भी सकारात्मक रिजल्ट आए। प्लाज्मा थेरेपी को पहले भी कई गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग में लाया गया। वायरस से संबंधित कई गंभीर बीमारियों का इस थेरेपी से इलाज किया जा चुका है। प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल 2002 में किया गया। 2002 में सार्स नाम के वायरस ने कई देशों में तबाही मचा रखी थी। इस वायरस के खात्मे के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। सार्स के बाद 2009 में खतरनाक एच1एन1 इंफेक्शन को रोकने के लिए प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया गया था, जिसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली। इसी तरह 2014 में इबोला जैसे खतरनाक वायरस को रोकने के लिए भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया। तब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इबोला को रोकने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की पहल पर कोरोना का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से शुरू हो गया है। चिकित्सक अनुमान लगा रहे हैं कि इस पद्धति से इलाज कर जल्द ही कोरोना संकट पर विजय हासिल की जा सकती है। उधर, लोगों ने नरोत्तम मिश्रा को इसके लिए धन्यवाद दिया है कि उन्होंने इस दिशा में सार्थक पहल की।

● **विशाल गर्ग**

अब थंब इम्प्रेशन के बिना मिल रहा राशन

मप्र में अब राशन दुकानों पर हितग्राहियों को बिना थंब इम्प्रेशन के बिना राशन दिया जा रहा है। दरअसल, थंब इम्प्रेशन से कोरोना वायरस फैलने की आशंका बनी हुई है। इसको देखते हुए प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बड़ा फैसला लेते हुए राशन दुकानों पर पात्र हितग्राहियों को बिना अंगूठे की छाप दिए राशन देने का निर्देश दिया है। उसमें कहा गया है कि आम लोगों को राशन लेने के लिए अब बायोमैट्रिक थंब इम्प्रेशन नहीं करना होगा। पात्र हितग्राहियों को नियमित दिया जाने वाला राशन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला राशन बिना थंब लगाए देने की छूट रहेगी। कोरोना वायरस के दौरान लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए ही इस तरह की पहल की गई है। इससे लोगों में व्याप्त भय खत्म हुआ है। साथ ही लोग बेझिझक राशन दुकानों पर अनाज लेने पहुंच रहे हैं।

भरे गोदाम, भूखा इंसान

कोरोना काल के इस महासंकट को यूएन की तसदीक की कोई जरूरत नहीं थी। यह हमारे चारों ओर दिख रहा है और साफ दिख रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर झारखंड के सुदूर गांवों तक, करोड़ों लोगों के सामने भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। करोड़ों परिवार ऐसे हैं, जिनके पास न तो राशन कार्ड हैं और न कोई आई कार्ड और न आधार कार्ड। लिहाजा इनमें से ज्यादातर लोगों को, न तो पीडीएस के जरिए राशन मिल रहा है और न ही सरकार की ओर से किए जा रहे तात्कालिक उपायों से इन तक खाना पहुंच पा रहा है।

भारत में भुखमरी कोई नई बात नहीं है। देश के पिछड़े इलाकों से अक्सर भूख से मौतों की खबरें आती रहती हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में दो वक्त का खाना नसीब नहीं होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देशों की लिस्ट में भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान से भी पीछे 102वें नंबर पर है। कोरोनावायरस संक्रमण को काबू करने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के बाद तो हालात और खराब हो गए हैं। घरों से बाहर निकलने और इस वजह से काम करने पर लगी पाबंदी ने उन करोड़ों गरीब परिवारों को दाने-दाने के लिए मोहताज कर दिया है, जो पीडीएस के दायरे में नहीं आते। ये हालात तब हैं जब देश में अनाज के गोदाम ठसाठस भरे हुए हैं। अनाज रखने की जगह नहीं और इसका बड़ा हिस्सा सड़ रहा है। केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान कह चुके हैं कि अगले 9 महीने के लिए अनाज देश में मौजूद है। याद रहे कि रबी की नई उपज भी इसमें जुड़ने वाली है। इसके बावजूद अगर झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर देश के बड़े शहरों से लोगों के भूखे रहने की खबरें आ रही हैं तो पांच ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देखने वाले इस देश की नीतियों में कुछ समस्या जरूर है।

लॉकडाउन के दौरान घोषित राहत पैकेज के मुताबिक सरकार ने पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) दुकानों के जरिए हर देशवासी को अतिरिक्त पांच किलो अनाज और एक किलो दाल तीन महीने तक फ्री देने का ऐलान किया था। लेकिन इस देश में लगभग 10 करोड़ गरीब लोग पीडीएस के दायरे से बाहर हैं। उनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसी बड़ी आबादी पर आज इस भयावह दौर में भुखमरी का संकट मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड तक एक बड़ी आबादी के पास खाने को कुछ नहीं है। लॉकडाउन ने इनकी मेहनत-मजदूरी का रास्ता बंद कर दिया है। अब इनके पास जो भी बचा-खुचा है, वो भी खत्म हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के एक गांव में लोगों ने बताया कि तीन-तीन दिन तक भूखा रहना पड़ रहा है या पानी पीकर गुजारा करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 50 आदिवासी परिवारों को जानवरों के चारे में इस्तेमाल होने वाली चीजें खाकर गुजारना करना पड़ रहा है। गंभीर बात यह है कि लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा आदिवासियों और दलितों पर वार किया है, जो हाशिए पर हैं। ये उन दस करोड़ लोगों में शामिल हैं, जिन्हें पीडीएस का राशन नहीं मिलता।

देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2013 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू हुआ था। इसके तहत 75 फीसदी ग्रामीण आबादी और 50 फीसदी शहरी आबादी को केंद्र सरकार हर महीने सस्ते दर पर पांच किलो अनाज देती है। यह आबादी पूरे देश की आबादी का लगभग 67 फीसदी है। केंद्र सरकार यह अनाज राज्य सरकारों को सप्लाई करती है, जो पीडीएस के जरिए इसे लोगों में बांटती है।

2011 की जनगणना के मुताबिक देश की आबादी 1.22 अरब थी। 67 फीसदी के हिसाब से पीडीएस के दायरे में आने वाली आबादी बैठती है, 81.40 करोड़ के आसपास। इस बीच दस साल बीत गए और अनुमान के मुताबिक देश की आबादी लगभग दस करोड़ बढ़ चुकी है। लेकिन केंद्र सरकार बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से पीडीएस कवरेज बढ़ाने की राज्य सरकार की मांग अनसुनी करती आ रही है। लिहाजा राज्यों को 2011 की जनगणना के हिसाब से पीडीएस कवरेज में आए लोगों के लिए अनाज मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा कार्यकर्ता लंबे समय से पीडीएस यूनिवर्सलाइजेशन की मांग कर रहे हैं। यानी देश के हर नागरिक को पीडीएस के दायरे में लाए जाने की मांग। कोरोना संकट को देखते हुए हर किसी को अनाज देने के लिए उप्र, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना समेत कुछ राज्यों ने ऐलान किया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी अनाज मिलेगा। लेकिन दिल्ली जैसे राज्य में इस प्रक्रिया को जटिल बना दिया गया है। दिल्ली में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें राशन लेने के लिए अपने फोन नंबर डालकर खुद को ऑनलाइन एनरॉल कराना पड़ता है। इसके बाद उनके नंबर पर एक ओटीपी आता है। फिर आधार अपलोड और परिवार का फोटो डालना पड़ता है। इसके बाद एक ई-कूपन मिलता है, जिसे राशन बांटने वाले के पास खोलना पड़ता है।

● **सुनील सिंह**

ठसाठस भरे हैं गोदाम फिर भी लोग खाने को मोहताज

देश में इस वक्त अनाज के गोदाम ठसाठस भरे हैं। एफसीआई के गोदामों में कम से साढ़े सात करोड़ टन अनाज भरा हुआ है। यह अभूतपूर्व स्थिति है। इससे पहले इतना अनाज एफसीआई के गोदामों में कभी नहीं रहा था। एक लेख में अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने लिखा है, 'इस साल मार्च में देश में अनाज का स्टॉक 7.70 करोड़ टन पहुंच गया। रबी की फसल कटाई के बाद इसमें और दो करोड़ टन का इजाफा हो सकता है। इतना अनाज भारत के सार्वजनिक भंडारों में कभी जमा नहीं हुआ था। लेकिन दूसरी ओर हालात ये हैं कि लॉकडाउन में लोगों की रोजी-रोटी पर चोट पड़ने से बड़ी आबादी के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है।'

उपचुनाव की रिहर्सल

मप्र की सत्ता भले ही कमलनाथ के हाथों से खिसक गई हो, लेकिन उन्होंने अभी हार नहीं मानी है। दोबारा मध्यप्रदेश की सत्ता में कैसे काबिज हों, इस जुगत में वे जुट गए हैं। इसके लिए उन्होंने प्रदेश की जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से ज्यादा सीटें जीतने के लिए अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उन्होंने अपने पूर्व मंत्रियों को इस काम में लगा दिया है। यही नहीं भाजपा के असंतुष्ट नेताओं को भी साधने की तैयारी की जा रही है। एक तरह से यह कहा जाए कि कांग्रेस ने उपचुनाव की रिहर्सल शुरू कर दी है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

अपनी मैदानी जमावट के साथ ही कमलनाथ ने शिवराज सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। इसके लिए कमलनाथ ने अपनी टीम के छह लड़ाकों यानी छह पूर्व मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उपचुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए गहन रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके लिए नाथ ने अपनी टीम के छह पूर्व मंत्रियों को शिवराज सरकार को घेरने के लिए मैदान में उतारा है। सज्जन सिंह वर्मा ने समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरा। किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अव्यवस्थाओं के बीच फसलों की खरीदी कर किसानों को क्यों परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कम गेहूं खरीदकर अपने व्यापारी मित्रों को मुनाफे पहुंचाने का मौका देने का आरोप भी लगाया।

उमंग सिंघार ने कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में गए पूर्व विधायकों में से दो के मंत्री बनने पर शिवराज की घेराबंदी की है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ग्वालियर-चंबल संभाग, गोविंद सिंह राजपूत को लेकर बुंदेलखंड और तुलसीराम सिलावट को लेकर मालवा के भाजपा नेताओं से सवाल किया कि अब इन क्षेत्रों का बड़ा भाजपा नेता कौन? वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार के तीनों कार्यकालों की पहचान मौतों से कराई। पहला कार्यकाल व्यापमं में हुई मौत, दूसरा किसान हत्या और मौजूदा तीसरे कार्यकाल को कोरोना से हुई मौतों वाला बताया। उन्होंने टेस्टिंग किट की कमी से कोरोना नमूनों की जांच नहीं हो पाने के मुद्दे पर सरकार को घेरा है।

पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कोरोना से निपटने में सरकार के फैसलों, पीपीई किट, मास्क, दवाएं, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर सहित अन्य उपकरणों की खरीदी को क्रियान्वित नहीं करने की आलोचना की। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दमोह में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी आंख निकालने की घटना पर चिंता जताई और कहा कि लॉकडाउन में भी अपराधी निरकुंश हो रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री सचिन यादव ने फसल बीमा पर कमलनाथ सरकार द्वारा राशि जमा नहीं करने के आरोपों का खंडन करते हुए 2017-18 के आंकड़ों के साथ शिवराज सरकार को घेरा। अब इन पूर्व मंत्रियों को प्रदेश सरकार को घेरने के साथ ही जनता के मन में विश्वास भी जगाना है कि भाजपा ने किस तरह उनके द्वारा चुनी गई सरकार को गिराया है।

कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी ने अपना सबसे अधिक फोकस ग्वालियर-चंबल संभाग की सीटों पर किया है। विगत दिनों कमलनाथ और डॉ. गोविंद सिंह के साथ नेताओं ने सिंधिया के साथ पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के विकल्पों पर मंथन किया है। इस दौरान अंचल की करीब आधा दर्जन सीटों पर सिंगल नामों पर चर्चा हुई, लेकिन जौरा, करेरा और मुंगावली सीटों पर फिलहाल कोई भी मजबूत नाम सामने नहीं आया है। बनवारीलाल शर्मा के निधन से रिक्त हुई जौरा सीट पर उनके परिवार के सिंधिया के साथ चले जाने से यह स्थिति बनी है।

सूत्र बताते हैं कि सुमावली सीट से मानवेंद्र सिंह गांधी, दिमनी से रवींद्र सिंह, अंबाह से सत्यप्रकाश शकवार, बमोरी से कन्हैयालाल अग्रवाल, अशोक नगर से अनीता दोहरे, डबरा से सत्यप्रकाश परसेडिया, भांडेर से फूलसिंह बरैया, मेहगांव से राहुल भदौरिया, चौधरी राकेश चतुर्वेदी, ग्वालियर से संत कृपाल महाराज, सुनील शर्मा, ग्वालियर (पूर्व) से अशोक सिंह, बृजेंद्र तिवारी, पौहरी से रामनिवास रावत, हरिवल्लभ शुक्ला, मुरैना से राकेश मावई, दिनेश गुर्जर, परसराम मुदगल, गोहद से रामनरेश हिंडोलिया, मेवाराम जाटव, राजकुमार देशलहरिया के नाम पर चर्चा की गई।

● **नवीन रघुवंशी**

पुराने बागियों पर डोरे डाल रही है कांग्रेस

कांग्रेस को पूर्व में धोखा देकर भाजपा का दामन थामने वाले दो नेताओं की वापसी को लेकर एआईसीसी गंभीर हो गई है। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इनकी वापसी को लेकर बातचीत का दौर तेज हो गया है। दरअसल कांग्रेस अपने पुराने बागियों को मनाकर भाजपा को मात देने की जुगत में हैं। सूत्रों की मानी जाए तो पूर्व सांसद प्रेम चंद गुड्डू और पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी की वापसी को लेकर कांग्रेस गंभीर हो गई है। इनकी वापसी को लेकर भोपाल से दिल्ली तक कवायद तेज हो गई है। वहीं पूर्व सांसद प्रेम चंद गुड्डू और उनके बेटे अजीत बोरासी की वापसी को लेकर भी एआईसीसी में हलचल तेज हो गई है। गुड्डू भी करीब डेढ़ साल पहले कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हो गए थे। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वे फिर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबी रहे। दोनों नेताओं की कई बार मुलाकात भी हो चुकी है। गुड्डू की वापसी का भी अंतिम फैसला एआईसीसी को करना है। प्रेम चंद गुड्डू और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी की वापसी को लेकर कांग्रेस के कई नेता और कुछ विधायक नाराज हो सकते हैं। इन्हें मनाने का जिम्मा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का होगा।

4500 करोड़ स्वाहा कर जागी सरकार

35 साल पहले शुरू की गई 400 मेगावॉट क्षमता की महेश्वर बिजली परियोजना को अचानक बंद कर दिया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि इस परियोजना पर 4500 करोड़ रुपए स्वाहा करने का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि शुरू से इस परियोजना को कागजी करार देकर इसका विरोध होता रहा है। आलम यह है कि 465 करोड़ की प्रस्तावित लागत वाली महेश्वर जल विद्युत परियोजना आज भी अधूरी है और 4500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। दरउसल, मप्र में उजाले के नाम पर निजी कंपनियों को उपकृत करने का ऐसा खेल चल रहा है कि प्रदेश को हर साल हजारों करोड़ रुपए की चपत लग रही है। देर से ही सही प्रदेश सरकार ने महेश्वर परियोजना को सार्वजनिक हित के खिलाफ मानते हुए परियोजना का विद्युत क्रय समझौता रद्द कर दिया है। इस आदेश के साथ ही **परियोजना के लिए दी गई एस्क्रो गारंटी** और पुनर्वास समझौते को भी रद्द कर दिया है।

महेश्वर जल विद्युत परियोजना में नर्मदा नदी पर जिले में एक बड़ा बांध बनाया जा रहा है। 400 मेगावॉट क्षमता की परियोजना के निजीकरण के तहत 1994 में एस कुमार समूह की कंपनी श्री महेश्वर हायडल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया था। राज्य सरकार ने कंपनी के साथ 1994 में विद्युत क्रय समझौता और 1996 में संशोधित विद्युत क्रय समझौता किया था। जिसके अनुसार बिजली बने या न बने और बिके या न बिके फिर भी 35 साल तक निजी परियोजनाकर्ता को समझौते के मुताबिक राशि का भुगतान होता रहेगा। परियोजना की डूब में 61 गांव प्रभावित आ रहे थे। 85 प्रतिशत से अधिक पुनर्वास बाकी है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महेश्वर परियोजना से 80 करोड़ यूनिट बिजली बनना प्रस्तावित है। परियोजना में निर्मित होने वाली बिजली 18 रुपए प्रति यूनिट पड़ती। जबकि फिलहाल प्रदेश में मांग पूरी करने के बाद 3000 करोड़ यूनिट अतिरिक्त बिजली 2.5 रुपए यूनिट की दर पर उपलब्ध है। ऐसे में मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने परियोजनाकर्ता श्री महेश्वर हायडल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर को भेजे आदेश में कहा है कि परियोजनाकर्ता ने विद्युत क्रय समझौते के तमाम प्रावधानों का उल्लंघन किया है। परियोजना में वित्तीय धोखाधड़ी हुई है। परियोजना की बिजली की कीमत 18 रुपए यूनिट से अधिक होगी। इस परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं के चलते बार-बार परियोजना का काम बंद हुआ। परियोजना स्थल की कुर्की हुई और पिछले 10 सालों से काम ठप है। सरकारों ने परियोजनाकर्ता को लाभ पहुंचाने के प्रयास किए। भारत की सर्वोच्च संस्था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 1998, 2000, 2003, 2005 व 2014 की रिपोर्टों में महेश्वर परियोजना के संबंध में गंभीर भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। कैग की 2014 की रिपोर्ट में लिखा है कि सरकार क्यों नहीं महेश्वर परियोजना का समझौता रद्द करती है।

परियोजना से 80 करोड़ यूनिट बिजली बनना प्रस्तावित है। फिलहाल प्रदेश में मांग पूरी करने के बाद 3000 करोड़ यूनिट अतिरिक्त बिजली 2.5 रुपए यूनिट की दर पर उपलब्ध है। अब यह परियोजना सार्वजनिक हित में नहीं है इसलिए इसके विद्युत क्रय समझौते 1994 एवं संशोधित समझौते 1996 को रद्द किया जाता है। 20 अप्रैल को आदेश जारी हुए। इसके अलावा पुनर्वास समझौते व 21 अप्रैल के आदेश में परियोजना के संबंध में दी गई एस्क्रो गारंटी को भी रद्द कर दिया है। मामले में नर्मदा बचाओ आंदोलन संयोजक आलोक अग्रवाल का कहना है महेश्वर परियोजना के खिलाफ पिछले 23 साल से विरोध चल रहा है। आंदोलन के मुताबिक महेश्वर बांध से बिजली बनती भी तो खरीदी नहीं जा सकती थी। विद्युत क्रय समझौते के अनुसार बिजली न खरीदने पर भी सरकार को निजी परियोजनाकर्ता को 35 साल तक हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपए देना पड़ते। यह राशि 42 हजार करोड़ रुपए होती है। जनता के रुपए लुटने से बच गए। आंदोलन की मांग है ऐसे निजीकरण के फैसलों में जनता के साथ लूट बंद होनी चाहिए। परियोजनाकर्ता ने सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से आम जनता का करोड़ों रुपए परियोजना के नाम पर लेकर अन्यत्र लगा दिए गए। परियोजनाकर्ता के डिफॉल्ट के कारण 102 करोड़ रुपए एस्क्रो गारंटी भी सरकार को चुकानी पड़ी। यह राशि भी परियोजनाकर्ता से वसूलनी चाहिए।

आंदोलन ने परियोजना के निजीकरण, बांध से प्रभावित होने वाले 60 हजार किसान, मजदूर, केवट, कहार आदि प्रभावितों के लिए पुनर्वास नीति के अनुसार कोई व्यवस्था न करने का विरोध किया था। परियोजना के रद्द होने से प्रदेश की जनता का 42 हजार करोड़ लुटने से बच जाएंगे। आर्थिक हालातों से जूझ रही फिलहाल परियोजना बंद है। कर्मचारियों को सालभर से वेतन नहीं मिला। सालभर पहले नर्मदा में गिरे गेट को भी ठीक नहीं किया गया।

● **विकास दुबे**

हर साल सरकार पर 2 हजार करोड़ का अतिरिक्त भार

प्रदेश में बिजली का जरूरत से ज्यादा सौदा अब जनता पर बोझ बन चुका है। सालाना करीब 2 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त बिजली के लिए निजी पॉवर प्लांट को भुगतान करना पड़ रहा है। जबकि पूरी बिजली भी इन प्लांट से नहीं ली जा रही है। लॉकडाउन के कारण आधी हो चुकी बिजली की डिमांड में भी सरकार को निजी पॉवर प्लांट को औसत तिमाही में करीब 500 करोड़ रुपए देना पड़ रहे हैं। देशभर में बिजली की मांग कमजोर होने से खरीदार नहीं मिल रहे हैं। मजबूरी में पॉवर प्लांट को बंद रखना पड़ रहा है। बिजली मामलों के जानकार एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में बिजली की उपलब्धता करीब 22 हजार मेगावॉट का दावा किया जा रहा है। जबकि उच्च मांग 1,45,00 से अधिक नहीं पहुंची है। इस समय लॉकडाउन में 6500 से 7 हजार के बीच डिमांड बनी हुई है। पॉवर प्लांट को बंद रखना पड़ रहा है। इसके बावजूद निजी पॉवर प्लांट से फिजूल के करार होने से उन्हें बिना बिजली लिए भी फिक्स चार्ज के नाम पर भारी भरकम रकम देनी पड़ रही है। ये राशि सालाना करीब 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है।

मनरेगा से मदद

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था भी लॉक हो गई है। अधिकांश उद्योग-धंधे बंद हैं। शहरों से पलायन कर लोग गांव पहुंच गए हैं। इससे गांवों पर बोझ बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कार्यों को शुरू कराकर तथा श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि कर बड़ी राहत दी है। इससे देशभर में करीब 5 करोड़ और मप्र में करीब 60 लाख लोगों को राहत मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए लागू लॉकडाउन में मप्र सहित देशभर में मनरेगा योजनान्तर्गत के तहत चल रहे ग्रामीण विकास के सारे काम ठप पड़ गए थे। इससे गांवों में आजीविका का संकट गहराने लगा था, क्योंकि लाखों संख्या में लोग शहरों से पलायन करके गांव पहुंच गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत लंबित भुगतानों की राशि तो जारी की है, साथ ही **लॉकडाउन** में ही मनरेगा के काम शुरू करने की अनुमति दे दी है। इससे गांवों में राहत महसूस की जा रही है। लेकिन क्या इससे प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा?

गौरतलब है कि प्रदेशभर में मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 के लिए 6 लाख 81 हजार ग्रामीण विकास के काम शुरू हुए हैं। इन सभी कार्यों की लागत 3000 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन मध्यप्रदेश में लॉक डाउन होने से सारे विकास के काम ठप पड़े हुए थे। विकास कार्य ठप होने से आदिवासी बाहुल्य ग्रामीण-अंचलों में मनरेगा जॉब कार्डधारी गरीब-मजदूर परेशान होने लगे थे। लेकिन एक बार फिर से काम शुरू हो गए हैं। कोरोना वायरस ने देश के हर वर्ग को प्रभावित किया है। लेकिन पहले से बुरे दौर से गुजर रही **ग्रामीण अर्थव्यवस्था** इससे बुरी तरह चरमरा रही है। अगर मप्र की बात करें तो यहां 54,903 गांव हैं, लेकिन उनकी स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वे प्रवासी मजदूरों को रोजगार दे सकें। सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रदेश के इन गांवों में अचानक 10 लाख प्रवासी मजदूर पहुंच गए हैं। जानकारों का कहना है कि मप्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में फिलहाल मई के मध्य तक बेरोजगारी का कोई संकट नहीं है। क्योंकि हर साल ही इन दिनों बड़ी संख्या में बाहर काम कर रहे मजदूर फसल कटाई के लिए वापस अपने गांव आते हैं। लेकिन उसके बाद स्थिति गंभीर हो सकती है।

लॉकडाउन से जहां देश-दुनिया में बेरोजगारी का संकट है, वहीं सरकारी सूत्रों की मानें तो फिलहाल मप्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे काफी हद तक अछूती है। यहां खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में इतना ज्यादा काम है कि लोगों को बैठने की फुर्सत नहीं है। कृषि विभाग की मानें तो इन दिनों 60-70 फीसदी लोग खेती के कामों में व्यस्त हैं। इससे फिलहाल बेरोजगारी का कोई बड़ा असर नहीं दिखने वाला। लेकिन खेती का काम खत्म होने के बाद इन 10 लाख मजदूरों की रोजी-रोटी का जुगाड़ कैसे होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।

मप्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ है इसका आंकलन इसी से किया जा सकता है कि केंद्र **सरकार के पैमाने** पर मप्र के 80 फीसदी गांव बदहाल साबित हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, आजादी के 70 साल बाद भी गांव पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्राम विकास का स्कोर कार्ड तैयार किया है। इस स्कोर कार्ड में गांवों के विकास के आधार पर 1 से 100 नंबर तक दस श्रेणियां बनाई गई हैं। गांवों को विकास के आधार पर अंक दिए हैं। इस स्कोर कार्ड में मप्र के कुल 54,903 गांवों में से 43,486 गांवों के नंबर 50 से कम हैं। यानी प्रदेश के 80 फीसदी गांव अभी भी पिछड़े हैं। जिन गांवों में विकास का पहिया तेजी से घूमा है उनकी संख्या 11,415 है। इन गांवों के अंक 50 से ज्यादा हैं। जिस आधार पर इन गांवों का सर्वे किया गया है उनमें सड़क, बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी जरूरतों के अलावा जरूरतमंद तक योजनाओं की पहुंच, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोजगार और पलायन को भी शामिल किया गया है। ऐसे में यह संभव नहीं है कि इन गांवों में 10 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सके।

● **कुमार राजेन्द्र**

गांवों में मनरेगा से दूर की जा रही बेरोजगारी

मप्र सरकार के अधिकारियों का दावा है कि शहरों से पलायन कर गांव लौटे मजदूरों को गांव में रोजगार देने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मनरेगा से काम लेने के लिए लोगों ने जॉब कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया है। वहीं गांवों में मनरेगा का काम भी शुरू हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शहर से आने वालों को गांव में रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसी क्रम में मनरेगा से लोगों को रोजगार देने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। प्रदेश में इस साल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण विकास के 3 हजार करोड़ रुपए की लागत से 6 लाख काम शुरू हुए थे, लेकिन लॉकडाउन में सब बंद हो गए थे। हालात यह हो गए थे कि मनरेगा के तहत जिन डेढ़ करोड़ गरीब-मजदूरों ने काम के लिए पंजीयन कराया था, उनमें से सिर्फ 90 हजार लोगों को ही काम मिल सका। अब यह बेकाम मनरेगा जॉब कार्डधारी भी काम मांग रहे हैं। दरअसल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत करीब डेढ़ करोड़ गरीब मजदूरों ने मनरेगा में काम करने अपना पंजीयन कराया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हर परिवार को 100 दिन का काम देना अनिवार्य है, लेकिन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि तक सिर्फ 90 हजार लोगों को ही 100 दिन का काम मिल सका है।

शराब तस्कर मालामाल

तस्करी के निकाले नए-नए तरीके

लॉकडाउन के दौरान तस्करों ने तस्करी के नए-नए फॉर्मूले इजात कर लिए हैं। गुना में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस के नाम पर घरों में शराब पहुंचाने वाले डिलिवरी मैन को पुलिस ने गत दिनों 40 पेटी शराब के साथ पकड़ा। गुना की साईं सिटी कॉलोनी में छापे के दौरान डिलीवरी मैन के किराए के मकान से अवैध रूप से रखी 500 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है, साथ ही एक स्कॉर्पियों भी पकड़ी है। आरोपी इसी वाहन से ग्वालियर से शराब मंगवाता था। वहीं भोपाल में नगर निगम की कचरा गाड़ी में शराब की तस्करी हो रही थी। जिसे मुखबिरों की सूचना के बाद पकड़ा गया। विंध्य क्षेत्र के जिलों में नशीली दवाओं की खूब बिक्री हो रही है। पुलिस रोजाना तस्करों को नशीली दवाओं की खेप के साथ पकड़ रही है। गत दिनों सिंगरौली के चितरंगी में पुलिस ने 1680 सीसी नशीली दवा सहित बाइक व चार पहिया वाहन जप्त किया।

मप्र में लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानें बंद हैं, लेकिन इससे सिर्फ वैध शराब बेचने वालों को समस्या हो रही है। अवैध शराब बेचने वालों का धंधा इस लॉकडाउन में भी खूब फल-फूल रहा है। मप्र आबकारी विभाग के सूत्रों का अनुमान है कि अभी तक लॉकडाउन में शराब तस्करों ने करोड़ों रुपए की अवैध कमाई कर ली है। इसको देखते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी) ने मप्र सहित दस राज्यों की सरकारों से शराब की दुकानें खोलने की मांग की है। लेकिन मप्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि 3 मई के पहले प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी।

आबकारी विभाग के सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में शराब की 3,605 दुकानों से देशी-विदेशी शराब की बिक्री होती है। लॉकडाउन के कारण सरकार ने इन दुकानों को बंद करा दिया है। उसके बाद भी प्रदेश में देशी-विदेशी शराब की अवैध बिक्री खूब हो रही है। सूत्र बताते हैं कि यह अवैध करोबार आबकारी, पुलिस, प्रशासन, कुछ स्थानीय नेता और शराब ठेकेदारों के साथ मिलकर कर रहे हैं। अवैध शराब के कारोबार में उपभोक्ताओं से डबल-ट्रिपल रेट वसूला जा रहा है। मसलन 180-200 रुपए वाली बीयर की बोतल 400-500 रुपए तक में बेची-खरीदी जा रही है। विदेशी स्कॉच 2500 वाली 4 से पांच हजार रुपए तक में ली-दी जा रही है। कमोवेश यही आलम भारत में निर्मित विदेशी ब्रांडेड शराब का है। इस शराब की 800-1000 रुपए के आसपास वाली कीमत की शराब की एक बोतल 2-3 हजार तक में बिक रही है।

सूत्रों का कहना है कि शराब तस्करों से हुई पूछताछ के दौरान पता चला कि लॉकडाउन में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद होते ही, उसकी डिमांड बेतहाशा बढ़ गई। सरकारी दुकान वालों का स्टॉक लॉकडाउन से ठीक पहले आधिकारिक रूप से क्लोज कर दिया गया। ऐसे में शराब कारोबार से जुड़े कुछ लोगों की चांदी हो गई। लॉकडाउन लागू होने की भनक लगते ही शराब के धंधे से जुड़े तमाम लोगों ने बहुतायत में स्टॉक दाएं-बाएं कर लिया, जिसकी अब लॉकडाउन में मनमानी कीमत वसूली जा रही है। शराब करोबार से जुड़े एक व्यापारी ने बताया, सुनने में आ रहा है कि 100 पाइपर्स की एक बोतल की कीमत 625-870 रुपए के आसपास है। जबकि ब्लैकियर इसकी कीमत चोरी-छिपे 2800 से 3000 रुपए तक वसूलते सुने जा रहे हैं।

इसी तरह ज्यादा डिमांड में रहने वाली बैलेंटीन की 1350 एमआरपी वाली बोतल 3000 रुपए में बेची जा रही है तो जॉनी वॉकर रेड लेबल की 1950 रुपए की बोतल 4000 और शिवाज रीगल तथा जानी वॉकर ब्लैक लेबल की 2880 वाली बोतल अधिक डिमांड के कारण 8000 रुपए में बेची जा रही है। यही हालत रेड लेबल जैसे मशहूर ब्रांड की है। बाजार में इसकी कीमत 1450 के आसपास है, मगर लॉकडाउन में इसकी कीमत 2500 से 3000 हजार तक जा पहुंची है। इसी तरह का हाल 150 रुपए वाली छोटी बोतल का है। वैसे सब कुछ खरीदने-बेचने वाले के बीच सौदे पर निर्भर कर रहा है मगर यह भी 300-400 तक के रेट पर बिकने की खबरें सुनी जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश में शराबबंदी के साथ ही हर जिले में कच्ची शराब बनाने की भट्टी खुल गईं। कहीं घर में, कहीं खेत में तो कहीं जंगल में कच्ची शराब की भट्टी खुल गई हैं। पुलिस ने टीकमगढ़ के निवाड़ी, शिवपुरी, जबलपुर सहित करीब दर्जनभर स्थानों पर छापामार कच्ची शराब बनाने के गोरखधंधे पर नकेल कसी है।

प्रदेशभर में पुलिस और आबकारी विभाग ने छापामारी कर अभी तक करोड़ों रुपए की अवैध शराब जप्त की है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पकड़ाए तस्करों से सुराग मिले हैं कि इस गोरखधंधे में कुछ कारोबारी सहित पुलिस भी मिली हुई है। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान शराब की लत वाले आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल में जहां एक व्यक्ति बीयर के भ्रम में एसिड पीने तथा एक व्यक्ति शराब की लत में धतूरा खाने से मौत का शिकार हुआ है। इसी तरह प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी शराब के आदी लोगों की मौत हुई है।

सीआईएबीसी के महानिदेशक विनोद गिरी का कहना है कि लॉकडाउन के बाद सरकार ने शराब की बिक्री पर रोक लगा दिया है। लेकिन अवैध बिक्री हो रही है। इसलिए हमने सरकारों से मांग की है कि वे शराब बिक्री की अनुमति प्रदान करें।

' पुलिस अलग है और हम अलग धरपकड़ कर रहे हैं। हमारे पास सीमित स्टाफ है। फिर भी हम शराब बेचने और बनाने वालों की धर-पकड़ कर रहे हैं। प्रदेश में महुआ से अवैध शराब बनाने वालों पर भी बड़ी कार्यवाही हुई है।

राजेश बहुगुणा, आयुक्त, आबकारी विभाग

● **रजनीकांत पारे**

किसान बेहाल

मप्र में इस बार बिना बोनस के गेहूं की खरीदी हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसानों को कई तरह की सौगातें दी हैं। उन्होंने कृषि ऋण और खाद-बीज के लिए लोन लेने वाले किसानों को 31 मई तक कर्ज चुकाने की छूट दी है, लेकिन गेहूं बेचने जा रहे किसानों से कर्ज की वसूली की जा रही है। इससे किसानों के सामने रोजी-रोटी चलाने की समस्या भी खड़ी हो गई है। मप्र में 15 अप्रैल से गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। लेकिन किसानों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी यह सामने आई है कि **पोर्टल पर किसानों** के रकबे की गलत जानकारी भरी गई है। जब किसान अपनी उपज लेकर उपार्जन केंद्र पहुंचता है तो उसकी थोड़ी उपज ही खरीदी जाती है। इससे किसानों में रोष है। प्रदेशभर में भोपाल, इंदौर और उज्जैन को छोड़कर सभी जिलों के 4,305 खरीदी केंद्रों पर खरीदी का काम चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से खरीदी की प्रक्रिया में कुछ बदलाव लाए गए हैं, जिससे प्रदेश के लगभग हर जिले से किसानों की परेशानियां सामने आ रही हैं। लॉकडाउन की वजह से सरकार ने खरीदी केंद्रों पर भीड़-भाड़ कम रखने का प्रबंध किया है और इसके तहत पहले चुनिंदा छोटे किसानों को एसएमएस के जरिए बुलाया जा रहा है। इन किसानों की गेहूं की खरीदी की सीमा तय की जाती है। हालांकि, रिकॉर्ड में खामी होने की वजह से कई स्थानों पर बड़े किसान अपनी पूरी फसल नहीं बेच पा रहे हैं।

आलम यह है कि एसएमएस मिलने के बाद जब किसान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं तो उनकी पूरी उपज नहीं खरीदी जा रही है। ऐसी ही परेशानी आई बीना के धमना ग्राम निवासी किसान राम प्रसाद को। उन्हें समर्थन मूल्य पर खरीदी का मेसेज मिला और वह 20 क्विंटल गेहूं लेकर बिहराना स्थित खरीदी केंद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि सिर्फ 25 डिसमिल खेती का उनका रिकॉर्ड है और सिर्फ डेढ़ क्विंटल गेहूं बेच सकते हैं। गेहूं न बिकने की वजह से उसे गांव से केंद्र तक लाने में लगा ढुलाई का पैसा भी डूब गया। राम प्रसाद जैसे कई किसानों को प्रदेशभर में ऐसी परेशानी आ रही है। कई जगह ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि किसानों की उपज को गुणवत्ताहीन बताकर वापस लौटा दिया गया। हरदा जिले के ग्राम रिछाड़िया की बुजुर्ग महिला रुक्मिणी पति नर्मदाप्रसाद की उपज को गुणवत्ताहीन बताकर खरीदने से इनकार कर दिया गया। महिला सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक केंद्र पर अधिकारियों से गुहार लगाती रही। काफी मशक्कत के बाद अधिकारियों ने गेहूं की सफाई कर दोबारा लाने को कहा। विदिशा जिले के किसान कार्यकर्ता राजकुमार बघेल ने बताया कि उनके जिले में हाल में हुई बेमौसम बारिश ने गेहूं की चमक खत्म कर दी है। दयानंदपुर खरीदी केंद्र में कई किसान अपना अनाज बेचने पहुंचे थे, इनमें से करीब छह किसानों का गेहूं चमक चली जाने के कारण नहीं खरीदा गया और उन्हें अनाज लेकर केंद्र से लौटना पड़ा।

वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा कृषि ऋण की वसूली पर रोक लगाए जाने के बाद भी समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच रहे किसानों की आधी राशि काटी जा रही है। ऐसे में किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। 18 मार्च को शुजालपुर के जामनेर में किसान दुर्गादास ने सत्यम वेयरहाउस में बने उपार्जन केंद्र पर 18 बोरी गेहूं बेचा। उनके गेहूं का कुल मूल्य 17325 रुपए हुआ। लेकिन उनके द्वारा लिए गए सोसायटी ऋण के विरुद्ध उनकी उपज की आधी रकम 8862.50 रुपए काट ली गई। ऐसा किसी एक किसान के साथ नहीं बल्कि उन सभी किसानों के साथ हो रहा है जिन्होंने कृषि ऋण ले रखा है। प्रदेश के सभी खरीदी केंद्रों पर इस कारण रोजाना किसानों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसानों के आक्रोश का कारण यह है कि उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कहते हैं कि शिवराज जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री होता तो खेत की मिट्टी भी 2100 के भाव बिकवा देता। आज जब वे मुख्यमंत्री हैं तो किसानों का गेहूं 1925 रुपए में खरीद रहे हैं। वहीं बकाया राशि काटकर किसानों के साथ संकट के समय उन्हें दोहरी मार दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वे तत्काल गेहूं खरीदी के बाद किसानों को पूरा भुगतान करें और फिलहाल बकाया राशि काटने पर आदेश निकालकर रोक लगाएं।

● **श्यामसिंह सिकरवार**

किसानों से तुलावटी नहीं ली जाएगी

कृषक कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को लाभान्वित करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा

कि रबी उपार्जन कार्य में किसानों से मण्डियों में हम्माली और तुलावटी की राशि नहीं ली जाएगी। पटेल ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न मण्डियों में हम्माली और तुलावटी की पृथक-पृथक दरें निर्धारित हैं। इन्हें एकीकृत करने पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि रबी उपार्जन के अंतर्गत मण्डी में सौदा-पत्रक के जरिए भी किसान व्यापारियों को सीधे अपनी उपज बेच सकेंगे। मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार किसानों को बीमित राशि का शत-प्रतिशत भुगतान कराएगी। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार द्वारा वर्ष 2018 की रबी और खरीफ फसलों की बीमा राशि के राज्यांश का भुगतान नहीं किए जाने से किसानों को बीमा का क्लेम नहीं मिल पाया। पटेल ने कहा कि अब राज्य सरकार ने खरीफ का राज्यांश 1695 करोड़ रुपए और रबी का राज्यांश 486 करोड़ रुपए, कुल राशि 2181 करोड़ रुपए का राज्यांश जमा करा दिया है। मंत्री पटेल ने कहा है कि सरकार शीघ्र ही सूरजधारा योजना और अन्नपूर्णा योजना में किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए तात्कालिक तौर पर 25-25 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान करेगी। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के बजट में की गई कटौती की पूर्ति करने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि पूर्व में किसानों को उन्नत बीज की उपलब्धता में हुई परेशानी और बीज उत्पादक समितियों को हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए भी सरकार विचार कर रही है।

हरे सोने से भरेगा खजाना

मप्र में 25 अप्रैल से हरे सोने यानी तेंदूपत्ते का संग्रहण शुरू हो गया है। इस बार सरकार ने 19 लाख मानक बोरा पत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के वनक्षेत्रों में आदिवासी और श्रमिक पत्तों के संग्रहण में जुट गए हैं। हालांकि कोरोना वायरस के कारण किए गए लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र के श्रमिक इस बार नहीं आ पाए हैं। इसलिए संग्रहण की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है।

आर्थिक बदहाली के इस दौर में सरकार को कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण बड़ी आर्थिक क्षति पहुंची है। ऐसे में सरकार को तेंदूपत्ता से बड़ी आय होने की संभावना है। प्रदेश के 22 लाख से ज्यादा तेंदूपत्ता श्रमिकों के लिए अच्छी खबर यह है कि वन विभाग ने 11 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता, तुड़ाई से पहले ही बेच दिया है। इस कारण श्रमिकों को बोनस की राशि मिलने में ज्यादा देर नहीं होगी। वहीं, 6 लाख मानक बोरा पत्ता बेचने के लिए विभाग ने फिर से टेंडर जारी कर दिए हैं। इस बार 19 लाख मानक बोरा पत्ता संग्रहण का लक्ष्य है। 25 अप्रैल से तुड़ाई शुरू कर दी गई है और 4 जून से पत्ता फड़ (खरीदी केंद्रों) पर पहुंचना शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदूपत्ता तुड़ाई और 2500 रुपए मानक बोरे में खरीदी करने की घोषणा की है।

विभाग के सूत्र बताते हैं कि पत्ते की क्वालिटी के हिसाब से तीन से छह हजार रुपए मानक बोरा की दर से बीड़ी ठेकेदारों ने पत्ता खरीद लिया है। इसका औसत निकालें, तो 3700 रुपए मानक बोरा में पत्ता बिका है। यह रेट पिछले सालों की तुलना में काफी कम है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में पत्ते के सबसे ज्यादा 5500 रुपए मानक बोरा रेट आए थे, तो पिछले 2 साल में चार से साढ़े चार हजार रुपए रेट आए। बताया जाता है कि इस बार कोरोना वायरस के कारण छाई विश्वव्यापी मंदी का असर तेंदूपत्ता पर भी नजर आ रहा है।

प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान लघु वनोपज, संग्रहण प्रसंस्करण, उपचरण, परिवहन, भंडारण और विपणन कार्यों में संलग्न श्रमिकों और ग्रामीणों को संक्रमण से बचाने के निर्देश दिए हैं। वनोपज संग्रहण के दौरान किसी संग्राहक अथवा वनकर्मी में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो उसे तुरंत निकटतम अस्पताल पहुंचाने के लिए कहा गया है। लघु वनोपज के संग्रहण में संलग्न कर्मचारी, क्रेता और प्रतिनिधि श्रमिक और ग्रामीण अनिवार्य रूप से चेहरे को मास्क, फेसकवर, गमछा, रुमाल, दुपट्टे से ढंककर रखेंगे। तेंदूपत्ता क्रेताओं और उनके प्रतिनिधियों के लिए वन मंडल अधिकारी अथवा प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा पूर्व से निर्धारित परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। प्रत्येक संग्रहण एवं भंडारण केंद्र और गोदाम पर आवश्यक रूप से सेनेटाजर और साबुन रखा जाएगा। यहां सभी संबंधित के लिए आने और जाने, दोनों समय 20 सेकंड तक हाथ धोकर हाथ सैनेटाइज करना जरूरी होगा। वनोपज संग्रहण आदि कार्यों में संलग्न सभी व्यक्ति आपस में कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखते हुए काम करेंगे। प्रत्येक संग्रहण केंद्र पर 2-2 मीटर की दूरी पर चूने का घेरा बनेगा। इन केंद्रों पर रात में कार्य के लिए उचित प्रकाश व्यवस्था होगी।

प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण का काम शुरू हो गया है, लेकिन श्रमिकों को डर सता रहा है कि कहीं इस बार भी उन्हें बोनस से हाथ न धोना पड़े। दरअसल, तेंदूपत्ता संग्राहकों को आर्थिक मदद देने वाला संघ अब आर्थिक घाटे की ओर जा रहा है। जिसकी वजह से बीते वर्ष श्रमिकों को बोनस नहीं मिल पाया था और इस साल का भी मिल पाना मुश्किल है। यह आर्थिक संकट प्रदेश स्तर पर है। रीवा संभाग के चारों जिलों में तेंदूपत्ता से करीब 200 करोड़ रुपए हर साल सरकार को संघ देता था। इसकी आधी लागत पत्ता तुड़ाई एवं परिवहन सहित अन्य कार्यों में खर्च हो जाती थी। करीब 100 करोड़ रुपए का हर साल फायदा होता था। लेकिन अब धीरे-धीरे संघ के सामने समस्याएं आने लगी हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण के साथ अन्य वन संपदाओं की खरीदी भी कुछ समय पहले तक की जाती रही है लेकिन उसमें आए आर्थिक घाटे की वजह से इसे बंद कर दिया गया है। बीते साल रीवा संभाग का महुआ खरीदा गया था लेकिन बाजार मूल्य की तुलना में वह अधिक महंगा पड़ रहा था, जिसकी वजह से बिक्री नहीं हो पाई। इस कारण अब महुआ की खरीदी बंद कर दी गई है। सरकार की ओर से वर्ष 2017 में तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस बांटा गया था। इसके बाद से सरकार की ओर से समीक्षा भी की गई है लेकिन फिलहाल बोनस वितरण करने के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं। चुनावी वर्ष होने की वजह से वर्ष 2017 तक का पूर्व की सरकार ने बोनस वितरित कर दिया था, इसलिए अब पुराना भी लंबित नहीं है, जिसे सरकार बांट सके। माना जा रहा है कि यदि इस वर्ष तेंदूपत्ते का बेहतर संग्रहण होगा तो आने वाले वर्षों में बोनस भी मिलेगा।

● **धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया**

हर साल 100 करोड़ मिलता है ब्याज

लघु वनोजन संघ के खाते में समितियों के 1300 करोड़ रुपए जमा हैं। इसका हर साल करीब 100 करोड़ रुपए ब्याज मिलता है। इस राशि को भी समितियों को बोनस के साथ बांटा जाता है। गौरतलब है कि तेंदूपत्ता संग्रहण से लाभांश की 70 फीसदी राशि लघु वनोपज संघ संग्राहकों को बांट देता है। जबकि 30 फीसदी राशि संघ अपने पास रख लेता है, इसमें से अध्यक्षीय कोटा, स्थापना व्यय और वनों के विकास पर राशि खर्च की जाती है। संघ ने दो टूक कह दिया कि वन समितियों के खातों में पैसा दिया जाएगा। इसके बाद समितियों को तय करना है कि वे इस पैसे का क्या इस्तेमाल करना चाहती हैं। संघ के इस जवाब से डीएफओ का प्रस्ताव रद्द हो गया। प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों को हर साल करीब 300 करोड़ रुपए बोनस दिया जाता है। पिछले साल बोनस की राशि दी गई थी। इससे पहले तत्कालीन भाजपा सरकार ने जूते-चप्पल, साड़ी और पानी की बॉटल बांटी थी, जिस पर भारी विवाद हुआ था। इस बार प्रबंध संचालक ने कहा है कि समितियों के खाते में बोनस की राशि ट्रांसफर की जाएगी। किसी भी सामान की खरीदी यहां से नहीं होगी।

बुंदेलखंड के लोगों के साथ उनका दुर्भाग्य भी चलता है। दूसरे प्रदेशों में मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा करने वाले लाखों लोग लॉकडाउन के बाद अपने घर तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब यहां उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

घर पहुंचकर भी बेहाल

कोरोना के खौफ के चलते शहरों से वापस अपने गांव पहुंचे मजदूरों के सामने अब बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अब का वक्त तो गांव में गेहूं कटाई से मिली मजदूरी से कट गया लेकिन अब क्या होगा। बुंदेलखंड के जनपदों में रहने वाले मजदूर परिवारों के सामने यह सबसे बड़ी चिंता है। उप्र के जिलों से ज्यादा खराब हालात मध्यप्रदेश के गांवों में हैं। क्योंकि इन गांवों में बड़ी संख्या में मजदूर शहरों से वापस लौटे हैं। इस बार मजदूरों की संख्या बढ़ने के कारण मजदूरी के रेट भी घट गए। वहीं लॉकडाउन में अब दुकानदारों ने भी उधार देना बंद कर दिया है। दुकानों पर पोस्टर लगा दिए हैं कि उधार बंद है।

अगर बुंदेलखंड में शामिल जिलों की बात करें तो उप्र के झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट और मध्यप्रदेश के दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और शिवपुरी शामिल हैं। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक इन सब जिलों के पंजीकृत मजदूरों की संख्या 8 लाख है। विगत दिनों एक सर्वे टीम ने झांसी के समीपवर्ती जिलों के उन गांवों में गांवों में जाकर मजदूरों की स्थिति को देखा जो बुंदेलखंड का हिस्सा हैं। सबसे पहले हाईवे किनारे पड़ने वाले झांसी के गांव बडोरा में टीम के लोग पहुंचे और यहां खेत में गेहूं की कटाई कर रहे मजदूरों से मुलाकात की। शोभरन के खेत में गेहूं की कटाई कर रहे मजदूरों का कहना था कि फिलहाल तो काम चल रहा है। गेहूं की कटाई और भूसा ढुलाई से मजदूरी मिल रही है लेकिन उसके बाद क्या होगा। मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिले के **चकरपुर निवासी** देवी सिंह राजस्थान में बेलदारी का काम करते थे लेकिन अब दस दिनों से गेहूं कटाई की मजदूरी कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के गांव मानपुर निवासी गोपाल सिंह गेहूं की कटाई करने के बाद घर में पहुंचे ही थे जब सर्वे टीम ने पूछा तो कहने लगे कि फिलहाल तो गेहूं के भरोसे समय कट जाएगा लेकिन आगे संकट आएगा। झांसी से 30 किलोमीटर दूर मध्यप्रदेश के दतिया जिले के गांव चिरुला निवासी सुदामा कहते हैं कि इस समय मजदूरों के सामने बड़ा संकट है। दुकानदार उधार नहीं दे रहे। ललितपुर जिले के पवा गांव में खेत से गेहूं की कटाई करके लौट रहे रूप सिंह से जब बात की गई तो कहने लगे कि इस बार बेमौसम बरसात ने भी गेहूं की फसल को बेकार कर दिया है। गेहूं खेत में गिर गया था उत्पादन भी कम हुआ है।

अनुमान है कि करीब 6 लाख मजदूर बुंदेलखंड और यहां से जुड़े इलाकों में लौटे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रामबाबू तिवारी कहते हैं कि जिन गांव के घरों में ताले लटके थे वे अब खुल रहे हैं। पलायन से वापसी का आंकड़ा 6 लाख से भी आगे जाएगा। उनका कहना है कि बांदा के गांवों में लगातार मजदूरों का पहुंचना जारी है। मजदूरों के लौटने के बाद सबसे बड़ी चुनौती उनके स्वास्थ्य परीक्षण की है। जो मजदूर आए हैं उनको बिना परीक्षण के वापस घर भेजा जा रहा है। संक्रमण की आपात स्थिति के बीच सरकार की ओर से कई घोषणाएं तो की गई है लेकिन वह जनता तक पहुंचकर कितना राहत देगी यह देखने की बात होगी। सरकार ने मनरेगा मजदूरों के बैंक अकाउंट में राहत धनराशि भेजे जाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन यह धनराशि ऐक्टिव मजदूरों के लिए ही होगी।

मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ और छतरपुर जिले से ही करीब 50 हजार मजदूर एनसीआर से वापस लौटे हैं। यह लोग दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में मजदूरी करते थे। लेकिन अब इनके सामने दो वक्त की रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। मानपुर निवासी दिलीप कुमार ने कहा कि कुछ दिन तो गेहूं की कटाई करके जो मजदूरी मिली उससे कट गए लेकिन अब तो उनके पास कुछ है ही नहीं। जमीन है नहीं जो कुछ कर लेते। दिलीप ने बताया कि वह काफी समय से गाजियाबाद में रहकर मजदूरी कर रहे थे। राशन कार्ड भी नहीं बन पाया है। डीलर के पास गए थे तो उसने कह दिया कि आपका नाम सूची में नहीं है। पहले गांव के दुकानदार उधार दे दिया करते थे लेकिन अब वह भी मना कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के गांव चकरपुर निवासी कपिल कुमार ने बताया कि उनके गांव में तो आज तक कोई नहीं आया। प्रशासन ने भी किसी की मदद नहीं की। लोगों को इस समय में क्या-क्या दिया जा रहा है इसकी जानकारी भी किसी को नहीं है। बांदा के प्रहलाद सिंह कहते हैं कि संकट बड़ा है।

मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि बुंदेलखंड में मजदूरों की संख्या अन्य जिलों के मुकाबले ज्यादा है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी के भी सामने कोई दिक्कत न हो। राशन का वितरण कराया जा रहा है। जिनके पास कार्ड नहीं हैं उनके कार्ड गांव और मोहल्लों में बनाए जा रहे हैं। सभी एसडीएम निरीक्षण कर रहे हैं। वह खुद लगातार जायजा ले रहे हैं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

अब शहरों में वापसी भी बड़ी चुनौती बनेगी

निवाड़ी निवासी रोहताश कुमार का कहना है उस जैसे करीब 500 मजदूर दिल्ली में किराए का मकान लेकर परिवार के साथ रहते थे। अब जब लॉकडाउन हुआ तो मकान खाली करके आ गए। अब अगर शहर को वापस जाएंगे तो दोबारा से मकान की तलाश करनी होगी। बड़े शहरों में मकान मिलना आसान नहीं है। नत्थीखेड़ा निवासी सुशील कहते हैं कि अभी तो लॉकडाउन खत्म ही नहीं हो पा रहा। मई-जून ऐसे ही बीत जाएगा तो फिर कैसे शहर में जाकर रहेंगे। जो पैसा था वह भी खत्म हो गया है। मकान मालिक एडवांस मांगते हैं।

संकट में आदिवासी

आदिवासियों पर जुल्म और शोषण का लंबा इतिहास रहा है और समय-समय पर कई रूपों में यह सामने आता रहा है। लेकिन, आदिवासियों में भुखमरी अब एक बड़े संकट के रूप में उभरकर सामने आ रही है। हाल में झारखंड के बोकारो में भूखल घासी नामक एक व्यक्ति की मौत ने फिर से साबित किया कि सरकारें आदिवासियों की सुरक्षा के मोर्चे पर विफल रही है। घासी के परिवारजनों का कहना है कि पिछले कई दिनों से उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि, यह ऐसी कोई पहली घटना नहीं है। झारखंड से ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं। नवंबर, 2018 में पश्चिम बंगाल में कुपोषण के कारण सात आदिवासियों की मौत हो गई थी और मामला चर्चा में रहा था। 2019 में भी भूख के चलते आदिवासियों की मौत की खबरें रोशनी में आती रहीं। एक अनुमान के मुताबिक 1967 के बाद से अब तक केवल झारखंड (जो पहले बिहार का हिस्सा था) में भूख की वजह से लाखों आदिवासियों की मौत हो चुकी है। कहने की जरूरत नहीं कि देशभर में अब तक न जाने कितने आदिवासी भुखमरी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। इस अनचाही मौत का सिलसिला दशकों से थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर साल देशभर में ऐसे दर्जनों मामले सामने आते हैं जब पर्याप्त खाने की कमी के कारण आदिवासी दम तोड़ देते हैं। लेकिन, विडंबना है कि हमेशा ही सरकारें और प्रशासनिक अमला कुछ और ही सच्चाई बयां करते हुए दिखता है।

साल 2018 में जब पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में सबर और लोधा समुदाय के सात व्यक्तियों की मौत हुई थी, तब भी मुख्य वजह पर्याप्त भोजन का उपलब्ध न हो पाना थी। लेकिन, सरकार ने क्षय रोग को मौत का कारण बताकर पल्ला झाड़ लिया था। हाल में जब झारखंड के बोकारो में आदिवासियों की मौत हुई, तब भी सरकार ने भोजन की कमी वाली बात से इनकार कर दिया। हालांकि जांच में पता चला है कि ऐसे परिवारों में अमूमन राशन कार्ड ही नहीं है और यह सरकार और प्रशासनिक अमले की बहुत बड़ी चूक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पोषणयुक्त आहार की कमी आदिवासियों की मौत की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन, सवाल है कि उन्हें पोषणयुक्त आहार क्यों नहीं मिल रहा? दरअसल, यह सबसे बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब तलाश कर ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (2015-16) के अनुसार महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्येक दूसरे बच्चे का विकास अवरुद्ध होने का कारण लंबे समय तक भूखे रहने से उत्पन्न कुपोषण की समस्या है। पर्याप्त पोषण आहार की कमी का ही नतीजा है कि आदिवासियों की जीवन प्रत्याशा चौंकाने वाली है। दरअसल, उनका जीवनकाल औसत भारतीय जीवन प्रत्याशा से लगभग 26 साल कम है। जाहिर है, यह अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा, उनका जीवन अनिश्चितताओं से भरा होता है और सरकारों की नजर में आदिवासियों का मरना कोई चिंता का विषय नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो, बात घूम-फिरकर गरीबी पर ही आ जाती है। दरअसल, मौजूदा वक्त में खेती-किसानी की बदतर हालत किसी से भी छुपी नहीं है। जाहिर है, खेती पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों की भी खस्ता हालत से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा, ग्रामीण इलाकों में आदिवासी भी मनरेगा में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करने को मजबूर हैं। लेकिन चिंता का विषय है कि समय पर मजदूरी न मिलने के कारण वे, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। यानि आमदनी की कमी एक बड़ी समस्या है। लिहाजा, ये गरीब आदिवासी अपने आप ही भुखमरी के शिकार हो जाते हैं।

बाहरी दुनिया द्वारा थोप दी गई श्रेष्ठता का ही परिणाम है कि आदिवासियों ने खुद को हीन, आदिम मान लिया है और यहां तक कि अपने जीवन के प्रति उनका एक घातक दृष्टिकोण भी पैदा हो गया है। ये सभी पहलू उन्हें हाशिए पर धकेल देते हैं, यहां तक कि उन्हें सामाजिक रूप से एकजुट करने वाले कुछ रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक प्रथाओं को विशेष रूप से लोकतांत्रिक मानदंडों और मानवीय मूल्यों को छोड़ देने पर मजबूर कर देता है जो सामूहिक जीवन की एक लंबी यात्रा और अस्तित्व के लिए संघर्ष के माध्यम से विकसित हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि गरीबी एवं भूमिहीनता की समस्या ने उन्हें भुखमरी के कगार पर ला खड़ा किया है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

आदिवासी परिवारों के सामने भोजन का संकट

आदिवासी परिवारों में भोजन का संकट वन आजीविका पर उनकी पारंपरिक निर्भरता में कमी और राज्य में गहन कृषि संकट के कारण उत्पन्न होता है। इसके अलावा, व्यवस्थित मुद्दों और सार्वजनिक पोषण कार्यक्रमों की कमजोरी ने समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया है। मिसाल के तौर पर पालघर के विक्रमगढ़ कस्बे में लगभग एक चौथाई जनजातीय परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सिर्फ इसलिए राशन नहीं मिल सका, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं थे। झारखंड से भी अक्सर ऐसे ही मामले सामने आए हैं। फिर राज्यों के बजट में पोषण व्यय में कमी भी एक समस्या है। जाहिर है, यह पोषण के प्रति सरकार की तेजी से कम होती प्रतिबद्धता का सूचक है। इस प्रतिबद्धता में संजीदगी दिखाने की जरूरत है। भोजन के अधिकार कानून के बावजूद भूख से मौतों की खबरें चिंता पैदा करती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कैसे सरकारी दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित होते हैं। हर व्यक्ति तक अनाज की आसान पहुंच को सुनिश्चित करना होगा और इसके लिए दो बातें बेहद जरूरी हैं। पहली तो यह कि बेहतर राजनीतिक कार्यशीलता सरकार को दिखानी होगी। बिना किसी राजनीतिक इच्छाशक्ति के इन समस्याओं पर काबू पा लेने का हर दावा खोखला ही है और दूसरा यह कि कैसे व्यवस्था के विभिन्न साधनों का उचित उपयोग कर लोगों की जरूरतों की पूर्ति की जाए।

चीन का चक्रव्यूह तोड़ेगा भारत?

- कोविड-19 के बाद बदल जाएगी दुनिया की सूरत
- भारत बन सकता है विश्व की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु
- सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बड़ी चुनौती
- लॉकडाउन की वजह से हर चौथा व्यक्ति बेरोजगार
- स्वदेशी को बढ़ाने की जरूरत
- केवल वादों और नारों से नहीं बनेगी बात
- भारत को विश्वगुरु बनाने का बेहतर मौका
- प्रकृति के महत्व को समझने का अवसर
- भारत को मुक्त व्यवस्था से निकलना होगा बाहर
- स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना जरूरी
- चीन पर अत्यधिक निर्भरता को करना होगा बाय-बाय
- स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारों को बजट बढ़ाना होगा
- ईमानदारी से गरीबी को मिटाना होगा
- अगर 100 साल बाद कोई महामारी आती है तो उससे निपटने का प्लान बनाना होगा

चीन ने कोरोना महामारी का ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि उसने लोगों की सेहत के साथ-साथ देश-दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर डाला है। लेकिन भारत को एक अवसर भी मिला है कि वह अपनी श्रमशक्ति के बल पर विश्व की अर्थव्यवस्था का मजबूत केंद्र बन सके। साथ ही भारत को यह भी तैयारी करनी होगी कि अगर 100 साल बाद फिर से कोई ऐसी महामारी फैलती है तो उससे आसानी से निपटा जा सके। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारों को बजट बढ़ाना होगा।

● राजेंद्र आगाल

कोरोना की आड़ में चीन दुनिया का अगला सुपर पावर बनने के लिए अपनी चाल चल चुका है। अमेरिका कराह रहा है। इटली में मातमी चीख है। स्पेन रो रहा है। ब्रिटेन आईसीयू में है। जर्मनी, फ्रांस, ईरान, तुर्की, स्विजरलैंड, नीदरलैंड, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत लगभग दुनियाभर के 190 से ज्यादा देश की एक तिहाई आबादी घरों में कैद है। अजीब कश्मकश है। माथे का तापमान और सांसों की रफ्तार नापी जा रही है। जिन्हें सांस लेने में मुश्किल वो कोरोना के मरीज और जो अब तक कोरोना से बचे हुए हैं, उनकी सांसें फूल रही हैं। जिंदगी ऐसी दांव पर लगी है कि जिंदगी चलाने वाली हर चीज को ठप करना पड़ गया। मगर कोरोना की रफ्तार ऐसी कि दुनियाभर के अस्पतालों से धीरे-धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रही है। वेंटीलेटर कम पड़ते जा रहे हैं। डॉक्टरों को प्रोटेक्ट करने वाले कपड़े नदारद हैं। टेस्ट किट की जबरदस्त कमी है। मास्क और सेनेटाइजर तो पहले से ही गायब हैं।

कोरोना वायरस के इस संक्रमण से विश्वभर में अब तक 2,34,245 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 33,31,040 लोग इससे संक्रमित हैं। भारत में 33,660 लोग संक्रमित हैं और 1134 लोगों की मौत हो चुकी है। यह वायरस दिन पर दिन खतरनाक रूप धारण कर रहा है। जानकारों का कहना है कि चीन ने विश्व की अर्थव्यवस्था को बदहाल करने और अपने आपको सबसे **पावरफुल बनाने** के लिए कोरोना वायरस का इजाद किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो, फ्रेंच नोबल लॉरिएट, एचआईवी के सह-आविष्कारक लॉक मॉन्टेनियर तथा नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट तासुकु होंजो उन कुछ लोगों में से हैं, जिनका मानना है कि चीन ने जान-बूझकर कोविड-19 का वायरस फैलाया है। तासुकु होंजो का दावा है कि चीन ने लैब में कोरोना वायरस बनाया है। उनका कहना है कि जिस लैब में इस वायरस को बनाया गया है उसमें पूर्व में मैं भी काम कर चुका हूं। जिस दौरान यह वायरस बनाया गया, उस दौरान मैंने लैब के टेक्नीशियन्स के साथ संपर्क करने की कोशिश की लेकिन किसी का मोबाइल ऑन नहीं था। लेकिन **चीन है कि वह इस बात** को मानने को तैयार नहीं है। हकीकत जो भी हो लेकिन यह बात तो तय है कि इस वायरस ने पूरे विश्व को तबाह कर दिया है। यहां तक कि अमेरिका की एक कंपनी ने तो चीन पर 20 ट्रिलियन डॉलर का मुकदमा भी ठोक दिया है।

अब तक कोई इलाज नहीं

कोरोना वायरस को लेकर दुनियाभर में फैली दहशत की एक बड़ी वजह यही है कि इसका अब तक कोई इलाज नहीं है। दुनियाभर के वैज्ञानिक अभी भी टीका विकसित करने में जुटे हैं। साथ ही हर्ड इम्युनिटी और एंटी बॉडी से सुरक्षा जैसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। हर्ड इम्युनिटी का मतलब यह है कि जब बहुत बड़ी संख्या में ये संक्रमण लोगों को हो जाएगा, तब उनके शरीर में इसके प्रति प्रतिरक्षण क्षमता स्वत: विकसित हो जाएगी, जैसा कि अनेक वायरस के मामलों में हुआ है। समझ है कि एक बार पीड़ित व्यक्ति के शरीर में संबंधित वायरस से प्रतिरोधी वायरस उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें एंटी बॉडी कहते हैं। मगर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन और दूसरी संस्थाओं के विशेषज्ञों ने एंटी बॉडी परीक्षणों पर भरोसा करने के मामले लेकर सावधान रहने की चेतावनी दी है। उनके मुताबिक इस वायरस के बारे में जो बातें अभी तक मालूम नहीं हुई हैं, उनमें यह भी शामिल है कि इम्युनिटी आखिर कितने समय तक रह सकती है। यानी यह संभव है कि पॉजिटिव आने वाले व्यक्तियों के मामले में एंटी बॉडी क्षमता भी ज्यादा समय तक कारगर नहीं रहेगी। प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ जर्मन लेबोरेटरी डॉक्टर्स (बीडीएल) के विशेषज्ञों का

कहना है कि एंटी बॉडी टेस्ट में गलत नतीजे एक बड़ी समस्या हैं। यानी किसी को कोविड-19 होने के बावजूद भी उसके टेस्ट का नतीजा निगेटिव आ सकता है।

100 से अधिक वैक्सीन पर काम

कोरोना के खिलाफ जंग में दुनियाभर में 100 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 6 टीकों को इंसानों पर परीक्षण करने की अनुमति दी गई है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों के एक समूह ने कोरोना वायरस का एक टीका विकसित किया है। मानव पर परीक्षण किए जाने के चरण में यह टीका सबसे पहले एक सूक्ष्मजीव विज्ञानी को लगाया गया है। इस महत्वपूर्ण परीक्षण के लिए शुरुआती दौर में शामिल किए गए 800 लोगों में सूक्ष्मजीव विज्ञानी एलिसा ग्रांताओ पहली स्वयंसेवी है। भारत में अहमदाबाद में जीडुस केडिला इंटरफेरोम अल्फा-2बी के साथ मिलकर, वहीं अहमदाबाद की ही एक और कंपनी हेस्टर बायोसाइंसेज भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के साथ मिलकर टीका विकसित कर रही है। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट और दिल्ली की भारत बायोटेक भी वैक्सीन डेवलप कर रही है। यह कंपनियां इंटरनेशनल कलैबरेशन के तहत कोरोफ्लू नाम की वैक्सीन के डेवलपमेंट और टेस्टिंग में लगी है। भारत बायोटेक को भी केंद्र सरकार ने फंड दिया है। उधर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि दुनिया में दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र से वैक्सीन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले भारत, इंडोनेशिया और थाइलैंड जैसे देशों को कोविड-19 महामारी से निपटने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। वैश्विक संस्था ने एसईएआर के वैक्सीन (टीका) उत्पादकों और राष्ट्रीय नियामक अधिकरणों से कोविड-19 का टीका विकसित करने के काम में तेजी लाने का अनुरोध भी किया। भारत में एम्स भी वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है। अब देखना यह है कि

कब खत्म होगी महामारी?

कोरोना की महामारी कब खत्म होगी कुछ पता नहीं। अमेरिका की एक खोजी संस्था की राय है कि अभी दुनिया में एक अरब लोगों के संक्रमित होने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामिनाथन का कहना है कि किसी भी महामारी का मुकाबले करने के लिए टीका (वैक्सीन) तैयार करने में प्रायः 10 साल लगते हैं। इबोला का टीका पांच साल में बना था। कोरोना का टीका तैयार करने में दर्जनों वैज्ञानिक लगे हुए हैं, फिर भी उसमें सालभर लग सकता है। यदि यह तथ्य है तो कोरोना का मुकाबला तब तक कैसे किया जाए ? यह भी तथ्य है कि कोरोना के रोगी अच्छी-खासी संख्या में ठीक हो रहे हैं। वे कैसे ठीक हो रहे हैं? उन्हें ठीक करने वाली कोई एक सुनिश्चित दवाई नहीं है। जैसा भी मरीज हो, वैसी ही दवाइयों का संयोग बिठाने की कोशिश की जाती है। लग जाए तो तीर नहीं तो तुक्का! अब अमेरिका के रोग-नियंत्रक विभाग ने कोरोना के नए लक्षणों का बखान कर दिया है। पहले खांसी, बुखार, छींक आदि लक्षण थे, अब इनमें हाथ-पांव कांपना, सिरदर्द, मांसपेशियों में अकड़न, गला रुंधना और स्वाद खत्म होना भी जुड़ गया है। दूसरे शब्दों में अब संक्रमित रोगियों की इतनी भरमार हो सकती है कि भारत और पाकिस्तान जैसे देश भी संकट में फंस सकते हैं, जहां कोरोना का हमला उतना तेज नहीं हुआ है, जितना अमेरिका और यूरोप में हुआ है। हमारे यहां इसकी संख्या शायद इसलिए भी कम दिखाई पड़ती है कि इन देशों की तरह हमारे यहां खुला खाता नहीं है। कई बातें छिपाई जाती हैं और हमारे यहां कोरोना की जांच भी बहुत कम हुई हैं। ऐसी हालत में बड़े पैमाने पर क्या किया जा सकता है। सरकार ने शारीरिक दूरी, मुखपट्टी, घर बंदी आदि का जमकर प्रचार करके ठीक ही किया है लेकिन करोड़ों लोग कोरोना से कैसे लड़ें, अपनी रोकथाम-शक्ति कैसे बढ़ाएं, इस बारे में हमारे नेतागण नौकरशाहों के नौकर बने हुए हैं। उनकी जुबान लड़खड़ाती रहती है। वे करोड़ों लोगों को घरेलू नुस्खे (काढ़ा वगैरह) लेने के लिए क्यों नहीं कहते? हवन-सामग्री के धुएं से संक्रमण को नष्ट क्यों नहीं करवाते?

देशी कंपनियों के रैपिड टेस्टिंग किट का इस्तेमाल क्यों नहीं?

एक तरफ देश स्वदेशी की बात करता है, दूसरी तरफ हर मामले में विदेशों पर भरोसा करता है। ताजा मामला कोराना संक्रमण के इस दौर में देखने को मिला। कोरोना वायरस के टेस्टिंग के लिए सरकार ने चीन से रैपिड टेस्टिंग किट मंगवाया, लेकिन चीन ने अपनी फितरत के अनुसार घटिया किट भारत भेज दिया। हालांकि भारत सरकार ने चीन से आए रैपिड टेस्टिंग किट का ऑर्डर कैंसिल कर उन्हें वापस लेने का निर्देश दे दिया है। साथ ही उनकी दो कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जानकारों का कहना है कि भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं जो रैपिड टेस्टिंग किट बनाती हैं। सरकार ने इन कंपनियों से यह किट क्यों नहीं लिया। जानकार यह भी बताते हैं कि चीन से जो रैपिड टेस्टिंग किट और पीपीई मंगाया गया है उससे आधी से भी अधिक कीमत में भारत में किट उपलब्ध है। अब जब चीन से आया सामान घटिया निकला है तब जाकर भारत सरकार को अपने देश में निर्मित किट की याद आई है। कई प्रदेशों में स्वदेशी किट का इस्तेमाल हो रहा है।

कौन सा देश इस महामारी का टीका बनाने में सफलता प्राप्त करता है।

भारत के लिए बड़ा मौका

दुनिया को अपने सस्ते सामान का मोहताज बनाने वाले चीन की चाल से पर्दा अब उठ चुका है। जहां एक तरफ कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा लिया है, वहीं कोरोना के प्रकोप से पहले चीन दुनिया के सभी बाजारों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। दुनिया की हर बड़ी कंपनी चीन में माल बनाती और बेचती है। मतलब अमेरिका हो या इटली सब चीन पर निर्भर हैं। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि कोरोना संकट को भयानक बनाने में चीन पर निर्भरता का बड़ा योगदान है। कोरोना का यही वो सबसे बड़ा सबक है, जिसे भारत को भी याद रखना होगा। विश्व समुदाय का मानना है कि यह समय भारत के उदय का है। दरअसल, भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी श्रमशक्ति है। भारत में श्रमिक सस्ती दर पर उपलब्ध हैं। ऐसे में भारत अपने यहां निर्माण इकाईयां स्थापित कर उनमें सस्ते सामान का उत्पादन कर विश्व बाजार पर छा सकता है। क्योंकि चीन में अब वह ताकत नहीं रह गई है कि वह सस्ते सामान अधिक दिन तक बना सके। अब वहां मजदूरी काफी बढ़ गई है। वर्ष 1990 में चीन की सालाना मजदूरी 11,475 रुपए थी, जो 2005 में बढ़कर 1 लाख 53 हजार रुपए हो गई। 2015 में 6 लाख 80 हजार रुपए और आज ये बढ़कर तकरीबन 10 लाख 32 हजार रुपए हो चुकी है। यानी पिछले 30 साल में चीन की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का वेतन 8900 प्रतिशत गुना बढ़ चुका है। इस तरह चीन में सामान बनाना अब उतना सस्ता नहीं रह गया है। कोरोना वायरस ने बड़ी-बड़ी कंपनियों को चीन से बाहर देखने का एक और मौका दे दिया है और वो विकल्प की तलाश में हैं। अब सवाल ये है कि चीन से उठकर ये विदेशी कंपनियां किस देश में जाएंगी। किसे इसका फायदा मिलेगा? ऐसे में तीन देशों (वियतनाम, मेक्सिको और भारत) के बीच प्रतियोगिता है। कोरोना वायरस भारत के लिए आपदा तो है ही, लेकिन अवसर भी है। क्योंकि भारत के पास चीन जितना बड़ा बाजार है। उससे कई गुना मैन पावर हैं। भारत को आज रोजगार की सख्त जरूरत है क्योंकि देश 1991 से भी बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।

300 कंपनियां दरवाजे पर

रेटिंग कंपनी नोमुरा की मानें तो कोरोना संक्रमण के बाद एक हजार से अधिक कंपनियां चीन को अलविदा करने की तैयारी कर चुकी हैं। उनमें से करीब 300 भारत में स्थापित होना चाहती हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कंपनियों से कहा है कि वे भारत का रुख करें। हालांकि आश्चर्यजनक यह है कि अभी तक जिन 56 कंपनियों ने चीन से मुंह मोड़ा है, उनमें से महज 3 कंपनियां ही भारत में अपने लिए जगह तलाश पाई हैं। 26 कंपनियां वियतनाम चली गई तो 11 कंपनियों ने ताइवान को अपना केंद्र बना लिया। 8 कंपनियों ने थाईलैंड में अपना केंद्र बनाया। रेटिंग कंपनी नोमुरा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि एक तरफ चीन में मजदूरी की बढ़ती लागत है तो दूसरी ओर शी जिनपिंग सरकार का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। इससे यह कंपनियां अपने लिए बेहतर विकल्प तलाश रही हैं। इसी वजह से इन्होंने चीन से बाहर जाने का फैसला किया है। इसके अलावा चीन से कोविड-19 के आउटब्रेक के कारण भी कंपनियां भारत या दक्षिण एशियाई देशों में जाने के लिए सोच रही हैं। भारत को उम्मीद थी कि और कम मजदूरी की दर से यह कंपनियां यहां आएंगी, पर ऐसा नहीं हो पाया।

भारत में कई समस्याएं

भारत में कंपनियां स्थापित करना टेढ़ी खीर होता है। भारत में यदि सरकार ने प्रोजेक्ट को क्लीयर कर भी दिया तो कंपनियों को फैक्टरी की जमीनों के लिए किसानों के साथ डील करनी पड़ती है। फिर उसे नौकरशाही के लंबे प्रावधानों से भी गुजरना होता है। इसके बाद लोकल माफिया का भी सामना करना पड़ता है। माफिया से जुड़े एनजीओ और लोकल ट्रेड यूनियन के अलावा लेबर लॉ से भी इन कंपनीज को दो चार होना पड़ता है। हालांकि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार लेबल लॉ और अन्य मुद्दों को सुलझाने में लगी है, लेकिन अदालतों में इसके खिलाफ लंबे केस भी हैं। इससे इसमें बाधा आ रही है। अगर मोदी सरकार इस गोल्डन अवसर को छोड़ना नहीं चाहती है तो इन मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाना होगा।

नीति बदलनी होगी

भारत अपनी जिस श्रमशक्ति के बलबूते चीन को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है उस श्रमशक्ति को यहां की सरकारों और राजनीतिक दलों ने मुफ्त की रोटी तोड़ने का आदी बना दिया है। कोरोना वायरस के इस संक्रमणकाल में ही यह देखने को मिल रहा है कि लोग मुफ्त का भोजन और राशन लेने के लिए लंबी-लंबी कतार लगाए रहते हैं। जब कि यह मुफ्तखोरी की आदत नहीं छूटेगी या छुड़ाई जाएगी तब तक भारत चीन को टक्कर देने लायक नहीं बनेगा। इसलिए सरकार को सबसे पहले नीति बदलनी होगी कि किसी को भी मुफ्त में कोई चीज नहीं दी जाएगी।

हुजूर! बहुत देर कर दी लॉकडाउन में

विश्व में सबसे खराब स्वास्थ्य सुविधाओं वाले भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। जो देश अपने बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दम भरते थे, आज उनके यहां सर्वाधिक मौते हो रही हैं। जबकि भारत में स्थिति कंट्रोल में है। इसके पीछे मुख्य तीन वजह बताई जा रही है। पहली लॉकडाउन, दूसरी यहां के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और तीसरी यहां की अधिकांश आबादी का युवा होना। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार ने समय पर लॉकडाउन कर दिया होता तो आज स्थिति इतनी खराब नहीं होती।

दरअसल, जिस समय देश में कोरोना वायरस का संक्रमण पैर पसार रहा था उसी समय मप्र में सत्ता हथियाने का भी षड्यंत्र चल रहा था। केंद्र की भाजपा सरकार ने भले ही सभी राज्यों को एहतियात बरतने का निर्देश दिया था लेकिन लॉकडाउन जैसी कोई अन्य तैयारी नहीं की जा रही थी। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आरोप है कि उस समय केंद्र की सरकार और मप्र भाजपा के नेता जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस सरकार को गिराने में लगे हुए थे। इस कारण लॉकडाउन देर से किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मप्र में संक्रमितों का आंकड़ा 2660 और मौत का आंकड़ा 137 तक पहुंच गया है। वह कहते हैं कि अगर समय पर केंद्र सरकार लॉकडाउन करती तो यह स्थिति नहीं बनती।

मप्र में कैसे बिगड़े हालात

मप्र में कोरोना वायरस के चलते 137 लोग जान गंवा चुके हैं। वह देश के उन राज्यों में तीसरे नंबर पर है, जहां कोविड-19 ने 100 से अधिक लोगों की जान ली है। आखिर जिस प्रदेश ने कोविड-19 के महामारी घोषित होने से पहले ही इससे बचाव की तैयारियां शुरू कर दी थीं, वह इस लड़ाई में कैसे पिछड़ गया। इसका जवाब प्रदेश में छिड़े सत्ता संघर्ष में दिखता है। भारत में कोरोना वायरस का पहला केस 30 जनवरी को आया। इसके बाद देश में कोरोना से लड़ने के लिए तेजी से निर्णय लिए गए। लेकिन मप्र पहले से सतर्क था। स्वास्थ्य विभाग ने 25 जनवरी को प्रदेश के सभी अस्पतालों को इससे जुड़े दिशा-निर्देश भेजे थे। तीन दिन बाद विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे जिले में टास्क फोर्स बनाएं और चीन से लौटने वालों के लिए आइसोलेशन वार्ड भी बनाएं। 31 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को महामारी घोषित किया। इसके बाद प्रदेश सरकार ने तय किया कि 15 जनवरी के बाद चीन से लौटे हर व्यक्ति का कोविड-19 टेस्ट कराया जाएगा। आज की तारीख में मप्र में 2660 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इंदौर, भोपाल और उज्जैन प्रदेश ही नहीं, देश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हैं। साफ लग रहा है कि जिस प्रदेश ने कोरोना से लड़ाई में अच्छी शुरुआत की थी, वह सत्ता संघर्ष में ऐसा उलझा कि उसे राजनीति के चक्कर में यह याद ही नहीं रहा कि सामने कोई बड़ा संकट खड़ा है। अब कांग्रेस कह रही है कि भाजपा की दिलचस्पी तो सिर्फ सरकार गिराने में थी, कोरोना संकट का तो अहसास ही नहीं था। दूसरी ओर, भाजपा कह रही है कि जब उसने सत्ता संभाली, तब अस्पतालों की हालत खराब थी।

सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देश

देश	कितने संक्रमित	कितनी मौतें	कितने ठीक हुए
अमेरिका	10,64,194	61,656	1,47,411
स्पेन	2,36,899	24,275	1,32,929
इटली	2,03,591	27,682	71,252
फ्रांस	1,66,420	24,087	48,228
ब्रिटेन	165,221	26,097	उपलब्ध नहीं
जर्मनी	1,61,539	6,467	1,20,400
तुर्की	1,17,589	3,081	44,022
रूस	99,399	972	10,286
ईरान	93,657	5,957	73,791
चीन	82,862	4,633	77,610

प्रभावित 10 शहर

शहर	कितने संक्रमित
मुंबई	5776
दिल्ली	3314
अहमदाबाद	2542
इंदौर	1372
पुणे	1099
जयपुर	859
थाणे	752
चेन्नई	678
सूरत	570
हैदराबाद	548

लेख लिखे जाने (30 अप्रैल) तक

कहां हैं प्राइवेट अस्पतालों की वकालत करने वाले लोग?

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी ने भारतीय चिकित्सा सेवाओं की कमजोरियां उजागर की हैं। खासकर, सरकारी और प्राइवेट हेल्थ सिस्टम के बीच के विरोधाभास की तो इसने अच्छे से कलई खोली है। पहले से स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी का सामना कर रहे सरकारी हेल्थकेयर सिस्टम के समक्ष जैसे ही कोरोना संकट से लड़ने की चुनौती आई, वैसे ही प्राइवेट हेल्थकेयर सेवाओं की वकालत करने वाले मूकदर्शक बन गए या फिर एक बैलआउट पैकेज की मांग में जुट गए। ऐसे समय जब अस्पतालों द्वारा मरीजों को या तो भर्ती करने से इंकार किया जा रहा है, या फिर उनसे कोविड-19 से मुक्त होने का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दावा है कि प्राइवेट हेल्थकेयर सेक्टर को सरकार से तरलता यानी पैसे चाहिए। इसके अलावा, उसे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करों से राहत के साथ ही कॉस्ट सब्सिडी भी चाहिए। कॉस्ट सब्सिडी का मतलब यह है कि हेल्थकेयर से जुड़ी चीजों की उत्पादन लागत का एक हिस्सा सरकार वहन करे। यह विडंबना ही है कि संगठन ने यह भी कहा है कि इस महामारी के कारण प्राइवेट हेल्थकेयर सिस्टम की सेहत पर बुरा असर हुआ है।

पूरी तैयारी पटरी से उतर गई

प्रदेश में कोरोना का इतने बड़े स्तर पर संक्रमण फैलने के विषय में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कहते हैं कि शुरुआती प्रयास के बाद गाड़ी पटरी से उतर गई है। वह कहते हैं कि हमने जनवरी से उन लोगों की तलाश शुरू कर दी थी, जो चीन से लौटे थे। स्वास्थ्य विभाग ने फरवरी में ही दर्जनों ऐसे नोट भेजे थे। हमने कोरोना से लड़ाई की तैयारी तभी कर ली थी, जब यह खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंचा था। तीन मार्च को तत्कालीन मुख्य सचिव सुधी रंजन मोहंती ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। उनसे कहा गया था कि विदेश से लौटने वाले सभी लोगों का मेडिकल चेकअप किया जाए। लेकिन इसके बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच सरकार गिराने और बचाने की लड़ाई शुरू हो गई। कमलनाथ सरकार खुद को बचाने में लग गई। उसके स्वास्थ्य मंत्री ने तब कहा था कि प्रदेश में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। इससे राजनीतिक दलों ने कोरोना को हल्के में ले लिया।

कमलनाथ सरकार में तब तुलसीराम सिलावट स्वास्थ्य मंत्री थे, जो अब भाजपा की शिवराज सरकार में जल संसाधन मंत्री बन चुके हैं। वे 6 मार्च को कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हुए थे। इसके बाद प्रदेश में होली नहीं मनाने के

निर्देश जारी हुए थे। सभी स्कूल-कॉलेज, मॉल्स बंद कर दिए गए थे। लेकिन सभी जानते हैं कि इसके बाद मप्र में कोरोना से नहीं, बल्कि सत्ता की लड़ाई लड़ी गई। 14 मार्च को इंदौर में रंगपंचमी का त्योहार जोर-शोर से मनाया गया। तब कांग्रेस के कोरोना संकट का जिक्र करने पर शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा नेता मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि यह 'कोरोना नहीं, डरोना' है। माना जाता है कि कोरोना वायरस 14 से 24 मार्च के बीच प्रदेश में तेजी से फैला। यह वही वक्त था, जब प्रदेश में सरकार होते हुए भी व्यवस्था शायद ही थी। 20 जनवरी को कमलनाथ सरकार गिर गई और इसी दिन जबलपुर में कोरोना का पहला केस सामने आया। प्रदेश में कोरोना का पहला मामला सामने आने के 15 दिन बाद तक इससे बचाव के ज्यादा प्रयास देखने को नहीं मिले। एक अधिकारी कहते हैं, 'शिवराज सरकार ने शुरुआती 15 दिन लगभग गंवा दिए क्योंकि इस वक्त कोई स्पष्ट निर्देश नहीं थे।' शिवराज ने 23 मार्च को शपथ ली थी। करीब एक महीने तक वे प्रदेश में अकेले मंत्री रहे। आज भी उनकी कैबिनेट में पांच मंत्री ही हैं। शिवराज सरकार का शुरुआती समय ब्यूरोक्रेसी में बदलाव करने में बीता। एक अधिकारी ने कहा, 'ऐसे समय में तीन-चार टीमें होनी चाहिए। लेकिन यहां तो एक ही टीम हर तरह की निगरानी कर रही थी। यहां कोई हेल्थ मिनिस्टर नहीं था। कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं था। कोई हेल्थ डायरेक्टर नहीं था।'

जांच रिपोर्ट में देरी

मप्र सहित देशभर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की एक वजह जांच किट की कमी रही है। दरअसल, किट की कमी के कारण ज्यादा संख्या में लोगों के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं इसलिए कोरोना वायरस संक्रमितों की वास्तविक संख्या नहीं पता चल पा रही है। इसके लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) जिम्मेदार है। राज्य सरकारों का भी यही कहना है कि उनके पास पर्याप्त जांच किट नहीं हैं। जानकारों का कहना है कि आईसीएमआर ने समय पर कोई तैयारी नहीं की थी। दरअसल, आईसीएमआर इस वायरस की गंभीरता को भांप नहीं पाया। उसने राज्यों को जांच किट मुहैया नहीं कराई। जबकि उसे मालूम था कि संक्रमण बढ़ेगा तो हजारों-लाखों केस सामने आएंगे। फिर भी उसने टेस्ट की व्यवस्था नहीं की। जब मामले बढ़ने लगे तो वह थोड़ा चेता और टेस्ट लैब की क्षमता बढ़ाई।

अगर मप्र की बात करें तो शुरुआती समय में **मप्र में रोजाना 500 टेस्ट ही हो पा रहे थे।** स्थिति बिगड़ने पर आईसीएमआर ने व्यवस्था की और अभी भी 2 से 3 हजार टेस्ट ही हो पा रहे हैं। जबकि आवश्यकता इससे कई गुना टेस्ट की है। यही नहीं प्रदेश में वर्तमान समय में आरटीपीसीआर तकनीक से जांच हो रही है। इस तकनीक से जांच काफी महंगी और देर से होती है। इस तकनीक से 40 से 50 बैच की रिपोर्ट 8 से 10 घंटे में आती है और 1 रिपोर्ट की जांच में दो से ढाई हजार रुपए की लागत आती है। वहीं रैपिड टेस्टिंग किट से जांच 10 से 20 मिनट में हो जाती है और एक जांच पर दो से ढाई सौ रुपए खर्च होते हैं।

अर्थव्यवस्था की चुनौती

लॉकडाउन के कारण देश सहित मप्र में सारे उद्योग और निर्माण कार्य ठप हो गए हैं। हालांकि धीरे-धीरे उद्योग शुरू हो रहे हैं। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए सरकार ने कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल, सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की सबसे बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजाना अफसरों के साथ मिलकर इस पर मंथन कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्योगों को केंद्र सरकार के नियमों का पालन करते हुए चालू करने का निर्देश दे दिया गया है। प्रदेशभर में करीब 40 फीसदी उद्योग धंधे शुरू हो गए हैं। वहीं 38 दिनों से बंद पड़े वल्लभ भवन, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के दफ्तरों को 30 फीसदी कर्मचारियों के साथ 30 अप्रैल से शुरू कर दिया गया है।

आपदा को अवसर में बदलने का निर्देश

उधर, मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आपदा से लोगों को राहत दिलाने के लिए कमर कस ली है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस आपदा को अवसर में बदलने का मौका है। इसलिए इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चीन में मौजूद विदेशी कंपनियां अपना कारोबार समेट रही हैं। ऐसे में हम प्रयास करेंगे कि कंपनियां बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश आएं। यहां निवेश के लिए अनुकूल माहौल हैं और हमने नीतियां भी निवेश आधार की बनाई हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि देश के युवाओं को नौकरी के लिए तैयार रहना होगा। कोरोना संक्रमण से निपटने के बाद चीन से कारोबार समेटकर कई बड़ी कंपनियां भारत आएंगी, क्योंकि चीन के बाद भारत ही बड़ा बाजार है और इससे लाखों युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिलेगा।

प्रकृति का बदला!

कोरोना वायरस को प्रकृति का बदला भी माना जा रहा है। दरअसल, हम अपने विकास और सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति का लगातार शोषण कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह प्रदूषण तेजी से कम हुआ है उससे यह संकेत मिले हैं कि हम मानव अपना लालच त्याग दें, तो मां स्वरूप पृथ्वी कैसे अपना श्रृंगार कर सकती है, जो कि हमारे लिए ही हितकारी है। हालांकि देश में आजादी के बाद से ही स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। लेकिन इन 6 सालों में स्वच्छता की जगह गंदगी, अंधेरा और पेयजल की समस्या हमारे सामने खड़ी होती रही। प्यास लगने पर कुआं खोदने की अपनी आदत के तहत अब सरकारों ने गुटखा पर प्रतिबंध लगाया है और थूकने पर जुर्माना लगाने की घोषणा दी है। जबकि पश्चिमी देशों में लोग स्वभावत: न तो गुटखा खाते हैं और न ही इधर-उधर थूकते हैं। दरअसल, सरकार केवल कायदे-कानून बनाने में विश्वास करती है। उसका न तो पालन किया जाता है और न ही कराया जाता है। ऐसे में हम अपने आसपास को स्वच्छ कैसे रख पाएंगे। फिर हम गंदगी करेंगे और कोई न कोई नया वायरस हमारी जान लेने के लिए उत्पन्न होगा।

सयाने सेल्समैन

राहुल गांधी जैसी गलतियां कैसे करने लगे केजरीवाल

ऐसा बार-बार क्यों लगता है जैसे भाजपा को शिकस्त देने के चक्कर में जैसी गलतियां कांग्रेस नेता राहुल गांधी करते गए, अरविंद केजरीवाल भी उसी रास्ते पर चलते हुए लड़खड़ाने लगे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दोबारा सत्ता हासिल कर खुद को साबित किया है तो राहुल गांधी ने भी 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस को उप्र की 12 सीटें एक्स्ट्रा दिलाकर वाहवाही तो लूटी ही थी और 9 साल बाद एक साथ राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी को सत्ता में लाकर तारीफ बटोरी ही ली थी, राष्ट्रीय स्तर पर वो फेल हो गए अलग बात है। वैसे तो केजरीवाल भी दिल्ली के बाहर कोई चमत्कार ही नहीं दिखा पाए। केजरीवाल की राहुल गांधी की तुलना यहां इसलिए प्रासंगिक हो जा रही है क्योंकि भाजपा के खिलाफ अपनी राजनीति चमकाने के लिए दोनों ही नेताओं ने एक ही तरह के प्रयोग किए हैं। पहले राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग किया और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले से थोड़ा परहेज। अरविंद केजरीवाल ने भी हनुमान चालीसा से आगे बढ़कर घर में गीता पाठ कराने लगे हैं। फर्क बस ये है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को कुछ दिन सम्मान देते हैं, लेकिन फिर भूकंप लाने के चक्कर में कुछ न कुछ ऐसा बोल ही देते हैं कि बवाल शुरू हो जाता है। केजरीवाल कम से कम इस मामले में लगातार चुप्पी साधे हुए हैं।

गलत सौदे करने वालों की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो पहले सामने वाले को उसका फायदा समझाते हैं। वो ये नहीं बताते कि उनका अपना क्या स्वार्थ है। इसी फायदे के लालच में आकर लोग ठगी के शिकार होते हैं। दिल्ली और अरविंद केजरीवाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल, केजरीवाल की खासियत यह है कि वे अपनी गलती को भी इतने बेहतर तरीके से पेश करते हैं जिससे लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब कोरोना वायरस के संक्रमण को ही ले लें। देश में यह वायरस सबसे अधिक **जमातियों** के कारण ही फैला है। लेकिन केजरीवाल अपनी गलती को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि में तब्दील कर जनता को यह बताने में जुटे हुए हैं कि वायरस को रोकने के लिए उनकी सरकार ने कितने कठोर और सार्थक कदम उठाते हैं। हालांकि वहां भी गलतियां ही गलतियां हुई हैं।

कोरोना संकट के वक्त अरविंद केजरीवाल की सक्रियता कदम-कदम पर बोल रही है, लेकिन सियासत खामोश हो गई लगती है। पहले दिल्ली दंगों को लेकर, फिर लॉकडाउन के दौरान पूर्वांचल के लोगों के पलायन को लेकर और अब **तब्लीगी जमात** के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि केजरीवाल के पास पूछने के लिए सवाल नहीं बचे हैं। तब्लीगी जमात के मामले में अजीत डोभाल की दखल से साफ है कि केंद्र में सत्ताधारी भाजपा कैसे खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही होगी, लेकिन राजनीति तो यही होती है कि कैसे विरोधी को ही घसीटकर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाए। तब्लीगी जमात के आयोजन के लिए सवाल तो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने वाली दिल्ली पुलिस से भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवालों पर केजरीवाल को सफाई देते नहीं बन रहा है। ऐसा लगता है जैसे भाजपा ने केजरीवाल को चारों तरफ से घेर लिया हो और उनको निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा हो। फिर भी केजरीवाल के मुंह से भाजपा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं निकल रहा है।

अरविंद केजरीवाल कहते हैं- 'अर्जुन की आंख की तरह इस समय सिर्फ देश को बचाना है। कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है।' खुद तो खामोशी बरत ही रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी केजरीवाल यही अपील कर रहे हैं वे भी चुप रहे और ऐसा कोई राजनीतिक बयान न दें जिससे बवाल मचने लगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरी एक ही खबर है, लेकिन फिलहाल वो उनके किसी काम नहीं आने वाली है। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास ले देकर आखिरी रास्ता बचता था- ऑड और ईवन, लेकिन रिपोर्ट आई है कि राजधानी की हवा पांच साल पहले जितनी साफ हो चुकी है। ऐसा बारिश के चलते हुआ है क्योंकि मार्च में 109.6 एमएम बारिश हुई थी और ये 1901 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा है। लेकिन ये साफ सुथरी हवा और ये बारिश फिलहाल अरविंद केजरीवाल के किसी भी काम नहीं आ रही है। दिल्ली में हुए दंगे हों, हाल फिलहाल पूर्वांचल के मजदूरों के पलायन का मुद्दा हो या फिर अभी-अभी निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के **मरकज में मजहबी जमावड़ा,** अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साधे हुए राजनीति करने की कोशिश की है। तीनों ही मामलों में अरविंद केजरीवाल को लगा होगा कि उनके चुपचाप बैठ जाने पर भाजपा ही फंसेगी, क्योंकि केंद्र के साथ-साथ उप्र में भाजपा की सरकार है और बिहार की सरकार में वो साझीदार है। दिहाड़ी मजदूरों के पलायन को लेकर अरविंद केजरीवाल उप्र की योगी आदित्यनाथ सरकार और बिहार की नीतीश कुमार सरकार के मंत्रियों के निशाने पर रहे। दोनों ही सरकारों के मंत्रियों ने केजरीवाल पर पूर्वांचल के लोगों के बिजली-पानी के कनेक्शन तक काट डालने के आरोप लगाए और केजरीवाल ये समझाने में भी नाकाम रहे कि क्यों लोगों को डीटीसी की बसें आनंद विहार से लेकर हापुड़ तक पहुंचाती रहीं।

अरविंद केजरीवाल लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की दुहाई देते फिर रहे थे, लेकिन जब पूरा देश घरों में बंद है और कैबिनेट की मीटिंग तक में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, फिर निजामुद्दीन में तीन दिन तक तब्लीगी जमात का जमावड़ा कैसे चलता रहा? मरकज में जमात के लोगों के जुटने के बाद भी न तो दिल्ली पुलिस हरकत में आई और न ही केजरीवाल सरकार के अफसर। अर्जुन की तरह धैर्य और धर्म के भरोसे अरविंद केजरीवाल भले ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीत चुके हों, लेकिन उसके बाद से दिल्ली की राजनीति में कदम-कदम पर उनकी राजनीतिक समझ अभिमन्यु जैसी ही नजर आ रही है। लगता है अरविंद केजरीवाल ऐसी उलझन में फंसे हैं जिसमें वो न तो धर्म निरपेक्षता को छोड़ना चाहते हैं और न ही हिंदुत्व का चोला ठीक से ओढ़ पा रहे हैं। दिल्ली दंगों से लेकर तब्लीगी जमात तक दोनों ही मामलों में यही उलझन केजरीवाल एंड कंपनी को ले डूबी है।

● **अक्स ब्यूरो**

कुछ तो बात जरूर है

ऐसा लगता है देश के सबसे पुराने और शक्तिशाली राजनीतिक कुनबे में भी वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। जिस तरह के नजारे दिख रहे हैं, उससे यही लगता है कि प्रियंका गांधी की सक्रियता किसी को पसंद नहीं है।

कांग्रेस में सोनिया गांधी की मंजूरी से राहुल गांधी की अगुवाई में एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई है। राहुल गांधी की अगुवाई इसलिए भी क्योंकि लिस्ट में सबसे ऊपर उनका ही नाम नजर आ रहा है। वैसे तकनीकी तौर पर राहुल गांधी का नाम मनमोहन सिंह के ठीक बाद है, हालांकि, वो कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला संयोजक। कंसल्टेटिव कमेटी में प्रियंका गांधी वाड्रा की गैरमौजूदगी खासतौर पर ध्यान खींच रही है। अहमद पटेल, एके एंटनी और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता भी सूची से नदारद हैं। बाकी नेताओं के न होने को तो राहुल गांधी की पंसद-नापसंद से जोड़कर देखा और समझा जा सकता है, लेकिन उनकी बहन प्रियंका गांधी का नाम सूची से बाहर होना काफी अजीब लगता है। ऐसे में जबकि प्रियंका गांधी कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान खासी एक्टिव देखी जा रही हैं, **कंसल्टेटिव कमेटी** से उनका नाम बाहर होने की असली वजह क्या हो सकती है। आइए कुछ कड़ियों को जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं।

किसी क्रिकेट टीम की तरह कंसल्टेटिव कमेटी में कुल 11 कांग्रेस नेताओं को शामिल किया गया है। क्रिकेट टीम में 12वां खिलाड़ी भी होता है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां भी जगह नहीं मिल सकी है। हैरानी इसलिए भी हो रही है कि सुप्रिया श्रीनेत, रोहन गुप्ता और गौरव वल्लभ जैसे नए चेहरों को भी कंसल्टेटिव कमेटी में शामिल किया गया है, लेकिन गाजे-बाजे के साथ 2019 के आम चुनाव से पहले **औपचारिक तौर** पर लाए गए कांग्रेस महासचिव को इस लायक नहीं समझा गया है और यही फिलहाल सबसे बड़ी मिस्ट्री साबित हो रही है।

हाल फिलहाल देखने को मिला है, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार किसी न किसी को पत्र लिख रही हैं। योगी आदित्यनाथ से लेकर मुकेश अंबानी तक, प्रियंका गांधी अलग-अलग तरीके से पत्र लिखकर सबसे कोरोना वायरस से जंग में सुझाव, सलाह और गरीब-मजदूरों के हित में अपील कर रही हैं। और तकरीबन ऐसा ही सोनिया गांधी भी कर रही हैं और राहुल गांधी भी। फिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि प्रियंका गांधी को उस कमेटी से बाहर रखा गया जिसकी रोजाना मीटिंग होनी है, वर्चुअल ही सही। कमेटी को कोरोना वायरस की चुनौतियों और बाकी जरूरी मुद्दों पर सलाह देनी है। ताज्जुब होता है जो नेता कोरोना को लेकर पार्टी में इस कदर एक्टिव है उसकी कोई राय ही नहीं ली जा रही है।

पार्टी में आम कार्यकर्ता आज सवाल कर रहा है कि प्रियंका चूक रही हैं या कांग्रेस नेतृत्व की उलझन है? प्रियंका गांधी ने बड़े स्तर पर कोरोना वायरस से संक्रमण को लेकर टेस्टिंग की मांग की है। ये तो वही मांग है जिसकी सलाह राहुल गांधी केंद्र सरकार को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला। लॉकडाउन खत्म होते ही नंबर बढ़ जाएंगे। क्या कंसल्टेटिव कमेटी में ऐसी बातों को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा की कमी नहीं महसूस की जाएगी। प्रियंका गांधी ने लॉकडाउन के दौरान रेलवे टिकिटों की बुकिंग पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने ट्वीट कर पूछा था कि बुकिंग क्यों जारी थी? केंद्र से प्रियंका गांधी ने जांच की भी मांग की थी। प्रियंका गांधी रह-रहकर उत्तर प्रदेश से जुड़े कई मसलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखती रही हैं। कोरोना संकट के मद्देनजर प्रियंका गांधी ने आर्थिक उपायों के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की सलाह दी है। प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ से किसानों, मजदूरों और मनरेगा कामगारों की मुश्किलें लॉकडाउन के वक्त कम करने की कोशिश करने की भी मांग की है।

प्रियंका गांधी ने धर्मगुरुओं को भी पत्र लिखकर अपील की थी कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर लोगों को जागरूक करें कि वे कोरोना से बचाव के उपायों पर अमल करें। याद कीजिए उद्धव ठाकरे की सलाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्रियों को ये सलाह दी थी और बाद में देखा गया कि किस तरह योगी आदित्यनाथ और उनके अफसर पूरे राज्य में धर्मगुरुओं से मुलाकात कर लॉकडाउन और कोरोना से बचाव के उपायों को समझाने की बात कर रहे हैं। अंबानी और अडानी हमेशा ही राहुल गांधी के निशाने पर रहे हैं और उसी कारण वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूट-बूट की सरकार कहकर टारगेट करते रहते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने मुकेश अंबानी को पत्र लिखा और ट्विटर पर शेयर भी किया था। पत्र में प्रियंका गांधी ने मुकेश अंबानी से जियो फोन की वैलिडिटी बढ़ाने की अपील की थी ताकि गरीब और **दिहाड़ी मजदूर पलायन** के दौर में आपस में घर परिवार से बात करना चाहें तो दिक्कत न हो। प्रियंका गांधी ने ऐसे ही पत्र वोडाफोन, एयरटेल और बीएसएनएल के प्रमुखों को भी लिखा था। प्रियंका गांधी के पत्र लिखने के बाद ऐसा लगा था जैसे कांग्रेस ऐसी चीजों के लिए कोई नरम दल तैयार कर रही हो। कहीं

लोकप्रियता में सबसे आगे

देश में कांग्रेस भले ही रसातल की ओर जा रही है लेकिन प्रियंका गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। खासकर उप्र में तो वे सरकार को घेरने के लिए कोई भी मौका नहीं चूकती हैं। आलम यह है कि विषम परिस्थिति में भी वे लोगों के बीच पहुंचकर उनकी सहानुभूति पा रही हैं। वर्तमान समय में वे देश की सबसे लोकप्रिय महिला नेत्री बनी हुई हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन वे केंद्र और राज्य सरकार पर वार नहीं करती हों। यही नहीं उन्होंने कांग्रेस में भी अपने प्रशंसकों की बड़ी फौज तैयार कर ली है। प्रियंका की यही लोकप्रियता शायद उनके घर को पसंद नहीं आ रही है।

टास्क फोर्स में मध्यप्रदेश के नेता को नहीं मिली जगह

कोरोना वायरस को लेकर देश में बने हालातों पर नजर रखने और कांग्रेस की रणनीति तय करने के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक उच्च स्तरीय परामर्श समूह का गठन किया है। इसमें पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। दिल्ली के अलावा कई राज्यों के नेताओं को परामर्श समूह में जगह दी गई है। इस समूह के जरिए कांग्रेस पार्टी कोरोना से बने देश के हालातों को लेकर पार्टी की रणनीति तय करेगी। लेकिन सोनिया गांधी के उच्च स्तरीय परामर्श समूह में मध्यप्रदेश के नेताओं को जगह नहीं मिल पाई है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, विवेक तन्खा जैसे नेता समूह का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। प्रदेश में सरकार गंवाने के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की पार्टी में अनदेखी अब प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है। अब तक कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़ी समितियों में प्रदेश के पार्टी नेताओं को जगह मिलती रही है। इससे पहले कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कई अहम समितियों में शामिल किया गया था। कांग्रेस पार्टी की नेता मीनाक्षी नटराजन को भी इस बार समूह में जगह नहीं मिल पाई है। यह अब चर्चा का विषय जरूर बन गया है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह को भी उच्च स्तरीय परामर्श समूह का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया है?

ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस नेतृत्व को प्रियंका गांधी की ये पहल नागवार गुजरी हो और उनको कंसल्टेटिव कमेटी से बाहर रखे जाने की ये बड़ी वजह बनी हो?

2019 में आम चुनाव के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची आई तो प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम गायब था। प्रियंका गांधी का नाम गायब रहने की खूब चर्चा रही क्योंकि ऐसे कई उम्मीदवार थे जो प्रियंका गांधी को कैंपेन के लिए बुलाना चाहते थे। जहां तक सूची में नाम की बात है तो प्रियंका गांधी का नाम महाराष्ट्र और हरियाणा के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल था, लेकिन वो एक भी रैली करने नहीं गईं। सिर्फ राहुल गांधी ही रैलियां करते रहे। तब तो राहुल गांधी को विदेश दौरे से प्रचार के लिए बुलाया गया था। बहरहाल, राहुल गांधी ने वो रैली भी की जो सोनिया गांधी करने वाली थीं, लेकिन अंतिम वक्त में उनका कार्यक्रम रद्द हो गया।

महाराष्ट्र और हरियाणा में प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार न करने को लेकर बताया गया कि चूंकि वो उत्तर प्रदेश में 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही हैं, इसलिए वो दूसरे राज्यों के चुनावों के लिए समय नहीं दे पा रही हैं। महाराष्ट्र को लेकर तो नहीं, लेकिन हरियाणा के मामले में माना गया कि रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों को लेकर भाजपा मुद्दा बना सकती थी, इसी वजह से प्रियंका गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से दूरी बनाने की कोशिश की होगी। झारखंड के स्टार प्रचारकों की दूसरी सूची में तो प्रियंका गांधी का नाम आ गया था, लेकिन वो कैंपेन के लिए तब पहुंची जब राहुल गांधी के एक बयान पर बवाल हो गया। तब राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया की तर्ज पर **रेप इन इंडिया कहकर** बवाल करा दिया था। फिर प्रियंका गांधी ने झारखंड के पाकुड़ में एक रैली की थी, इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी के बाहर जाने का कार्यक्रम बन गया था।

अब अगर उप्र पर फोकस कर रही थीं तो प्रियंका गांधी ने झारखंड में चुनाव प्रचार क्यों किया और फिर दिल्ली में भी तो राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार किया ही। दिल्ली चुनाव में तो ऐसा लगा जैसे भाई-बहन ने योगी और मोदी में से एक-एक को अपने-अपने हिस्से में बांट रखा हो। प्रियंका गांधी हर रैली में योगी आदित्यनाथ को टारगेट करती रहीं और राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी रहे। दिल्ली चुनाव के दौरान ही तो राहुल गांधी का डंडा-मार बयान चर्चित हुआ था। सवाल ये है कि अगली बार कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी को लेकर सवाल पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे?

अगर फिर से यही समझाया जाए कि प्रियंका गांधी उप्र पर फोकस कर रही हैं तो सवाल है कि क्या उप्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य में काम करने वाले की कांग्रेस की कोर टीम में जरूरत नहीं महसूस की जा रही है, वो भी तब जबकि कोरोना संकट के वक्त भाजपा के सारे मुख्यमंत्रियों में योगी आदित्यनाथ ही सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। बताते हैं कि कोरोना वायरस के दौर में प्रियंका गांधी ने उप्र के लिए खास तैयारी की हुई है। प्रियंका गांधी ने एक व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया है जिसका नाम 'कांग्रेस फाइट्स कोरोना' है। ये ग्रुप उप्र पर ही फोकस है और इसमें राज्य के सभी कांग्रेस पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष जुड़े हुए हैं। इसी ग्रुप में प्रियंका गांधी का ध्यान आजमगढ़ की ओर दिलाया गया कि वहां मदद की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने वहां एक ट्रक अनाज भिजवाया और साफ-साफ निर्देश दिया कि इसे उन जरूरतमंद लोगों को दिया जाए जिन तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही हो।

जरा गौर कीजिए। आजमगढ़ लोकसभा सीट का फिलहाल अखिलेश यादव प्रतिनिधित्व करते हैं और वो उप्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एक साथ और एक तीर से दो-दो विरोधी नेताओं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने वाली प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस क्या अनदेखी नहीं कर रही है? सिर्फ यही नहीं प्रियंका गांधी छोटी-छोटी चीजों पर भी ध्यान दे रही हैं, ताकि कांग्रेस को प्रदेश में खड़ा किया जा सके। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके इलाहाबाद की चमन रावत के जज्बे को सलाम किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता चमन रावत कोरोना से जंग के लिए घर पर मास्क तैयार कर रही हैं। फर्ज कीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा नहीं ज्वाइन किए होते तो क्या कंसल्टेटिव कमेटी में उनको भी जगह नहीं मिलती। खासकर तब जबकि रणदीप सुरजेवाला, मनीष तिवारी और केसी वेणुगोपाल जैसे नेता मौजूद हैं?

पूरी संभावना होती कि ज्योतिरादित्य सिंधिया निश्चित तौर पर कंसल्टेटिव कमेटी का हिस्सा होते। इसलिए भी क्योंकि ये टीम पूरी तरह राहुल गांधी के मनमाफिक बनाई गई है और ऐसे में कमलनाथ की दखलंदाजी शायद ही हो पाती। वो भी तब जब वो कुर्सी गंवाने के बाद शिवराज सिंह चौहान से बदला लेने की दिन-रात तैयारियों में जुटे हों। फिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि सिंधिया के साथ कांग्रेस में औपचारिक एंट्री के बाद बराबर की जिम्मेदारी निभाने वाली प्रियंका गांधी कांग्रेस की कोर टीम से बाहर रहीं? प्रियंका गांधी वाड्रा की कंसल्टेटिव कमेटी में गैरमौजूदगी पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इसे राहुल गांधी के मनमाफिक और सोनिया गांधी की मंजूरी से बनाया गया है।

● **दिल्ली से रेणु आगाल**

नेतृत्व का लोहा

कोरोना वायरस के इस संक्रमणकाल में पूरा विश्व त्राहि-त्राहि कर रहा है। ऐसे दौर में भी भारत की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा बेहतर है। इसके लिए पूरा विश्व समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता को सराह रहा है। दरअसल, भारत में जिस तरह लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, उससे यही संदेश जा रहा है कि भारत की 135 करोड़ जनता को मोदी पर विश्वास है।

पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। इस बीच अमेरिकी डेटा रिसर्च कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया के टॉप 10 नेताओं पर तुलनात्मक अध्ययन किया है। इस रिसर्च के मुताबिक दुनिया के दस बड़े देशों के राष्ट्रप्रमुखों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे प्रभावशाली नेता बताया गया है। दरअसल, कोरोना के खिलाफ हो रही जंग में अमेरिका में एक ओपिनियन पोल किया गया। जिसमें दुनियाभर की सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों को लेकर राय ली गई। इस पोल में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी कदम उठाए हैं। इस आधार पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर हैं।

दरअसल, अमेरिका की एक वेबसाइट ने इस दौरान अमेरिकी लोगों के बीच आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक और राजनीतिक पक्षों को लेकर सर्वे किया है। इस सर्वे में एक दिलचस्प बात निकलकर सामने आई है। सर्वे के मुताबिक राजनीतिक प्रभाव के मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के अन्य ताकतवर नेताओं से कहीं ज्यादा लोकप्रिय बनकर उभरे हैं। दुनिया की सबसे अमीर हस्ती बिल गेट्स ने खत लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना की जंग में उनके कार्यों की खूब तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में गेट्स ने लिखा है कि कोरोना के खिलाफ आपने और आपकी सरकार ने जो जरूरी कदम उठाए हैं, उसकी हम सराहना करते हैं। बता दें कि बिल गेट्स हेल्थ और सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए भारत को फंड मुहैया कराते रहे हैं।

भारत खुद भी कोरोना वायरस से जूझ रहा है लेकिन इस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने देशवासियों के साथ-साथ अन्य देशों की भी चिंता सता रही है। मोदी ने 'वसुधैव कुटुंबकम' और 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' की भारतीय संस्कृति को जिंदा रखते हुए करीब 55 देशों की मदद की है। भारत ने दुनिया के 55 से ज्यादा देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और पैरासिटामोल दवाइयां भेजी हैं।

भारत की इस मदद के बाद पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी के नाम का डंका बजने लगा है। बता दें कि भारत तो उन देशों में से है जिसने चीन की भी मदद की है जब वो अपने शहर वुहान में फैले कोरोना वायरस के सामने बेबस खड़ा था। कोरोना वायरस ने लगभग विश्व के हर कोने में अपने पैर पसार लिए हैं। सभी देश एकजुट होकर इस वायरस से लड़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने **इस सकंट की घड़ी में** सभी देशों को एक साथ लाने के लिए एक अहम पहल की जिसमें उन्होंने साउथ एशियन असोसिएशन फॉर रिजनल को-ऑपरेशन यानी सार्क राष्ट्राध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मीटिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए

मदद के लिए हमेशा आगे

भारत एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों की मदद के लिए हमेशा अपने हाथ आगे बढ़ाता है। नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में फैली इस महामारी के रोकथाम के लिए दवाई भिजवाना हो या फिर विदेशों में फंसे उनके नागरिकों को सुरक्षित निकालवाना, भारत ने उनकी पूरी मदद की। आपको बता दें कि चीन, ईरान, इटली समेत दुनिया देशों के नागरिकों को एयर लिफ्ट करके भारत ने उनके देशों तक पहुंचाया है। चूंकि इतने बड़े पैमाने पर लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों का प्रभावित होना स्वाभाविक है। ऐसे में सरकार ने 1.76 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से राहत देने का प्रयास किया है। इसमें 80 करोड़ से अधिक जरूरतमंदों को गेहूं और चावल मुफ्त मिलेगा। वहीं 20 करोड़ से अधिक महिलाओं के जन-धन खातों में सीधे रकम पहुंचाई जा रही है। साथ ही पीएम-किसान योजना के तहत 9 करोड़ किसानों को राहत के अलावा 20 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा और 63 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रोत्साहन दर्शाता है कि कोरोना आपदा से निपटने के लिए मोदी सरकार किस कदर कमर कसे हुए है।

भारत ने इमरजेंसी फंड की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी वो पहले नेता बन गए जिन्होंने इस वायरस से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पर जोर दिया। इस फैसले पर कई देश के नेताओं ने उनकी तारीफ भी की। भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के मदद के लिए खड़ा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नेपाल को इस महामारी से बचाने के लिए 23 टन जरूरी दवाएं भेजी हैं। जिसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी भारत की तरफ से मेडिकल राहत सामग्री भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद व्यक्त करते हुए ट्वीट कर कहा था, 'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए नेपाल को 23 टन आवश्यक दवाएं दी है। आज भारतीय राजदूत के द्वारा हमारे स्वास्थ्य मंत्री को दवाईयां सौंपी गईं।'

कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में पिछले एक महीने में तैयारी का सूचकांक (इंडेक्स ऑफ रेडीनेस) तेजी से बढ़ा है, आत्मसंतुष्टि का सूचकांक नीचे चला गया है, जबकि महामारी से निपटने के लिए सरकारों के प्रयासों में लोगों का विश्वास न केवल ठोस बना हुआ है, बल्कि अप्रूवल (अनुमोदन) रेटिंग में वृद्धि जारी है। आईएएनएस/सी-वोटर के सर्वे में गत दिनों यह बात सामने आई। 16 मार्च से 20 अप्रैल के बीच किए गए इस सर्वे में इंडेक्स ऑफ रेडीनेस के माध्यम से पता चला है कि आगे की योजना बनाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। वह राशन, दवाइयों और इनकी खरीद के लिए अलग से धन रख रहे हैं।

सर्वे में 20 अप्रैल तक 42.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तीन सप्ताह से अधिक समय तक राशन और दवाओं का स्टॉक किया है, जबकि 2 सप्ताह से कम वाले लोगों की संख्या अभी भी 56.9 प्रतिशत से अधिक हैं। हालांकि 4,718 व्यक्तियों के नमूने के आकार वाले सर्वेक्षण में एक हफ्ते से भी कम समय के लिए तैयारी करने वालों की संख्या केवल 12.1 प्रतिशत है। 16 मार्च को तीन सप्ताह से कम राशन रखने वाले लोगों की संख्या 90 प्रतिशत थी और लगभग तीन सप्ताह से अधिक राशन किसी के पास नहीं था। वहीं, अब विशेष रूप से अप्रैल में लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा के बाद के समय लगभग हर दिन यह संख्या बढ़ रही है।

इंडेक्स ऑफ पैनिक की बात करें तो 20 अप्रैल तक के आंकड़े बताते हैं कि 41.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ऐसा लगता है कि उनके परिवार में किसी को भी यह महामारी हो सकती है। वहीं, 56.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इससे इतर कहा कि उन्हें या उनके परिजनों को यह वायरस प्रभावित नहीं करेगा। सर्वे की शुरुआत में पहले कुल 35.1 प्रतिशत को लगता था कि उन्हें संक्रमण हो सकता है। ट्रैकर में सबसे कंसिस्टेंट रीडिंग ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट इंडेक्स पर आई है। देश में 93.5 फीसदी लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को प्रभावी ढंग से संभाल रही है और इससे अच्छे से निपट लेगी।

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर 25 मार्च को लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि को 15 अप्रैल के बाद भी संभावित चुनौतियों को देखते हुए 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया था। आईएएनएस/सी-वोटर कोविड-19 ट्रैकर (सर्वे) के अनुसार, मोदी सरकार महामारी के प्रकोप की स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाल रही है। लॉकडाउन के पहले दिन इस बात को लेकर विश्वास रखने वाले लोगों की कुल संख्या 76.8 प्रतिशत थी, जबकि वर्तमान में 21 अप्रैल तक यह आंकड़ा बढ़कर 93.5 प्रतिशत हो गया है।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 को और भी अधिक फैलने से रोकने की अप्रत्याशित चुनौती का सामना करते हुए देश ने अद्भुत **एकजुटता** एवं संयम का परिचय दिया है। जब पहली बार लॉकडाउन किया गया था तो यह इस देश में एक असंभव सा विचार प्रतीत हो रहा था, पर अब लोग स्वयं के साथ अपने साथी लोगों को भी कोरोना वायरस से बचाने के अपने संकल्प में दृढ़प्रतिज्ञ हो गए हैं। देशवासियों ने इस महामारी के खिलाफ जैसी एकजुटता दिखाई वह विश्व इतिहास में अभूतपूर्व है। आने वाली पीढ़ियों को आश्चर्य होगा कि भारत जैसे विविधता वाले देश में यह आखिरकार कैसे संभव हो पाया? यह सब देश में असाधारण नेतृत्व की बदौलत ही संभव हो पाया है।

विदेशों ने भी माना मोदी की लोकप्रियता का लोहा

मोदी कोई साधारण नेता नहीं हैं। यहां तक कि उनके घोर आलोचक भी यह स्वीकार करते हैं। उनकी असाधारण अपील देश में धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक सहित तमाम विभाजक रेखाओं को भेदकर राष्ट्र को एक कड़ी में जोड़ देती है। कोरोना को रोकने के लिए उनकी सरकार ने शुरुआती दौर में ही कई मोर्चों पर कदम उठाए, पर सबसे ज्यादा लॉकडाउन कहीं अधिक कारगर साबित होता दिख रहा है। यह विविधता में एकता की सबसे उम्दा मिसाल बनकर उभरा है। भारत के अनुभव से सिंगापुर ने महीनेभर के लॉकडाउन का फैसला किया। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोलैंड और अमेरिका के तमाम हिस्सों में भी अघोषित लॉकडाउन जारी है। फिर भी मोदी ने जिस व्यापक स्वरूप और सख्ती से लॉकडाउन को लागू किया उसकी तो किसी वैश्विक नेता ने उनसे पहले कल्पना तक नहीं की थी।

कोरोना का संक्रमण बेशक फैल रहा है, फिर भी हम विश्वास से भरे हैं, क्योंकि दुनिया के अन्य हिस्सों में संक्रमित रोगियों की निरंतर बढ़ती संख्या की तुलना में भारत में इसका प्रकोप काफी सीमित है। यह इसलिए आश्चर्यजनक है, क्योंकि भारत न केवल अधिक जनसंख्या घनत्व वाला एक विकासशील देश है, बल्कि यहां सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं एवं संसाधन भी सीमित हैं।

जब कोरोना जैसी आपदा आकर घेर ले तो उससे उबारने के लिए दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व की दरकार होती है। इस भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह खरे साबित हो रहे हैं। यह उनके आव्हान का ही असर था कि देश के आम जनमानस ने पहले जनता कर्फ्यू के दिन ताली-थाली बजाकर और उसके बाद 5 अप्रैल को मोमबत्ती-दीया जलाकर कोरोना के खिलाफ मुहिम में जुटे योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के साथ ही संकट के समय राष्ट्रीय एकजुटता का भाव प्रदर्शित किया।

● **इन्द्र कुमार**

30 हजार करोड़ की सहायता

कोरोनावायरस के संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ पर व्यापक असर हुआ है। यहां के जरूरतमंद परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के संचालन व सामान्य कामकाज के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आगामी तीन माह में 30 हजार करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मांगी है। बघेल ने 10 हजार करोड़ रुपए की राशि तत्काल जारी करने का आग्रह किया है, ताकि औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियों और कृषि क्षेत्र की तुरंत सहायता की जा सके। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में राज्य में कोविड-19 के प्रसार की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए राज्य को आंशिक राजस्व प्राप्ति से संबंधित आर्थिक गतिविधियों के संचालन की छूट तत्काल प्रदान करने का आग्रह किया है।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 को फैलने से रोकने के मामले में नियंत्रित स्थिति को देखते हुए राज्य को आंशिक राजस्व प्राप्ति से संबंधित आर्थिक गतिविधियों के संचालन की छूट तत्काल प्रदान करने का आग्रह किया है। बघेल ने पत्र में लिखा है कि मिठाई दुकानों के संचालन की छूट दी जाए, जिससे दुग्ध उत्पादकों का दूध बिकना संभव हो सके। उन्होंने लिखा है कि संपत्तियों के क्रय-विक्रय के पंजीयन की छूट सहित वाहनों के शोरूम का संचालन और पंजीयन, शहरों में निर्माण कार्यों के संचालन, ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए एयर कंडीशनर, कूलर और फ्रिज के शोरूम के संचालन, समस्त प्रकार के मरम्मत कार्य और ग्रीन जिलों में सभी प्रकार के खुदरा कार्य खोलना उचित होगा। राज्य शासन की ओर से सभी व्यक्तियों के मास्क पहनने, सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाएंगे।

बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखा है कि लॉकडाउन की लंबी अवधि के कारण राजस्व प्राप्ति लगभग शून्य हो गई है। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में राज्य को केंद्रीय करों में से प्राप्त होने वाली राशि में भी बड़ी कमी होना निश्चित है। दूसरी ओर राज्य के 56 लाख गरीब और जरूरतमंद परिवारों, जिनकी आय का कोई साधन नहीं बचा है, के जीवनयापन के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि यदि उक्त गतिविधियों के संचालन की तत्काल अनुमति नहीं दी जाती है तब राज्य के सामान्य कामकाज का संचालन संभव नहीं हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने पत्र में बताया है कि राज्य में कोविड-19 के प्रकोप की स्थिति तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों से बेहतर है। 21 अप्रैल तक राज्य में कोविड-19 के 36 मरीज संक्रमित पाए गए थे, जिनमें से 25 व्यक्ति संक्रमण मुक्त होकर घर जा चुके हैं, शेष 11 व्यक्तियों का उपचार जारी है तथा सभी की दशा सामान्य है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिदिन लगभग 400 व्यक्तियों की जांच की जा रही है। पिछले पांच दिन में कोई भी नया व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित नहीं पाया गया है। राज्य के 28 जिलों में से 23 जिलों में अभी तक एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया गया है, जबकि चार जिलों जहां 8 संक्रमित मिले थे, वहां पिछले तीन सप्ताह से कोई प्रकरण सामने नहीं आया है तथा एकमात्र जिले के 11 सक्रिय संक्रमितों का इलाज अभी जारी है।

इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता की मांग कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र से 1016 करोड़ रुपए की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए एक पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। इसमें कहा गया है कि मनरेगा के तहत वर्ष 2020-21 की पहले तीन माह की राशि को जारी किया जाए। कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन से मजदूरों के सामने संकट आ गया है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत 39.56 लाख परिवारों के 89.20 लाख श्रमिक पंजीकृत हैं। इनमें से 32.82 लाख परिवारों के 66.05 लाख श्रमिक सक्रिय रूप से योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त करते हैं। मार्च 2020 की शुरुआत में राज्य में करीब 12 लाख श्रमिक रोज कार्य कर रहे थे। पिछले 10 दिनों से कोरोना संक्रमण से हुए लॉकडाउन से श्रमिकों की संख्या बहुत कम हो गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, राज्य शासन की ओर से कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। वर्तमान में मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 484 करोड़ रुपए की मजदूरी भुगतान लंबित है। इन विपरीत परिस्थितियों में इस लंबित मजदूरी का भुगतान तत्काल किया जाना आवश्यक है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

लॉकडाउन बढ़ने से छोटे कारोबारी मुसीबत में

लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 3 मई करने के सरकारी निर्णय का भले ही लोग स्वागत कर रहे हों, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी लॉकडाउन बढ़ने से आर्थिक हालत खस्ता होने के साथ ही परेशानी बढ़ गई है। छोटे-छोटे कारोबारियों ने 22 मार्च से बंद छोटे-छोटे कारोबार को लॉकडाउन से मुक्त कराने की मांग की है। गरीब एवं मध्यम वर्ग के जरूरतमंदों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या अब और बढ़ गई है। ऐसे लोग इस उम्मीद में थे कि 14 अप्रैल तक किसी तरह लॉकडाउन का पालन कर वे अपना एवं परिवार का जीविकोपार्जन कर लेंगे। ऐसे में लॉकडाउन की समय-सीमा 3 मई तक बढ़ा दिए जाने से मध्यम वर्ग के लोगों की चिंता बढ़ने के साथ ही परेशानी बढ़ गई है। मध्यम वर्गीय श्रेणी के लोगों का कहना है कि ऐसे में वे अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। समाज में एक बड़ा वर्ग मध्यम श्रेणी का है, जिसके पास ना तो कोई राहत सामग्री पहुंच रही है और ना ही कोई इनकी सुध लेने वाला है। ऐसे लोगों के पास राशन कार्ड तक नहीं है। जिससे इस वर्ग से जुड़े बड़े तबके को कुछ मदद मिल सके। उनका आरोप है कि जनप्रतिनिधि से लेकर पंचायत प्रतिनिधि तक इस दिशा में पूरी तरह उदासीन है। चौक-चौराहों पर ठेला गुमठी लगाकर लगाकर चाय एवं अन्य तरह के सामान बेचकर परिवार के सदस्यों के लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करने वाले आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं।

राज्यपाल भरोसे उद्धव

कोरोना संक्रमण के संकट से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र से आ रही राजनीतिक खबरें वहां एक बार फिर राजनीतिक संकट खड़ा होने का संकेत दे रही हैं। पिछले सप्ताह राज्य मंत्रिमंडल ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सूबे के राज्यपाल से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्य की विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश अभूतपूर्व इस मायने में है कि इससे पहले देश में **विधान परिषद** वाले किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के लिए ऐसी सिफारिश करने की नौबत नहीं आई। यह सिफारिश इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का पद संभाले छह महीने पूरे होने वाले हैं, वह अभी तक राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं बन पाए हैं।

महाराष्ट्र में दो सदनों वाला विधानमंडल है- विधानसभा और विधान परिषद। मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। उद्धव ठाकरे अभी न तो विधायक हैं और न ही विधान पार्षद (एमएलसी)। अगर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया तो देश में यह पहला मौका होगा जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधानमंडल का निर्वाचित सदस्य न होकर **मनोनीत** सदस्य होगा। लेकिन अगर राज्यपाल ने मंत्रिमंडल की सिफारिश को ठुकरा दिया तो आगामी एक मई को 60 बरस के होने जा रहे महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व संकट पैदा हो जाएगा। इस संकट के चलते न सिर्फ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी दांव पर लगेगी, बल्कि चंद महीनों पहले बड़ी मशक्कत के बाद बनी महाविकास अघाडी यानी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार का वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। कुल मिलाकर इस संवैधानिक पेच वाले संकट की चाबी राज्यपाल और प्रकारांतर से केंद्र सरकार के पास है।

उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के ऐसे आठवें मुख्यमंत्री हैं, जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित हुए बगैर ही मुख्यमंत्री बने हैं। उनसे पहले 1980 में अब्दुल रहमान अंतुले, 1983 में वसंतदादा पाटिल, 1985 में शिवाजीराव निलंगेकर पाटिल, 1986 में शंकरराव चव्हाण, 1993 में शरद पवार, 2003 में सुशील कुमार शिंदे और 2010 में पृथ्वीराज चव्हाण भी मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानमंडल के सदस्य बने थे। अंतुले, निलंगेकर पाटिल और शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा का उपचुनाव लड़ा था और जीते थे, जबकि वसंतदादा पाटिल, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार और पृथ्वीराज चव्हाण ने विधान परिषद के रास्ते से विधानमंडल का सदस्य बनने की संवैधानिक शर्त पूरी की थी।

दरअसल महाराष्ट्र में इस समय जो स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए कोई और नहीं बल्कि सत्ता पक्ष खुद ही जिम्मेदार है। उद्धव ठाकरे ने विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित हुए बगैर 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। संविधान की धारा 164 (4) के अनुसार उन्हें अपने शपथ ग्रहण के छह महीने के अंदर यानी 28 मई से पहले अनिवार्य रूप से राज्य के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना है। इस संवैधानिक अनिवार्यता से वाकिफ ठाकरे ने हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ही तय कर लिया था कि वह विधानसभा का सदस्य बनने के बजाय विधान परिषद का सदस्य बनकर संवैधानिक अनिवार्यता पूरी करेंगे। लेकिन इसे पूरा करने में उन्होंने जरा भी तत्परता नहीं दिखाई। उनकी पार्टी और उनके गठबंधन में शामिल दलों ने भी अपने मुख्यमंत्री को विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित कराने को लेकर कोई फिक्र नहीं की।

ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद 7 जनवरी 2020 को विधान परिषद की दो रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे। ठाकरे चाहते तो इनमें से किसी भी एक सीट से चुनाव लड़कर विधान परिषद के सदस्य बन सकते थे, क्योंकि दोनों ही सीटें सत्तापक्ष के सदस्यों- शिवसेना के तानाजी सावंत और एनसीपी के धनंजय मुंडे के इस्तीफे से खाली हुई थीं। ये दोनों ही नेता विधानसभा के लिए चुन लिए गए थे, लिहाजा उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। सावंत के इस्तीफे से खाली हुई सीट का चुनाव यवतमाल जिले के स्थानीय निकाय सदस्यों द्वारा, जबकि मुंडे के इस्तीफे से खाली हुई सीट का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा किया जाना था। दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल था, जिसके बूते उद्धव ठाकरे आसानी से विधान परिषद के लिए निर्वाचित हो सकते थे। लेकिन शायद उन्होंने उपचुनाव के जरिए निर्वाचित होने बजाय 24 अप्रैल को खाली हो रही विधायकों के कोटे वाली 9 सीटों के नियमित चुनाव का इंतजार करना उचित समझा।

● **बिन्दु माथुर**

मनोनयन ही माध्यम

अब उनके सामने एक विकल्प और बचता है, वह है विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनयन का। वर्तमान में राज्यपाल के मनोनयन कोटे से विधान परिषद की दो सीटें खाली हैं, क्योंकि पूर्व में मनोनीत दो सदस्यों ने पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। इन दोनों खाली सीटों का कार्यकाल भी जून मध्य तक ही शेष है। बहरहाल, राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल कोटे की इन्हीं दो में से एक सीट पर उद्धव ठाकरे को विधानपरिषद का सदस्य मनोनीत किए जाने की सिफारिश राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजी है। लेकिन यह विकल्प भी निरापद नहीं है, क्योंकि इसमें भी संवैधानिक पेच हैं। हालांकि राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले विधान परिषद सदस्यों के नामों की सिफारिश राज्य सरकार ही करती है, लेकिन राज्यपाल की अपेक्षा रहती है कि जिन नामों की सिफारिश राज्य सरकार कर रही है, वे गैर राजनीतिक हो।

असाधारण होने का मौका

योगी आदित्यनाथ की सरकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की ही तरह 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की बातें करती है। लेकिन एक बड़े वर्ग को ऐसा लगता है कि इस पर अक्सर उनका भगवा एजेंडा भारी पड़ जाता है। लखनऊ में 19-20 दिसंबर को हुए दंगे से निपटने का योगी सरकार का तरीका इसका एक उदाहरण माना जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर के दंगों के बाद जो बयान दिया उसमें 'बदला लेने' की बात कही गई थी। वे शायद उस वक्त यह भूल गए थे कि किसी भी अपराध के लिए सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही की जा सकती है, बदले की कार्रवाई नहीं। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का काम अपने नागरिकों से बदला लेने का नहीं बल्कि उनकी रक्षा करने का होता है। फिर भले ही उनमें से कुछ लोगों ने उसे वोट दिया हो या नहीं। लेकिन योगी सरकार ने दंगों की आरंभिक जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी और फिर उन्हें वसूली के नोटिस भिजवाने भी शुरू कर दिए।

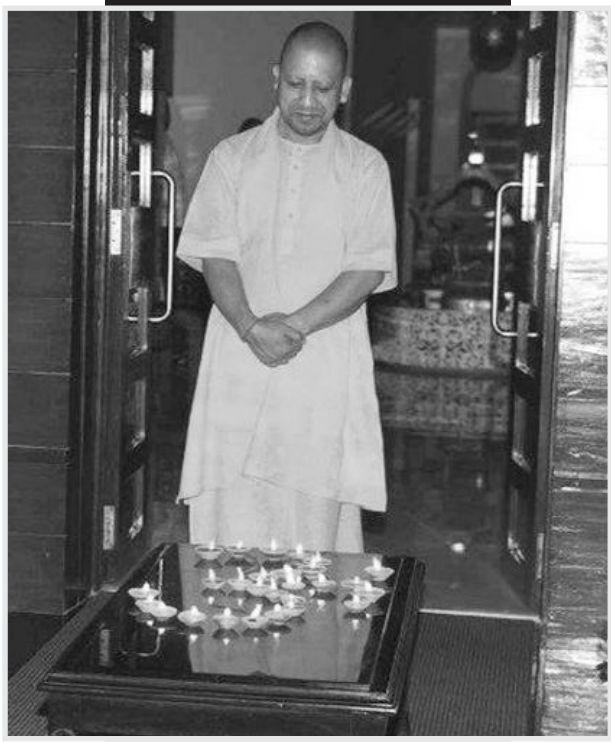

फिर इसके लगभग ढाई महीने के बाद दंगों की शुरूआती जांच में दोषी ठहराए गए **57 आरोपियों** के पोस्टर राजधानी लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर चस्पा कर दिए गए। पोस्टरों में इन लोगों से 88.6 लाख रुपए के नुकसान की भरपाई करवाने की बात कही गई थी। इस तरह के पोस्टर गोरखपुर, कानपुर आदि शहरों में भी लगाए गए। सरकार के इस भड़काऊ कदम पर बुद्धिजीवियों और समाज के जागरूक नागरिकों की कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। निजता का सम्मान करते हुए सरकार से पोस्टर हटाने की गुहार भी लगाई गई। मगर योगी सरकार को दया नहीं आई। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के पोस्टरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई और दो दिन के भीतर सभी **पोस्टरों को हटवाकर इस बारे में** अदालत को सूचित करने का निर्देश भी दिया।

इस हालत में अगर चाहती तो योगी सरकार सड़कों से पोस्टरों को हटवाकर नुकसान की भरपाई की कार्रवाई जारी रख सकती थी। इससे न केवल इस मामले में कड़वाहट थोड़ी कम हो सकती थी बल्कि अदालत के आदेश का सम्मान भी हो जाता। लेकिन सरकार ने इसे 'प्रतिष्ठा का प्रश्न' बनाकर फिर से अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। वह पोस्टर हटाने के बजाय मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई। साथ ही साथ योगी सरकार ने अपने कदम को जायज ठहराने और भविष्य में भी ऐसा ही कर सकने के लिए एक अध्यादेश भी जारी कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर राज्य सरकार को एक बड़ा झटका दे चुका था। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की थी कि उसने इस अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के 2011 के उस आदेश का ही अनुपालन करने की कोशिश की है। जिसमें कहा गया था कि यदि किसी प्रदर्शन के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसे रोकने के लिए कड़े नियम बनाए जाने चाहिए। हालांकि अदालत इस दलील से संतुष्ट नहीं हुई और अब मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है।

योगी सरकार के लिए 'सबका विश्वास' हासिल करने का यह सुनहरा अवसर था। अगर वह सरकार के तीन साल पूरे होने पर सीएए विरोधी हिंसा के सामान्य आरोपियों को कड़ी चेतावनी और पाबंदियों के साथ आम माफी दे देती तो इससे प्रदेश में एक सकारात्मक माहौल बन सकता था। लेकिन सरकार यहां पर चूक गई। दंगों या विरोध प्रदर्शनों के दौरान होने वाली हिंसा, तोड़फोड़ व आगजनी आदि से निपटने तथा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कड़े कदम उठाने का स्वागत होना चाहिए लेकिन इसके लिए सत्ता को बदले की भावना के बजाय निष्पक्ष कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए था। मगर योगी सरकार इसके लिए तैयार होती नहीं दिखी।

अब कोरोना संकट ने योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को एक नया मौका दिया है। बदली हुई परिस्थितियों में अगर वे बिना किसी भेदभाव के कुछ अच्छा कर देते हैं तो वह उनके बीते तीन सालों पर भारी पड़ सकता है। इस दिशा में बीते कुछ दिनों से वे काफी कुछ करते भी दिख रहे हैं। उदाहरण के लिए वे कोरोना के संकट से निपटने के लिए तुंरत और कठोर निर्णय ले रहे हैं। और राज्य की पुलिस प्रशासन तब्लीगी जमात के हवाले से पूरे मुस्लिम समुदाय को ही खलनायक बनाने के कुछ प्रयासों पर भी उचित कदम उठा रही है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में एक समाचार चैनल ने यह खबर चलाई थी कि प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में तब्लीगी जमात के चार लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें लेने जब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो उस पर पथराव किया गया। फिरोजाबाद पुलिस ने न्यूज चैनल की इस खबर का तुरंत खंडन किया और इससे जुड़े ट्वीट को हटाने का निर्देश भी दिया। ऐसा ही कुछ दूसरे ऐसे कुछ मामलों में भी देखा गया है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

भरोसे पर खरा उतरने का समय

कोरोना संकट से निपटने में योगी सरकार तो कठोर निर्णय लेती दिख रही है लेकिन इनके क्रियान्वयन के मामले में प्रशासन उतना चुस्त अब तक नहीं दिख पा रहा है। इस मामले में राज्य सरकार के स्तर पर कभी-कभी अस्पष्टता का अभाव भी देखा जा रहा है। इसी के चलते जब उसने 8 अप्रैल को राज्य के 15 जिलों के कुछ इलाकों को पूरी तरह से सील करने की घोषणा की तो नोएडा जैसे राज्य के सबसे विकसित और व्यवस्थित शहरों में अफरा-तफरी का आलम बना रहा। अगर योगी सरकार संकट की इस घड़ी में राज्य के हर समुदाय को दूसरे के बराबर न्याय और सभी को जरूरी चीजें उपलब्ध कराने का भरोसा दिला दे तो न केवल कोरोना को हराने में यह बड़ी भूमिका निभा सकता है बल्कि आदित्यनाथ को भी एक नई तरह से स्थापित करने का काम कर सकते हैं। नहीं तो वे कितने ही उत्सव मना लें सबके विश्वास का दावा नहीं कर सकते।

कोरोना पॉलिटिक्स

राजस्थान में इन दिनों कोरोना पॉलिटिक्स जोरों पर है। 2018 में विधानसभा चुनाव हार चुकी भाजपा और सत्तारूढ़ कांग्रेस में इन दिनों शीतयुद्ध चरम पर है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए एक बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में सियासी उबाल आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी पर कोरोना संकट में राज्य की कोई मदद नहीं करने का आरोप लगाकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पूरी तरह से विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रघु शर्मा के बयान को देशवासियों का अपमान बताया है, तो प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के बयान की निंदा करते हुए कहा कि सत्ता के मद में चूर मंत्री प्रधानमंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद की मर्यादा भी भूल गए। झूठ बोलकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की पसंद बनने का सपना देख रहे रघु शर्मा किस प्रमाण के साथ प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं।

दरअसल, एआईसीसी द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन पत्रकार वार्ता में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि **कोरोना वायरस की महामारी** में केंद्र राज्यों की मदद नहीं कर रहा है। पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्रियों ने मदद मांगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हमसे कुछ भी मत मांगो और आप भी कुछ मत करो, 2 दिन अखबार में छपकर रह जाएगा। अब आप बताइए ऐसे में हम क्या करते। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस व भाजपा सहित सभी राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद और राज्यों की सीमा 3 से बढ़ाकर 5 फीसदी करने की मांग की थी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के बयान पर आपत्ति जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया गया झूठा आरोप बेहद निंदनीय है। प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे व्यक्ति पर मनगढंत आरोप लगाना न केवल मर्यादाहीन है, बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी है। अपने दूसरे ट्वीट में वसुंधरा राजे ने कहा कि चिकित्सा मंत्री की प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी देशवासियों का अपमान है, जो साबित करती है कि राज्य सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर बातों के सिवाय कुछ भी नहीं है। जबकि हम राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना संकट में राज्य सरकार के सहयोग के लिए तैयार हैं।

वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सरकार का हिस्सा हैं, जो बयान मंत्री शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिया है, वो सच है तो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करें। जिसके आधार पर वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे है, साथ ही ये भी बताएं कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कब और कैसे बात हुई। पूनिया ने आगे कहा कि अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपनी हैसियत में रहकर अपने विभाग का काम ठीक से करें। इसके साथ ही प्रदेश भाजपा कार्यालय में सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की उपस्थिति में आयोजित हुई एक ऑनलाइन प्रेसवार्ता के दौरान सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश सरकार की तुष्टिकरण की नीति के कारण ही राज्य में कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, अपने वोट के लिए सरकार तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ सख्ती नहीं कर रही है। यही कारण है कि ये संक्रमण प्रदेश के 26 जिलों तक पहुंच गया है। पूनिया ने आगे कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार से संरक्षण मिलने के कारण इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि ये अब पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों पर भी हमले कर रहे हैं। प्रदेश के अधिकारियों के हाथ सरकार ने बांध रखे हैं, उनको सरकार की ओर से स्वतंत्र रूप से काम करने से रोका जा रहा है। पूनिया ने आगे कहा कि कांग्रेस प्रदेश में विद्वेष की राजनीति कर रही है, उसकी अकर्मण्यता के खिलाफ आवाज उठाने पर वो भाजपा के विधायकों और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बताएं कि अब तक उनकी सरकार ने राज्य सरकार के पैसे से कितने लोगों को गेहूं बांटा, भारत सरकार की ओर से जो 40 हजार मीट्रिक टन गेहूं आया उसका वितरण कैसे किया। भारत सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए मनरेगा में, उज्ज्वला योजना में प्रदेश की 62 लाख महिलाओं को तीन महीने तक फ्री रिफिलिंग की सुविधा पर प्रतिमाह 478 करोड़, किसान सम्मान निधि में प्रदेश के 64 लाख किसानों को 2 हजार रुपए के हिसाब से 870 करोड़, जनधन खाता धारक प्रदेश के 1 करोड़ 52 लोगों को 500 रुपए, आपदा राहत में 970 करोड़ रुपए, चिकित्सा में आवंटित 1883 करोड़ में से 1780 करोड़ अब तक दिया है, इनको कैसे खर्च किया ये बताएं।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

सरकार अपनी विफलता केंद्र पर मढ़ रही

कटारिया ने आगे कहा कि गहलोत सरकार ने दावा किया कि वो श्रमिकों के खाते में 2500 रुपए डाल रही है। सरकार बताए कि अब तक उसने कितने लोगों के खाते में कितने रुपए डाले हैं। केंद्र ने सबसे अधिक पैसा राजस्थान को दिया है, जिससे प्रदेश सरकार राहत अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ये बता दें कि राज्य सरकार के खुद के खजाने से कितना पैसा राहत के काम पर खर्च किया गया है। कटारिया ने आगे कहा कि एसएमएस अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मियों को धर्मशाला में रुकवाया जा रहा है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। मुख्यमंत्री एक बार खुद उस धर्मशाला का दौरा करके आएं जिसमें ये स्वास्थ्यकर्मी रोके गए हैं। इसके साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी विफलता को केंद्र के माथे डालना चाहती है।

मन के घाव

कोरोना संकट काल में बिहार सरकार कैसा काम कर रही है? क्या वह जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है? क्या वह आम लोगों की भावनाओं का सही आंकलन कर पा रही है? क्या वह इस स्थिति में है कि बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश सरकार पर भरोसा जताए? दरअसल, ये सवाल इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव को महज 4-5 महीने ही शेष बचे हैं। दरअसल अक्टूबर-नवंबर में संभावित चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दल इस कोरोना संकट को लेकर बहुत कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार को घेरने का कोई अवसर भी नहीं जाने देना चाह रहे। यही वजह है कि तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता बार-बार कोटा में फंसे छात्रों और अप्रवासी मजदूरों का मुद्दा लगातार सोशल मीडिया पर उठाते रहे हैं। यहां सवाल यह भी है कि नीतीश सरकार क्या खुद अपने ही सवालों में उलझी हुई है या फिर वह विपक्ष के सवालों का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझती है। इन प्रश्नों के बीच दो बड़े सवाल ऐसे हैं जिसका आने वाले चुनाव पर क्या असर होगा इस बात का जवाब स्वयं 15 वर्षों से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश सरकार के पास भी नहीं है।

दरअसल, ये दो सवाल भर ही नहीं, बल्कि 'आक्रोश की ज्वालामुखी' हैं जो आने वाले समय में नीतीश सरकार पर फट सकते हैं। आक्रोश की दो ज्वालामुखी अप्रवासी मजदूर और हमारे वे छात्र और उनके परिवार हैं, जो बाहर के प्रदेशों में फंसे हुए हैं। इनमें से कुछ तो वापस आ पाए हैं, मगर अधिसंख्य बिहार आने की छटपटाहट में दिन काट रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की मानें तो ये दो 'आक्रोश' नीतीश सरकार के लिए काफी मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मणिकांत ठाकुर कहते हैं- सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, तीनों क्षेत्रों पर कोरोना **संकट का इफेक्ट** रहेगा। बिहार के चुनाव के संदर्भ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दो बातों से बड़ा नुकसान हो सकता है। पहला ये कि जिस तरीके का रवैया नीतीश सरकार का अप्रवासी मजदूरों के प्रति रहा है, उससे ये नीतीश अप्रवासी मजदूर के दिल से उखड़ गए हैं। कोरोना के कहर से अधिक बिहार सरकार की सख्ती से उनका जीवन नर्क हो गया।

मणिकांत ठाकुर कहते हैं, 'कोरोना-बंदी की घोषणा के वक्त माइग्रेंट के बारे में नहीं सोचा गया, ये केंद्र सरकार की गलती थी। अचानक इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के कामगार-मजदूरों पर बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। ये जान-बूझकर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस बड़ी समस्या के बारे में सोचा ही नहीं गया।'

इसके बाद तो बिहार की नीतीश सरकार की भी 'आपराधिक' चूक हुई है। जब मौका था कि अप्रवासियों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। उप्र के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को 'बुरा फंसे' समझकर अपने लिए समय रहते इस समस्या का निवारण कर लिया। उसी राह पर मप्र की शिवराज सरकार भी चल रही है, मगर बिहार सरकार अपनी जिद में इसे टालती रही। यही नहीं, उस पर तर्क भी कुतर्क के साथ गढ़ती रही। बकौल मणिकांत ठाकुर 'जिस तरह से लोग सड़कों पर आ गए और जैसे-तैसे बिहार आने लगे। रेलगाड़ी और ट्रकों-बसों के जरिए व्यवस्थित तरीके से बुलाते तो ये ठीक रहता। दो हजार-चार हजार लोग पैदल चले आ रहे थे, क्या ये नीतीश सरकार को नहीं दिख रहा है। मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि चूंकि बिहार में सर्वाधिक माइग्रेंट हैं वे सब लोग आने वाले चुनाव तक तो घर लौटेंगे ही। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि उसी समय दुर्गापूजा और छठ पर्व हुआ करता है। ऐसे में अगर ये आ गए तो इनके 'मन के घाव' की कीमत नीतीश सरकार को चुकानी होगी। यही नहीं कोटा और अन्य प्रदेशों में फंसे छात्रों के साथ बाहर जो फंस गए, उनको भी एड्रेस नहीं किया गया। चुनाव के महज 4-5 महीने ही शेष हैं पर बिहार विपक्ष के पास नीतीश सरकार पर हमलावर होने का मौका भी नहीं है।

उधर, कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में चुनाव आयोग को बिहार चुनाव की चिंता सता रही है। दरअसल इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर हाल ही में एक बैठक की। पता चला है कि इस बैठक में चुनाव आयोग ने दक्षिण कोरिया मॉडल पर चुनाव कराने को लेकर चर्चा की। बता दें कि दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस माहमारी के बीच इसी माह नेशनल असेंबली की 300 सीटों के लिए चुनाव आयोजित कराए गए हैं। यही वजह है कि चुनाव आयोग भी बिहार चुनाव दक्षिण कोरिया मॉडल के आधार पर कराने की योजना बना रहा है। इसके लिए आयोग ने बाकायदा एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। यह कमेटी दक्षिण कोरिया मॉडल का अध्ययन करेगी और बिहार चुनाव में उसे लागू करेगी। बता दें कि दक्षिण कोरिया में बीती 15 अप्रैल को चुनाव हुए थे। इस दौरान करोड़ों लोगों ने चुनावों में हिस्सा लिया। हालांकि इसके लिए दक्षिण कोरिया सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थीं। दरअसल कोरियाई सरकार ने लोगों को बड़ी मात्रा में मास्क, ग्लव्ज, हैंड सैनेटाइजर वितरित किए, ताकि लोग सावधानी से अपना वोट डाल सकें। मतदान कराने वाले कर्मचारियों के लिए भी पीपीई किट, फेस प्रोटेक्शन, मास्क और मेडिकल ग्लव्ज का इंतजाम किया गया। लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करने को कहा गया।

● **विनोद बक्सरी**

क्या बदलेगी बिहार की राजनीति?

वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगता है कि वे प्रधानमंत्री मोदी के नाम के सहारे चुनाव जीत जाएंगे। पर ये भी जमीनी सच्चाई है कि कोरोना संकट अभी लंबा चलेगा, ऐसे में केंद्र की सरकार के खिलाफ भी असंतोष बढ़ने की ही आशंका अधिक दिख रही है। बकौल अशोक कुमार शर्मा विपक्ष इस आक्रोश को भुनाने की कोशिश में तो जरूर है, पर कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से वह बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। लेकिन जनता के हाथ खुले हैं और ये दोनों आक्रोश भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और आने वाले चुनाव तक अगर इसी तरह आक्रोश की ये आग धधकती रही तो बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव हो सकते हैं।

कमजोर हुआ चीन

दुनिया में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुनिया की एक तिहाई आबादी लॉकडाउन में है। लेकिन जहां से ये महामारी शुरू हुई वो देश रिकवरी मोड में है, कामधंधा शुरू हो गया है और वायरस का केंद्र रहे वुहान और इसका जंगली जानवरों और जीव-जंतुओं वाला हन्नान सी-फूड मार्केट भी खुल गया। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि कोरोना ने चीन का मैन्युफैक्चरिंग किंग वाला तमगा छीन लिया और अब लोग चीनी सामान से किनारा करने लगेंगे? क्या चीन ने कोरोना तैयार किया है? क्या यूरोप और अमेरिका की इकोनामी को ढहाने के लिए चीन ने कोरोना को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है? भारत के लोगों के पास कैसे कोरोना से लड़ने के लिए है यूनिक ताकत इसकी भी बात करेंगे। साथ ही हम देश-दुनिया में चीन के मेक ओवर वाली खबरों और मीडिया में चलाए जा रहे एजेंडे को भी एक्सपोज करेंगे।

एक देश की नासमझी कैसे इस वक्त पूरी दुनिया भुगत रही है, ये कोरोना वायरस के संकट ने बता दिया है। आपने मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सुना होगा और इसका इस्तेमाल भी किया होगा। मेड इन चाइना वायरस के बारे में अब पहली बार आपको पता चल रहा है। कोरोना वायरस को मेड इन चाइना वायरस या चीनी वायरस कहने पर चीन को बुरा जरूर लग जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया में जो ये संकट बना है वो **मेड इन चाइना वायरस** की वजह से ही है। चीन पूरी दुनिया में अपने खतरनाक वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए जाना जाता है और इसलिए कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर लैब में निर्मित करने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल के एक जैविक हथियार विश्लेषक डैनी सोहम से बातचीत के आधार पर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक हैरान करने वाला दावा किया था। वॉशिंगटन पोस्ट में दावा किया, 'वुहान शहर में जैविक हथियार तैयार करने की गोपनीय परियोजना है। जहां इजराइली सेना के पूर्व खुफिया अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल डैनी सोहम ने चीन के जैविक हथियार को लेकर काफी काम किया है। दावा है कि चीन के जैविक हथियार का केंद्र है **वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी।** जहां मारक विषाणुओं पर काफी काम होता है। ये तमाम प्रयोगशाला जनसंहार के हथियार विकसित करने का काम करती है। यह लैब नवंबर 2018 में शुरू हुई थी और इसे बेहद गोपनीय श्रेणी में रखा गया था।

इस वक्त दुनिया के साथ-साथ भारत भी कोरोना से लड़ने में लगा है। लेकिन विश्व और मानवता के लिए सबसे बड़े संकट काल के महाभारत में भारत के लोगों के पास युद्ध की काबिलियत बेहद ज्यादा है। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि राहत पहुंचाने वाला यह तथ्य वैज्ञानिकों के ताजा शोध में उजागर हुआ है। शोधकर्ताओं का दावा है कि भारतीयों में एक विशिष्ट और विरला माइक्रो आरएनए मौजूद है। यह वंशानुगत आरएनए (राइबो न्यूक्लिक एसिड) अन्य देशों के लोगों में नहीं पाया जाता है। इसमें कोरोना वायरस की तीव्रता को मंद करने की ताकत है। दिलचस्प बात यह कि मौजूदा कोरोना वायरस भी आरएनए वायरस है।

अब चूंकि इस खोज ने सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया तो आखिर इसकी खोज किसने की ये सवाल उठना मौजूं है। दरअसल, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो टेक्नोलॉजी दिल्ली की टीम की ओर से कोरोना सार्स-टू पर यह शोध किया गया। इसमें डॉ. दिनेश गुप्ता के नेतृत्व में चार एक्सपर्ट ने पांच देशों के कोरोना मरीजों पर स्टडी की। 21 मार्च को ऑनलाइन जनरल में प्रकाशित रिसर्च पेपर संकट की इस घड़ी में भारतीयों के लिए उम्मीद जगा रहा है। केजीएमयू की डॉ. शीतल वर्मा के अनुसार इटली, चीन, भारत, अमेरिका और नेपाल के लोगों पर ये रिसर्च किया। एचएसए-एमआईआर-27-बी नामक यह माइक्रो आरएनए अन्य देशों के मरीजों में नहीं मिला। शोध में पता चला कि भारतीयों में मौजूद ये विशेष माइक्रो आरएनए उस वायरस को म्यूटेंट कर देता है जिससे वायरस की क्षमता दूसरे देशों के लोगों की अपेक्षा कम हो जाती है। दुनिया के तमाम देशों में कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि सात औद्योगिक शक्तियों के समूह के विदेश मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि चीन कोरोना वायरस महामारी के बारे में एक 'गलत सूचना' अभियान चला रहा है। जी-7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस जैसे सात देश और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। कोरोना से लड़ने के लिए इन्होंने जो प्रण लिए हैं, उसमें चीन का कहीं जिक्र तक नहीं है और चीन को पूरी तरह नकार दिया गया है। इसके उत्तर में चीन ने भी जी-7 के इन कदमों को निराशाजनक बताया है।

● **अक्स ब्यूरो**

बर्बाद हुई चीन की अर्थव्यवस्था

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड एनिशिएटिव प्रोजेक्ट को दुनिया के बड़े हिस्से में वर्चस्व के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन कोरोना वायरस ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को जमीन पर ला दिया है। इस खर्चीले प्रोजेक्ट के मंद पड़ने से चीन के अरबों डॉलर डूबने को जोखिम पैदा हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से चीन की अर्थव्यवस्था अब पस्त नजर आने लगी है। इस बात की पुष्टि चीन के मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े करते हैं। दरअसल, फरवरी में चीन में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गईं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चीन का खरीद प्रबंध सूचकांक (पीएमआई) फरवरी में गिरकर 35.7 पर आ गया। इस सूचकांक का 50 से नीचे रहना यह बताता है कि कारखाना उत्पादन घट रहा है। कोरोना वायरस और इसको लेकर बोले गए झूठ की वजह से संदेहास्पद चीन से दुनिया की दूरी की ओर बढ़ते कदमों के बीच भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग ताकत बनने का मौका है। जापान और चीन पहले यह करिश्मा कर चुके हैं। अब इसको दोहराने की बारी एशिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत की है।

बिडेन बने चुनौती

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रत्याशी बनकर सामने आए हैं। अपने वालेंटियर्स के एक शानदार नेटवर्क और चंदा इकट्ठा करने वाले एक सुचारू तंत्र के बावजूद बर्नी सैंडर्स डेलिगेट्स का गणित अपने पक्ष में न होने की बात समझ चुके थे। उनके पीछे हटते ही बिडेन की दावेदारी साफ हो गई। मार्च में सैंडर्स कुल 26 प्राइमरी में हुए चुनावों में से सिर्फ सात जीत सके थे। वे बिडेन से करीब 300 डेलिगेट पीछे थे। यह आंकड़ा इतना बड़ा था कि इसकी खाई पाटना मुश्किल था। लेकिन सैंडर्स के पैर पीछे खींचने और उनका बिडेन को समर्थन देने की कई बातें छुपी हैं, जिन्हें ठीक तरीके से समझा जाना चाहिए। साफ है कि यहां कोई साजिश की बात नहीं है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऐसा जताने की कोशिश जरूर की। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी में अब सैंडर्स का काम तमाम हो चुका है। बिडेन के लिए सैंडर्स का समर्थन आधिकारिक और सहानुभूतिपूर्ण है। यह 2016 में हिलेरी क्लिंटन को दिए गए समर्थन से बहुत अलग है। सैंडर्स और बिडेन के कैंपेन में कभी आपसी कड़वाहट नहीं थी। जबकि क्लिंटन के साथ ऐसा नहीं था। क्लिंटन के दिमाग में अब भी पुरानी चीजें मौजूद हैं। हाल में उन्होंने सैंडर्स के बारे में बहुत सारी बातें कहीं। वो यहां तक बोल गईं कि सैंडर्स को कोई पसंद नहीं करता।

बिडेन और सैंडर्स के बीच माहौल खुशनुमा है। दोनों ने माना है कि कुछ चीजों पर दोनों के बीच अलगाव है, लेकिन वे एक लंबे वक्त से दोस्त हैं। सैंडर्स ने कहा, 'मैं जानता हूं कि आप एक समावेशी रुझान रखने वाले व्यक्ति हैं। आप उन लोगों को भी साथ लेना चाहते हैं, जो आपसे असहमत हैं। आप उनकी बात सुनना चाहते हैं। हम तर्क कर सकते हैं। यही लोकतंत्र कहलाता है। आप लोकतंत्र में यकीन रखते हैं। मैं भी रखता हूं। चलिए एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। मौजूदा दौर और भविष्य की चुनौतियों का मिलकर सामना करते हैं। जो, मैं आपके साथ भविष्य में सहयोग करने के लिए उत्सुक हूं।' जो बिडेन ने भी ऐसी ही गर्मजोशी की झलक पेश की। अगर बहुलतावादी लोकतंत्र का विश्लेषण किया जाए, तो हम पाएंगे कि जिसने भी चुनाव जीता है, उसने अपने सबसे करीबी विपक्षी को गठंबधन में जगह देकर राजनीतिक एजेंडे में बात रखने का अहम जरिया दिया है। दोनों ने करीब 6 कार्य समूहों का गठन किया है, ताकि एक-दूसरे के साथ विदेश नीति समेत अलग-अलग मुद्दों पर बेहतर तालमेल बना पाएं। नामांकन जीतने जा रहे बिडेन के लिए यह करना जरूरी नहीं था। लेकिन उन्होंने ऐसा किया। वैसे भी बिडेन के सीनेटर इतिहास से पता चलता है कि वे किसी दूसरे के नुकसान से खुद का फायदा नहीं निकालते।

बिडेन, समझौतों और रियायतों के जरिए खाई पाटने में बहुत कुशल हैं। वह सीनेट में गठबंधन बनाकर विधायी काम को कराने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इसी विशेषता ने बराक ओबामा का ध्यान उनकी तरफ खींचा था। उनके समझौतावादी व्यवहार और गठबंधन की राजनीति ने उन्हें सैंडर्स के ऊपर बढ़त दिलाई है। जिन कार्य-समूहों का प्रस्ताव दिया गया, उनके जरिए सैंडर्स के नए विचारों की पहुंच बिडेन तक बनेगी, सैंडर्स के लोग बिडेन के कैंपेन और एजेंडे को आकार देने में मदद करेंगे। बिडेन वाम धारा के लोगों से अपनी हार के साथ समन्वय बनाने के लिए कह सकते थे। लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि वे वाम धड़े के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, उनकी समझौतावादी राजनीति एक मौका है जिससे वाम धड़ा अपनी नीतियों को प्रभाव बना सकता है।

दूसरे शब्दों में कहें तो बिडेन ने वामपंथियों को अपने गठबंधन में मिला लिया है। सहयोग के बदले वह उन्हें ठोस रियायतें और प्रभावी पद देने के लिए तैयार हैं। बिडेन जानते हैं कि सैंडर्स ने एक पूरी अमेरिकी पीढ़ी की उम्मीदें बांध रखी हैं। उन्होंने जनता को बड़ा सोचने और ज्यादा मांग करने के लिए प्रेरित किया है। सैंडर्स के तेज-तर्रार कैंपेन से पता चला है कि अमेरिकी जनता का एक बड़ा धड़ा उनके विचारों के लिए तैयार है। सैंडर्स भले ही व्हाइट हाउस न पहुंच पाएं, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को जरूर बदल दिया है।

बड़ा सवाल यह है कि सैंडर्स के समर्थक किस हद तक बिडेन के साथ जाने के लिए तैयार होंगे। सैंडर्स ने डोनाल्ड ट्रम्प को हराने की अहमियत बताते हुए एकता की अपील की है। उन्होंने ट्रम्प को आधुनिक अमेरिकी इतिहास का सबसे खतरनाक राष्ट्रपति करार दिया है। 2016 में सैंडर्स के समर्थक बड़ी संख्या में हिलेरी क्लिंटन के खेमे में चले गए थे (तकरीबन 80 फीसदी)। लेकिन 12 फीसदी ने ट्रम्प को वोट दिया था। वहीं 12 फीसदी वोटर्स अहम भी साबित हुए। आखिर विस्कोंसिन, मिशिगन और पेंसिलवेनिया में जीत का अंतर काफी कम रहा था। सैंडर्स की अपील के बाद बड़ी संख्या में समर्थकों के बिडेन के पक्ष में जाने की संभावना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उस तरफ नहीं खिचेंगे। यह लोग कुछ राज्यों में नतीजों को प्रभावित करने में सक्षम हैं। तस्वीर अभी काफी धुंधली है।

● **अक्स ब्यूरो**

सर्वे में ट्रम्प से आगे बिडेन

29 मार्च को वाशिंगटन पोस्ट के सर्वे से पता चला है कि 80 फीसदी सैंडर्स के समर्थक बिडेन के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन 15 फीसदी का एक भारी हिस्सा ट्रम्प के लिए भी मतदान करेगा। अगर 2016 में सैंडर्स के 12 फीसदी मतदाता ट्रम्प को चुनाव जिता सकते हैं, तो मौजूदा परिस्थितियों में सैंडर्स के 15 फीसदी मतदाता बिडेन के लिए बहुत चिंता का विषय हैं। लेकिन फिर 2009 का चुनाव भी याद आता है। तब हिलेरी क्लिंटन के 15 फीसदी मतदाताओं ने रिपब्लिकन कैंडिडेट जॉन मैक्केन को वोट दिए थे, लेकिन तब भी बराक ओबामा चुनाव जीत गए थे। इसमें कोई शक नहीं कि पाला बदलने वालों के हिस्से को बेहद छोटा रखने के लिए बिडेन बहुत कोशिश कर रहे हैं। यह सैंडर्स के साथ उनके हालिया व्यवहार से भी झलक रहा है। यह बात भी उनके एजेंडे पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। लेकिन ट्रम्प भी सैंडर्स के मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे। वह उनके पाले से आए हुए लोगों का पलकें बिछाकर स्वागत करेंगे। क्योंकि इस महामारी के दौर में वो राष्ट्रीय औसत में बिडेन से 6 अंकों से पीछे चल रहे हैं। वहीं एबीसी/पोस्ट के सर्वे में बिडेन को दो अंकों की ही बढ़त बताई गई है।

तंग नजरिये की शिकार स्त्री

हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी दुनिया भर में लगभग 90 फीसदी महिलाएं और पुरुष, महिलाओं के प्रति किसी न किसी तरह का पूर्वाग्रह रखते हैं। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा दुनिया की 80 फीसदी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 75 देशों का अध्ययन करने के बाद तैयार की गई है। अध्ययन में सामने आया है कि आज भी दस में से 9 लोग महिलाओं के प्रति दकियानूसी सोच रखते हैं। गौरतलब है कि 'जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स' नाम से आई यूएनडीपी की अपनी तरह की यह पहली रिपोर्ट है। दुनिया की लगभग 80 फीसदी आबादी को लेकर हुए इस अध्ययन के आंकड़ों का विश्लेषण **इस कटु सत्य से रूबरू** कराता है कि महिलाओं को समानता हासिल करने के मामले में आज भी अनगिनत बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

बीते कुछ बरसों में बहुत कुछ बदल कर भी सोच और संवेदनशीलता के मोर्चे पर कुछ न बदलने की स्थितियों में कितनी ही परेशानियां आज भी आधी आबादी के हिस्से हैं। दुनिया के हर हिस्से की महिलाओं ने खेल और अंतरिक्ष से लेकर राजनीतिक पटल और कारोबार के संसार तक अपनी क्षमता और योग्यता को सिद्ध किया है। बावजूद इसके उनके प्रति पूर्वाग्रही सोच कायम है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की इस रिपोर्ट में शामिल लगभग 50 फीसदी लोगों के मुताबिक पुरुष श्रेष्ठ राजनीतिक नेता होते हैं। 40 प्रतिशत से ज्यादा लोगों का मानना था कि पुरुष बेहतर कारोबारी दिग्गज होते हैं। इतना ही नहीं, 28 फीसदी लोगों ने तो पत्नी की पिटाई तक को जायज माना है। अफसोस कि इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि अध्ययन में शामिल 30 देशों में महिलाओं के प्रति नजरिया बदला है। लेकिन दुनिया के बड़े हिस्से में आज भी गैर-बराबरी कायम है। इस फेहरिस्त में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। वहीं हमारा देश छठे स्थान पर है।

दरअसल, सोच की दिशा न सिर्फ समाज में बदलाव की संभावना बनाती, बल्कि आमजन में बदलावों को लेकर सहज स्वीकार्यता भी लाती है। विचार की यह दिशा ही व्यवहार भी तय करती है। कार्यस्थल से लेकर घर-परिवार तक, राय बनाने का यह भाव महिलाओं के प्रति अपनाए जाने वाले व्यवहार में भी झलकता है। फिर बात चाहे घरेलू हिंसा की हो या कार्यस्थल पर होने वाले शोषण और दुर्व्यवहार की। विचार ही व्यवहार में तब्दील होकर महिलाओं के प्रति असंवेदशील परिवेश बनाते हैं। हमारे यहां पूरी सामाजिक-पारिवारिक व्यवस्था की धुरी होने के बावजूद औरतें ही असमानता की सोच की सबसे ज्यादा शिकार बनती हैं। आज भी शादी कर घर बसाने के फैसले में बेटियों की राय को बेटों की राय के बराबर नहीं माना जाता। अच्छी-खासी पढ़ी-लिखी और काबिल बेटियों के परिवार भी देहज देने को विवश किए जाते हैं।

पक्षपाती नजरिए का ही नतीजा है कि कई घरों में महिलाओं की राय और भागीदारी के कोई मायने नहीं समझे जाते। साथ ही, महिलाओं को कामकाजी मोर्चे पर भी अपनी क्षमता और योग्यता साबित करने के लिए कई अनकही-अनचाही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कहना गलत न होगा कि लैंगिक असमानता की सोच के चलते महिलाओं के जीवन का हर पहलू प्रभावित होता है। महिलाओं को कमतर आंकने की यह सोच हमेशा से पूरी दुनिया में देखी गई है। यही वजह है कि स्त्रियों को संबोधित अनगिनत योजनाओं और नीतियों के बावजूद उनके जीवन में आज भी असमानता का दंश कायम है।

यह अध्ययन बताता है कि पुरुष और महिलाएं दोनों समान रूप से मतदान करते हैं, लेकिन दुनियाभर में केवल 24 प्रतिशत संसदीय सीटों पर महिलाएं चुनी गई हैं। इतना ही नहीं, वैश्विक स्तर पर 193 देशों में से सिर्फ 10 में सरकारों की मुखिया महिलाएं हैं। चिंतनीय है कि शिक्षित और कामकाजी महिलाओं के बढ़ते आंकड़ों के **बावजूद कार्यस्थल** पर भी भेदभाव कायम है। यूएनडीपी की रिपोर्ट में सामने आया है कि विश्वभर में समान काम के लिए समान वेतन पाने का हक आज भी महिलाओं के हिस्से नहीं आया है। एक जैसा काम करने के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। इतना ही नहीं, महिलाओं को वरिष्ठ पदों पर पहुंचने के भी कम अवसर मिलते हैं। निसंदेह, इन हालात के लिए स्त्रियों के लिए मौजूद सोच ही जिम्मेदार है। इसके चलते काबिलियत और क्षमता के मुताबिक नहीं, बल्कि एक महिला होने के नाते उनके बारे में विचार बनाए जाते हैं।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

सुरक्षा की नई चिंताएं भी

चिंतनीय यह भी है कि महिलाओं की नई भूमिकाओं के साथ उनकी सुरक्षा की नई चिंताएं भी जुड़ गई हैं। घर की चारदीवारी से निकलकर उच्च शिक्षा, नौकरी या व्यवसाय के लिए अपनी राह बना रही महिलाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं के बढ़ते आंकड़े भी इस भेदभावपूर्ण सोच का ही नतीजा हैं। सशक्त और आत्मनिर्भर बनने के बावजूद घर और बाहर उपेक्षा, अपमान और असुरक्षा की स्थितियों की अहम वजह भी सोच का न बदलना ही है। हाल ही में 'ऑनलाइन एब्यूज' को लेकर किए गए एक अध्ययन में 95वें भारतीय महिला नेताओं के लिए किए गए ट्वीट की समीक्षा में पाया गया कि 13.8 फीसदी ट्वीट या तो आपत्तिजनक थे या फिर अपमानित करने वाले। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के इस अध्ययन के मुताबिक ऐसी अभद्रता ऑनलाइन दुनिया में किसी विषय पर महिलाओं द्वारा रखी गई राय लोगों की प्रतिक्रिया भर नहीं होती, बल्कि योजनागत रूप से उन्हें प्रताड़ित करने की सोच लिए होती है। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं कि पूर्वाग्रह पूर्ण सोच हर मामले में स्त्रियों के लिए बड़ी बाधा बन रही है। जबकि समानता के भाव के बिना सम्मान और सहजता दोनों ही मोर्चों पर कुछ कमी-सी रहती है।

रामायण बनाम महाभारत की भिन्नता और समानताएं

जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखि तिन तैसी जिसने भी जिस भावना धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा वैसा ही उसे नजर आया। क्या कारण है कि रामायण को लोग पूजते हैं और कुछ लोग महाभारत को घरों में रखना भी वर्जित मानते हैं। रामायण प्रेम, त्याग, कर्तव्य, समभाव और आज्ञापालन जैसे कई आदर्श मूल्यों के साथ-साथ जोड़ने की प्रवृति सिखाती है। जबकि महाभारत इससे बिलकुल उलट है। राग, द्वेष, छल-कपट, राजनीति नैतिकता के ह्रास व बड़ों की **अवहेलना के** साथ उद्दंडता परिवार तोड़ने और अति महत्वाकांक्षा, अहंकार का चरमोत्कर्ष दिखाती है लेकिन अंत में महाभारत में भी न्याय व सत्य की ही विजय दिखाती है। जबकि दोनों में विष्णु अवतार मौजूद हैं और अधर्म पर धर्म की विजय गाथा है।

रामायण व महाभारत दोनों ही भारतीयों के जीवन, नैतिक विचारों और धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित करते हैं। अंतर यह है कि रामायण प्रधानरूप से अलंकृत काव्य के रूप में प्रस्तुत इतिहास है जबकि महाभारत एक शुद्ध इतिहास ग्रंथ है। कहा जाता है भगवान शंकर ने सर्वप्रथम सौ करोड़ श्लोकों में राम भगवान के चरित्र का वर्णन किया था- 'चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरं', जबकि महाभारत मूल रूप से 'जय संहिता' थी। **महाभारत** के पहले ही श्लोक में 'ततो जयमुदीरयेत' का उल्लेख होता है। जब तुलसीदासजी ने रामचरित मानस लिखी तो उन्होंने इसके संदर्भों का उल्लेख करते हुए 'नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत रामायणे निगदितं क्वचितअन्यतोपि' अर्थात इस ग्रंथ में अनेक प्रकार के पुराणों, रामायण आदि का संदर्भ लिया गया है ऐसा उल्लेख किया है। महाभारत में इस प्रकार के संदर्भ घटनाओं के रूप में बीच-बीच में मिलते हैं पुस्तकों के रूप में नहीं।

दोनों का प्रारंभ राज्यसभा के दृश्य से होता है दोनों में ही सत्य की असत्य पर विजय दिखाई गई है। कुछ समय तक चाहे असत्य का उत्कर्ष दिखाई पड़े परंतु अन्ततोगत्वा सत्य की ही विजय होती है। दोनों ही काव्य अपने-अपने रचयिताओं के शिष्यों द्वारा यज्ञ के शुभ अवसर पर सुनाए गए हैं। दोनों काव्यों में चिरकाल तक आदान-प्रदान होता रहा है और समय के साथ-साथ इन दोनों काव्यों में परिवर्धन एवं परिशोधन होता रहा है। वेदों की भांति प्राकृतिक शक्तियों की उपासना समाप्त हो गई थी। वरुण अश्विन्, आदित्य, उषस आदि वैदिक देवताओं का अस्तित्व समाप्त हो गया था। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश आदि की उपासना की जाती थी। मंदिरों का निर्माण किया जाता था।

दोनों ग्रंथों में सीता और द्रौपदी नामक नायिकाओं का जन्म भी अलौकिक प्रकार से हुआ है, सीता का पृथ्वी से और द्रौपदी का अग्निकुण्ड से। दोनों ग्रंथों में अयोध्या राजकुमारों का जन्म व **कौरव-पांडवों** का जन्म भी सामान्य नहीं है। द्रौपदी व सीता के पास क्षुधा-तृप्ति की दिव्य शक्ति थी, द्रौपदी के पास अक्षय पात्र और सीता का इंद्र द्वारा दी हुई खीर का अशोकवाटिका में सेवन। दोनों का प्रारंभ राज्यसभा के दृश्य से होता है। सीता स्वयंवर एवं द्रौपदी स्वयंवर में राम व अर्जुन द्वारा धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने में, रावण द्वारा सीताहरण व द्रौपदी का जयद्रथ द्वारा हरण होने में, राम तथा पाण्डवों के वनवास में सीता व द्रौपदी के कारण महायुद्ध होने में, देवताओं द्वारा प्रदत्त दिव्यास्त्र प्राप्त करने में राम को सुग्रीव से तथा पाण्डवों की मत्स्यनरेश विराट से मित्रता होने जैसी बातों की समानता मिलती है।

रामायण में एक ही नायक है और वह है राम, लेकिन महाभारत में मुख्य पात्रों के बीच में किसी एक का नायक के रूप में चयन करना कठिन है। रामायण में धर्म की प्रधानता है जबकि महाभारत में शौर्य और कर्म प्रधान हैं। रामायण में राम का रावण के साथ युद्ध करना एक नियति थी जबकि महाभारत में कौरवों व पाण्डवों का युद्ध पारस्परिक द्वेष और ईर्ष्या के कारण ही हुआ। रामायण में सदाचार और नैतिकता का प्राधान्य है। जबकि महाभारत में राजनीति और कूटनीति का प्रधान है। रामायण में वर्ण व्यवस्था कठोर थी जबकि महाभारत के समय तक इसमें शिथिलता आ गई थी। रामायण में जब हनुमान सीता को अपनी पीठ पर बिठाकर उसे राम के पास ले जाने का प्रस्ताव रखते हैं, तो सीता परपुरुष-स्पर्श के भय से उसे अस्वीकार कर देती है। सीता को अपनी चारित्रिक शुद्धि प्रमाणित करने के लिए अग्नि-परीक्षा देनी पड़ती है। किंतु महाभारत में जयद्रथ द्वारा द्रौपदी के अपहरण के पश्चात उसे कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ती। द्रौपदी पांच पतियों वाली है। अग्नि परीक्षा का चलन महाभारत में नहीं था।

रामायण महाभारत से पहले की रचना है। कारण यह है कि रामायण, महाभारत के पात्रों से अनभिज्ञ थे लेकिन महाभारत के रामोपाख्यान में रामकथा का वर्णन है। रामायण महाभारत की अपेक्षा बहुत ही लघु है भाषा और शैली की दृष्टि से भी दोनों में साम्य है। कुछ उपमाओं, लोकोक्तियों व श्लोकों के अर्थ भी एक समान हैं। दोनों काव्यों में शब्दावली एक जैसी है, उदाहरणार्थ 'नोत्कंठा कर्तुमर्हस' दोनों काव्यों में पाया जाता है। रामायण की कथा सुश्लिष्ट एवं सुसंबद्ध है। किंतु महाभारत की कथा इतनी सुश्लिष्ट एवं सुसंबद्ध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत में विभिन्न विषय एक साथ रख दिए गए हों। रामायण एक ही कवि की रचना है, जबकि महाभारत पर अनेक कवियों की छाप है। व्यास, वैशम्पायन व सौति उग्रश्रवा यह तीन तो मुख्य रूप से वक्ता हैं ही। इसीलिए रामायण की शैली में एकरूपता है और महाभारत की शैली में भिन्नता। रामायण की भाषा कलात्मक, परिष्कृत, अलंकृत है, जबकि महाभारत की भाषा प्रभावशाली एवं ओजयुक्त है।

रामायण में आर्यसभ्यता अपने विशुद्ध रूप में मिलती है, जबकि महाभारत के समय में म्लेच्छों का आगमन प्रारंभ हो गया था। लाक्षागृह बनाने वाला पुरोचन म्लेच्छ था। धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर की उत्पत्ति नियोगविधि द्वारा हुई थी। दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करता है और गुरुजन उसे रोक नहीं पाते। दोनों ग्रंथों को नैतिकता और वैवाहिक विचारों में काफी मतभेद है। धार्मिक विश्वास और नैतिक नियमों में भी दोनों ग्रंथों में पर्याप्त अंतर है।

● **ओम**

नाजायज रिश्ता

अगले हफ्ते डैडी घर आ रहे हैं। मैं आप दोनों की करतूतों के बारे में डैडी को जरूर बताऊंगी। घर को नर्क बनाकर रख दिया है। ज्योति ने अपनी मां और चाचा को धमकाते हुए कहा।

ज्योति 23 वर्षीया युवती थी। ज्योति के पिताजी निर्मल सिंह फौजी थे और मां नीलम देवी उपचारिका (नर्स) थीं। मनीष और आकाश दो छोटे भाई थे। दोनों दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई करते थे। फौज में सेवारत होने के कारण निर्मल सिंह अपने घर पर अपने परिवार के संग बहुत कम समय व्यतीत कर पाते थे। ज्योति के चाचा ने दो शादियां की थी। लेकिन शराबी एवं **व्यभिचारी** होने के कारण दोनों शादियां असफल रहीं। अपनी पत्नी के कहने पर निर्मल सिंह ने अपने भाई को अपने घर में शरण दे दे दी थी।

मां और चाचा को धमकाने के बाद ज्योति अपने कमरे में चली गई। दरअसल, आज फिर उसने अपनी मां और चाचा को संभोगरत अवस्था में देख लिया था।

अगले हफ्ते जब निर्मल सिंह घर आए तो व्यथित होते हुए ज्योति ने उन्हें अपनी मां और चाचा के प्रेम प्रसंग के बारे में सब कुछ बता दिया।

निर्मल सिंह ने जब ज्योति के परोक्ष में अपनी पत्नी और अपने भाई से इस संबंध में पूछताछ की तो उन लोगों ने उन्हें मोबाइल फोन में एक वीडियो क्लिप दिखाया। जिसमें ज्योति और उसका प्रेमी आलिंगनबद्ध होके एक-दूसरे को चूम रहे थे।

वीडियो क्लिप दिखाने के बाद नीलम देवी ने अपने पति से कहा- जब हम दोनों ने ज्योति को इस नाजायज रिश्ते से दूर रहने को कहा तो ज्योति ने हमारी बात मानने से **ढीठतापूर्वक** इंकार कर दिया और कहा कि वह अपने अंतर्जातीय प्रेमी से ही विवाह करेगी, क्योंकि वह दो महीने की गर्भवती है।

आपके सामने उसका भेद कहीं हम दोनों खोल ना दें, इस डर से उसने ऐसा घटिया आरोप हम दोनों पर लगा लिया।

अगले दिन ज्योति की हत्या के जुर्म में पुलिस ने निर्मल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अदालती कार्यवाही के पश्चात निर्मल सिंह को कारागार (जेल) भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि ज्योति गर्भवती नहीं थी।

- आलोक कौशिक

जन्मभूमि

जन्मभूमि श्रेष्ठ है कर्मभूमि से।
जन्मभूमि सर्वश्रेष्ठ है स्वर्ग से।।
मां के गर्भ में कदम ताल से।
जन्मभूमि का एहसास हुआ।।
जन्मभूमि पर कदम बढ़ाए।
जननी जन्मभूमि मुस्कुराए।।
जन्मभूमि श्रेष्ठ है कर्मभूमि से।
जन्मभूमि सर्वश्रेष्ठ है स्वर्ग से।।
कैसे भूल जाऊं जन्मभूमि।
जन्मभूमि पर पला बढ़ा।।
जन्मभूमि तुम्हें देखकर।
यादें सजी सपने साकार।।
जन्मभूमि श्रेष्ठ है कर्मभूमि से।
जन्मभूमि सर्वश्रेष्ठ है स्वर्ग से।।
जिंदगी की भागदौड़ में।
दौड़ लगाई कर्मभूमि में।।
कर्मभूमि से पहुंचे जन्मभूमि।
जननी जन्मभूमि मुस्कुराए।।
जन्मभूमि श्रेष्ठ है कर्मभूमि से।
जन्मभूमि सर्वश्रेष्ठ है स्वर्ग से।।
इंसान भरा स्वार्थ ईर्ष्या से।
अश्रु बहने लगे जन्मभूमि से।।
जब उड़ गए प्राण पखेरू।
तन मिल जाए जन्मभूमि में।।
जन्मभूमि श्रेष्ठ है कर्मभूमि से।
जन्मभूमि सर्वश्रेष्ठ है स्वर्ग से।।

- कुमार जितेन्द्र जीत

माँ

रमली को आज आने में देर हो गई। हरि दारू के नशे में अनाप-शनाप बक रहा था। बेटी बुधिया को दो-तीन तमाचे जड़ चुका था। वह कोने में सिसक रही थी। रमली के आते ही हरि बरस पड़ा - 'आ गई देवी जी, इतनी देर कैसे हुई आज? मालूम है ना आज बाजार है.. खाना कौन बनाएगा तेरा बाप...?' अचानक हुए हमले से रमली कांप उठी। कैसे कहती की सेठानी के यहां मेहमान आने से काम बढ़ गया। हरि को समझाते हुए कहती है- 'कभी-कभी काम ज्यादा बढ़ जाते हैं 'मछली कहां रखे हो' मैं खाना जल्दी बना रही हूं, आप थोड़ा आराम कीजिए...' साली मुझे पाठ पढ़ाएगी और गुस्से में रमली को डंडे से पीटने लगा। मां को पीटते देख बुधिया ने आकर हरि को धक्का देकर मां को बचा लिया। रोते-रोते कहती है- 'चलो हम कहीं भाग जाते हैं मां' बाबूजी आपको रोज पीटते हैं' मुझे पीटते हैं 'अब नहीं रहेंगे मां' चलो मां...' मां बेटी रोने लगी। रमली समझाते हुए कहती है - 'नहीं गुड़िया, हम कहीं नहीं जाएंगे। गरीब की औरत सबकी भौजाई होती है' मर्द कैसा भी रहे इज्जत तो सलामत रहती है। मत रोना बेटी सब ठीक हो जाएगा। रमली ने बुधिया को बाहों में भर लिया। मां के बाहों में बुधिया खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी।

- भानुप्रताप कुंजाम 'अंशु'

अनिश्चितकालीन लॉक

कोरोना के कारण खेल जगत पर छाई अनिश्चितता का तुरंत कोई हल दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि खेल प्रतियोगिताओं के भविष्य पर लगा यह ग्रहण गहराता जा रहा है। इसका असर ओलंपिक समेत कई बड़े खेल इवेंट पर पड़ा है। ज्यादातर खेल प्रतियोगिताएं, क्रिकेट सीरीज और फुटबॉल मैच या तो स्थगित कर दिए गए हैं या उन्हें रद्द किया जा चुका है। ओलंपिक अधिकारियों ने टोक्यो की सराहना अब तब के सबसे अच्छे मेजबान शहर के रूप में की थी लेकिन कोई भी कोरोना वायरस महामारी से निपटने की योजना नहीं बना सका, जिससे 2020 खेलों के अभूतपूर्व स्थगन के लिए मजबूर होना पड़ा। इस ओलंपिक का आयोजन अब 23 जुलाई 2021 से होगा। आयोजकों ने तैयारियों से सबका दिल जीता लेकिन वायरस के प्रकोप का खतरा पैदा होने से पहले कई बार इस पर **संकट के बादल छाए।** इस दौरान भ्रष्टाचार और बजट की गड़बड़ी के आरोपों का साया खेलों पर पड़ा।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। इस टी-20 टूर्नामेंट की शुरुआत इस साल 29 मार्च से होनी थी। लेकिन कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद इसे 15 अप्रैल तक टाल दिया गया। लेकिन अब लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ जाने के चलते बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि फिलहाल आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बोर्ड ने आईपीएल से जुड़े आठों फ्रेंचाइजीज को अपने फैसले की सूचना भेज दी है।

यह भी संभावना जताई जा रही है कि अब बोर्ड सितंबर-अक्टूबर में इसका आयोजन करने की सोच सकता है। लेकिन जानकारों के मुताबिक इस पर वैश्विक हालात को देखते हुए फैसला किया जाएगा। वैसे बीसीसीआई के मुखिया सौरव गांगुली इस संभावना को खारिज कर चुके हैं। उनका कहना था कि दुनिया की सभी टीमों का टुअर प्रोग्राम बना हुआ है और इसे बदला नहीं जा सकता। कोरोना वायरस के चलते कई खेल आयोजन स्थगित या रद्द हो चुके हैं। जुलाई में होने वाला टोक्यो ओलंपिक एक साल के लिए टल गया है। विंबलडन को इस साल रद्द कर दिया गया है जबकि मई में होने वाले फ्रेंच ओपन को फिलहाल टाल दिया गया है। कोविड-19 के प्रभाव के चलते बीसीसीआई ने ईरानी कप, सीनियर महिला वनडे नॉक-आउट, विज्जी ट्रॉफी, महिला वनडे चैलेंजर्स, महिला अंडर-19 नॉक आउट, महिला अंडर-10 टी-20 लीग, सुपर लीग और अन्य घरेलू टूर्नामेंट फिलहाल टाल दिए गए हैं। इसके अलावा महिला अंडर-19 टी-20 चैलेंजर ट्रॉफी, महिला अंडर 23 नॉक-आउट, महिला अंडर 23 वनडे चैलेंजर के सभी मैचों को अगली सूचना तक रोक दिया गया है।

● **आशीष नेमा**

'सर्वोत्तम तैयारी' से स्थगन तक

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने गत दिनों आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक से चर्चा कर इन खेलों को अगले साल तक टालने का फैसला कर लिया। सितंबर 2013 में टोक्यो को आईओसी ने ओलंपिक की मेजबानी सौंपी जिसके बाद जापान के हजारों लोग खुशी से झूम उठे। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने वादा किया कि टोक्यो सुरक्षित हाथों में है। 2015 में ओलंपिक के लिए सबसे महंगे स्टेडियम के कारण आलोचना झेलने के बाद आबे को राष्ट्रीय स्टेडियम के खाके को रद्द करना पड़ा जिससे उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, 'मैंने फैसला किया है कि हमें फिर से इसका खाका तैयार करना होगा। सितंबर 2015 में चोरी का आरोप लगने के बाद इसके प्रतीक चिन्ह को रद्द कर दिया गया। डिजाइनर ओलिवियर डेबी ने आरोप लगाया कि इसका लोगो बेल्जियम के थिएटर से चुराया गया है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जिसके बाद आयोजन समिति ने यह कहते हुए प्रतीक चिन्ह को वापस ले लिया कि जनता को इसका समर्थन हासिल नहीं है। 2018 में प्रतीक चिन्ह में हुई चूक के बाद स्कूली बच्चों द्वारा चुने गए ओलंपिक और पैरालिंपिक के ओलंपिक शुभंकर 'मिराटोवा' का सही तरीके से जारी होने से आयोजन समिति ने राहत की सांस ली। इसी साल एक अभूतपूर्व कदम के तहत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विभिन्न आरोपों के साथ खेलों में मुक्केबाजी प्रतियोगिता के संचालन का अधिकार एआईबीए से वापस ले लिया। बाद में हालांकि आईओसी ने खुद ही मुक्केबाजी टूर्नामेंट का आयोजन करने की बात कही।

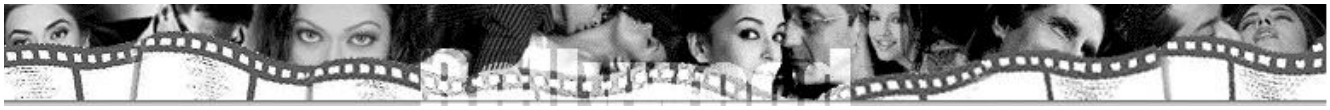

शोक में डूबा बॉलीवुड

ऋषि कपूर

जन्म: 4 सितंबर 1952
मृत्यु: 30 अप्रैल 2020

कैंसर से जूझ रहे ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में मुंबई में निधन

इरफान खान

जन्म: 7 जनवरी 1967
मृत्यु: 29 अप्रैल 2020

लंबे समय से कैंसर और आंतों के इन्फेक्शन से जूझ रहे थे इरफान

'बॉबी' से 'द बॉडी' तक का सफर

ऋषि कपूर नहीं रहे। वे 67 साल के थे। ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। 30 अप्रैल 2020 को मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। अपने 50 साल के फिल्म करियर में ऋषि ने तकरीबन 121 फिल्मों में काम किया।

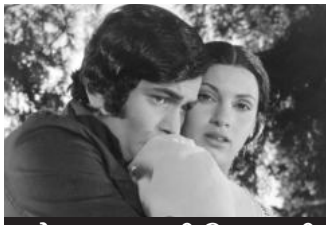

बतौर एक्टर पहली फिल्म बॉबी

उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर (1970) से डेब्यू किया था। फिल्म में अपने किरदार के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड मिला था। बतौर एक्टर उनकी फिल्म बॉबी (1973) थी जिसमें वह डिंपल कपाड़िया के साथ नजर आए थे। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर का बेस्ट एक्टर अवॉर्ड (1974) में मिला था। ऋषि कपूर की छवि एक रोमांटिक हीरो की थी। उन्हें दर्शकों ने रोमांटिक अंदाज में काफी पसंद भी किया। यही वजह है कि 1973 से 2000 के बीच ऋषि ने 92 रोमांटिक फिल्मों में काम किया जिनमें से 36 फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। इनमें कर्ज, दीवाना, चांदनी, सागर, अमर अकबर एंथनी, हम किसीसे कम नहीं, प्रेम रोग, हीना जैसी फिल्में शामिल हैं।

'द बॉडी' साबित हुई अंतिम फिल्म

इमरान हाशमी और शोभिता धुलिपाला स्टारर द बॉडी ऋषि कपूर की अंतिम फिल्म साबित हुई। यह फिल्म पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋषि ने एसपी जयराज रावल की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा 2019 में उनकी एक और फिल्म झूठा कहीं का भी रिलीज हुई थी। इसमें उन्होंने कुमार पांडे नाम के शख्स की भूमिका निभाई थी।

ऋषि कपूर को मिले अवॉर्ड

- 1970 – नेशनल फिल्म अवॉर्ड (चाइल्ड)
- 1974 – फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड
- 2008 – फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड
- 2009 – रूसी सरकार से विशेष सम्मान
- 2011 – फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर क्रिटिक अवॉर्ड
- 2016 – स्क्रीन लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड
- 2017 – फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवॉर्ड

...मैं आपके साथ हूं भी और नहीं भी

हैलो! भाईयों-बहनों, नमस्कार, मैं इरफान... **मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी...** ये आखिरी शब्द थे इरफान की आवाज में। जिसे उन्होंने अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के प्रमोशन के लिए रिकॉर्ड किया था। लेकिन उन्होंने अपने संदेश में कहा था- मेरा इंतजार करना। इस इंतजार का अंत इस तरह होगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान का निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर और आंतों के इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। हाल ही में उनकी मां का भी निधन हुआ था। लेकिन वे वहां जा नहीं पाए थे।

राजस्थान के रहने वाले इरफान एनएसडी के स्टूडेंट थे

इरफान के परिवार में पत्नी सुतापा देवेंद्र सिकदर और दो बेटे बाबिल और अयान हैं। इरफान खान टोंक के नवाबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उनका बचपन भी टोंक में ही गुजरा। उनके माता-पिता टोंक के ही रहने वाले थे। 7 जनवरी 1967 को जन्मे इरफान का पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान था। वे एक्टिंग में बाय चांस आ गए। वे क्रिकेटर बनना चाहते थे। लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वे फैमिली बिजनेस संभालें। हालांकि, इरफान को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने का मौका मिल गया और यहीं से उनका एक्टिंग करियर शुरू हुआ। छोटे पर्दे पर उनकी शुरुआत 'श्रीकांत' और 'भारत एक खोज' से हुई।

पहली फिल्म
'सलाम बॉम्बे'
मीरा नायर की सलाम बॉम्बे से फिल्मों में आए थे इरफान खान

आखिरी फिल्म
'अंग्रेजी मीडियम'
हाल ही में रिलीज हुई अंग्रेजी मीडियम उनकी आखिरी फिल्म

मकबूल, लंच बॉक्स, पीकू, पान सिंह तोमर ने उन्हें अलग पहचान दिलाई

1988 में आई मीरा नायर की फिल्म 'सलाम बॉम्बे' से इरफान ने शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो, द लंच बॉक्स, पीकू, तलवार और हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें हासिल (निगेटिव रोल), लाइफ इन अ मेट्रो (बेस्ट एक्टर), पान सिंह तोमर (बेस्ट एक्टर क्रिटिक) और हिंदी मीडियम (बेस्ट एक्टर) के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला।

एक लेखक की व्यथा कथा

देश में लॉकडाउन है और मैं भी तमाम देशवासियों की तरह घर में रहने को मजबूर हूं। हालांकि लॉकडाउन घोषित होते समय अंदर से बहुत खुश था कि विद्यालय बंद हो जाने से इस अवधि में लेखन के शौक के चलते कुछ लिखने-पढ़ने का सार्थक काम हो जाएगा और तदनुरूप योजना भी बना ली थी कि कम से कम तीन कहानी, चार-पांच लेख, एक दर्जन कवितएं और मन भर हाईकू तो रच ही डालूंगा। पेन, पैड, लैपटाप सब तैयार कर लिया था। अखबार कोरोना समाचार और चित्रों से भरे हैं। रेहड़ी, ठेला और पटरी पर दो जून की रोटी तलाशने वाले छोटे-मोटे व्यापारी-कामगार रोजगार बंद होने से पेट की आग में झुलस रहे हैं। कल-कारखानों से भगाए गए मजदूर डे-नाइट वॉकिंग करते हुए किसी तरह अपने गांव-घर पहुंचे तो प्रशासन ने उन्हें घरबदर कर स्कूलों में बने आइसोलेशन वार्ड में पटक दिया है। जहां दीवारों में अंकित सद्वाक्य 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेसु कदाचन' का अर्थ समझते उनका समय बीत रहा है। सोचा कि एक लेखक होने के नाते उनके दर्द को स्वर देना भी मेरा दायित्व है तो उन पर भी कुछ कालजयी लेखन कर डालूं। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। घर पर दो दिन तो आराम से कटे। समय से चाय नाश्ता, लंच-डिनर, रात को सोते समय केसर-शहद मिला दूध और साथ में एक चम्मच स्वर्णभस्म युक्त च्यवनप्राश भी। तो इतना सब खाने-पीने के बाद रचनाएं भी मक्खन की मानिंद दिमाग में उतराने लगी थीं। पर हाय रे मुआ कोरोना, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, काम का न काज का दुश्मन अनाज का जैसे मुहावरे अब वास्तविक अर्थ के साथ साक्षात थे। तीसरे दिन की सुबह से आज की सुबह है, मैं बस मुआ कोरोना को कोस रहा हूं। कोरोना मिल जाए तो बिना नमक, मिर्च-मसाले के कच्चा ही चबा जाऊं। आप पूछ रहे हैं हुआ क्या, अरे जनाब यह पूछिए कि क्या नहीं हुआ।

तीसरे दिन की मधुर प्रात, चिड़ियों के कलरव और मलय बयार के झोंकों का आनंद लेते हुए चादर ताने मैं एक प्रेम कथा का ड्राफ्ट मन ही मन बुन रहा था कि पत्नी का कारुणिक मंद्र स्वर गूंजा, 'मेरे बाबू, आज बदन दर्द हो रहा है, पांव भी भारी है, अपनी चाय बना लोगे क्या।' 'हां, ठीक है। पर फिर से पांव भारी। पिछले ही साल तो बेटी प्रतीक्षा जन्मी है। इतनी जल्दी, पर तुमने पहले कभी बताया नहीं। पर चलो ठीक है, अम्मा कब से पोते का मुंह देखने को तरस रही हैं।' मैं खुशी मिश्रित आश्चर्यचकित था। 'ऐसा वैसा कुछ नहीं है, लेखक महराज। बस, मन-तन बोझिल सा है।' मैं किचन में चाय बनाने लगा कि तभी एक आवाज कानों से टकराई, 'मेरे सोना, एक कप मेरे लिए भी बना देना। तुम्हारी

चाय में तो जादू होता है।' मैंने बाअदब उन्हें बिस्तर पर ही चाय और एक गिलास पानी देकर पूछा, 'कोई और आज्ञा है महारानी।' 'क्या हर समय मजाक करते रहते हो। किसी के दुख-दर्द से तुम्हें तो कोई मतलब ही नहीं। अब देखो न, कितना काम बिखरा पड़ा है। काम वाली बाई भी नहीं आ रही है।' 'हां, तुम सही कह रही हो, एक ही चेहरा देख-देख कर मैं भी बोर गया हूं।' मैंने दबे स्वर में मन की भड़ास निकाली। पर उसके कान तो चमगादड़ की तरह लो फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंगें भी पकड़ लेते हैं। वह सिंहनी सी दहाड़ी, मैं शुरू से ही तुम्हारे चाल-चरित्र जानती थी। मति मारी गई थी मेरी, भाग फूट गए थे जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर घर से भागकर तुमसे शादी की थी। पड़ोसी मिस्टर वर्मा कैसे अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहते हैं। कुछ सीखो उनसे।' 'मिसेज वर्मा के साथ तो मैं भी खुशी-खुशी रह लूंगा।' यह कहते हुए मैं कमरे बाहर निकलने वाला ही था कि पत्नी का कोमल स्वर हवा में तैरा, 'कमर में मरहम लगा दो न, दर्द से उठा नहीं जा रहा।' मरहम लगाकर एवं दैनिक जरूरी कामों से निबट कर मैं मेज पर बैठ गया हूं। चाय की तलब लगने लगी है, हालांकि अभी तक मेरी चाय का कप और पकोड़े की प्लेट नहीं आई है और न ही किचन से ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं। कई बार पत्नी की ओर मांगने के लिए संकेत करने का साहस बटोरा है पर उनकी मुख मुद्रा देखकर कछुए की भांति अपनी भावना को मन के अंदर समेट कर व्हाट्सएप पर मिसेज वर्मा द्वारा भेजे पनीर के पकोड़े खाते हुए चाय पी रहा हूं। इसी बीच पत्नी ने दूध का डिब्बा मेज पर जोर से रखते हुए दशानन के से कोमल मधुर स्वर में बोलीं कि पड़ोस की डेरी से दूध ले आऊं। हालांकि बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है और बाहर निकलने वालों के डंडे खाने और मुर्गा बनने के कई फोटो और वीडियो देखकर मेरे कदम घर की लक्ष्मण रेखा को पार करने का दुस्साहस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मामा मरीच का अनुसरण कर डेरी की ओर बढ़ चला हूं। सौभाग्य से आज रास्ता खाली है और मैं सकुशल दूध लेकर घर में घुसा ही हूं की पत्नी की मधुर मुस्कान भरी मनुहार सुनकर विस्मित हुआ, 'हाथ-मुंह धोकर बैठो। मैं नीम और सहजन के फूलों के पकोड़े और कॉफी लेकर आती हूं। अपने को तीन-चार बार चुटकी से काटा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। और तभी झाड़ू-बाल्टी और पोंछा के साथ प्रकट होकर वह बोलीं कि नाश्ता आने तक कमरे और आंगन की मैं साफ-सफाई और पोंछा कर डालूं। मैं गमछे को सिर पर बांधकर झाड़ू लगाने में जुट गया हूं। कोना-कोना, सोफा-दीवान के नीचे सभी जगह से जाले-धूल साफ करने के निर्देश लगातार आकाशवाणी के संगीत की तरह गूंज रहे हैं। मैं बाबा झामदेव का गोनायल डालकर पोंछा लगा रहा हूं। किचन से आती हुई खुशबू और काफी की महक से मेरे काम में गति आ गई है और चेहरे पर खुशी की चमक। लेकिन यह खुशी पल भर बाद ही गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गई। मैं देख रहा हूं कि बाथरूम में चादरें, तकियों के कवर और कपड़े रखे जा रहे हैं। पकौड़े सामने आ गए हैं और मैं भूखे कुत्ते की तरह पकौड़ों पर टूट पड़ा हूं। नाश्ते के बाद बाथरूम में पड़े कपड़े धुल कर छत पर पहुंचा ही हूं कि तभी, 'चांद नहीं निकला वहां। अब छत पर ही टहलते रहोगे कि नीचे भी आओगे।' मैं तार पर कपड़े फैलाते हुए आसपास की छतों की ओर चांद निहारने की असफल कोशिश कर रहा हूं पर सभी छतों में तपते सूरज किसी न किसी काम में लगे हैं। नीचे उतर आंगन में बैठा ही हूं कि सामने थाली में चावल बीनने के लिए रखे हुए हैं और दाल की सीटी बज रही है। पूजा घर से घंटी के साथ मिली ध्वनि का एक टुकड़ा मेरे कानों से टकराया कि दाल का कूकर उतारकर चावल चढ़ा दूं और पूजा होने के पहले भरवां करेला बना लूं। पूजा हो गई है और प्रसाद के लिए दाल, चावल, पापड़, अचार, चार फुलके, दही का खीरा वाला रायता और खीर सजा थाल रख आया हूं। अब वह शाम की चाय और रात के खाने का मीनू बताकर आराम करने ख्वाबगाह तशरीफ ले जा रही हैं। और इधर मेरी कमर दर्द से कमान हुई जा रही है, वह दर्द जो एक स्त्री हर दिन जीती है।

● **प्रमोद दीक्षित 'मलय'**

वाटर हार्वेस्टिंग कराएं, जल सकंट से मुक्ति पाएं

बादल अमृत-सा जल लाता
अपने घर आंगन बरसाता
आओ करें इसका संग्रहण
बह ने जाए अमृत कलश
नदी नहर नल झील सरोवर
वापी कूप कुंड नद निर्झर
सर्वोत्तम सौन्दर्य प्रकृति का
कल-कल ध्वनि संगीत मनोहर
जल से अन्न पत्र फल पुष्पित सुन्दर उपवन है ।
जल पीकर जीते सब प्राणी जल ही जीवन है ।।

सौजन्य से : राष्ट्रीय पाक्षिक अक्स

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए

In Pursuit of Truth

पाक्षिक अक्स

www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल
फोन:0755-4017788,2575777

D-17008